

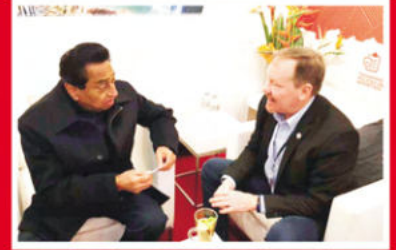
• मप्र कांग्रेस: फुल टाइम अध्यक्ष कब? • बुदेलखंड पैकेज: भ्रष्टाचार की जांच शुरु

In Pursuit of Truth

आक्ष

पाक्षिक

www.akshnews.com



आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार

वर्ष 18, अंक-9

1 से 15 फरवरी 2020

मूल्य 25 रुपये

R.N.I NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/2015-17



भगवा
पर हावी

भक्ति



युवाओं के लिये बेहतर कल का निर्माण

मध्यप्रदेश सरकार ने युवाओं को रोज़गार तथा स्वरोज़गार के अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाने के लिये अनेक रणनीतिक कदम उठाये हैं।

- मध्यप्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को देना अनिवार्य।
- प्रदेश के आईटीआई, पॉलीटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी कैंपस, भोपाल में प्रिंसीजन इंजीनियरिंग कोर्स में प्रशिक्षण की सुविधा।
- ड्यूल सिस्टम ऑफ़ ट्रेनिंग योजना के अंतर्गत 91 यूनिट में 1,884 सीटों पर प्रवेश के लिये इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ एमओयू।
- 97 कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में 2059 आईटीआई प्रशिक्षार्थियों का चयन।
- राष्ट्रीय शिशुता प्रोत्साहन योजना के तहत अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर 4,996 प्रतिष्ठान तथा 1,05,755 शि्षुओं का रजिस्ट्रेशन। अब तक 6,675 प्रशिक्षार्थियों का नियोजन।
- मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में 14 जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने के लिए प्रशिक्षणदाताओं का चयन। प्रतिवर्ष प्रति केंद्र से 3000-5000 प्रशिक्षार्थियों को केपिटल इंटेसिव पाठ्यक्रम में आवासीय प्रशिक्षण।



- शहरी बेरोज़गार युवाओं को 100 दिन के रोज़गार के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण की मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ। अब तक 29,802 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण।
- प्रतिभावान खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि एवं खेल संघों को अनुदान राशि में कई गुना वृद्धि।
- खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम।
- खेल अकादमी एवं प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को चिकित्सा और दुर्घटना जीवन बीमा की सुविधा।

उम्मीदें रंग लाईं,

तरक्की मुस्कुराई

मप्र कांग्रेस

9 | सियासी संतुलन

मप्र कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि यहां जितने दिग्गज नेता हैं पार्टी उतने धड़े में बंटी हुई है। बात भी सही है। लेकिन वर्तमान समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ गुट सबसे अधिक चर्चा में हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कमलनाथ...

राजपथ

10-11 | फुल टाइम अध्यक्ष कब?

मप्र कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और उसे कब नियुक्त किया जाएगा इस पर लगातार बहस चल रही है। अभी हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि नए पीसीसी अध्यक्ष का ऐलान 15 दिन...

विवाद

13 | मिलावट का घालमेल

एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी की तर्ज पर मप्र में मिलावट का घालमेल चल रहा है। मिलावट पर नकेल कसने के लिए एक ओर कमलनाथ सरकार हर तरह के माफिया और खासकर मिलावटी माफिया को जड़ से मिटाने...

विडंबना

17 | यह कैसी नीति?

मप्र में सबसे अधिक महिला अपराध होता है। इसके लिए शराब को सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में शराब की नई दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध लगा रखा था।



अपनी 'भगवा' राजनीति से विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी भाजपा मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ की 'भक्ति' से टेंशन में नजर आ रही है। दरअसल, दिखावे से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 13 माह के कार्यकाल में धर्म और संस्कृति के विकास, विस्तार और संवर्द्धन की दिशा में जो कदम उठाए हैं वे जन मानस पर छा गए हैं। इस कारण जनता में कमलनाथ और उनकी सरकार की बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है।



दिल्ली दरबार

29 | त्रिकोणीय मुकाबला

दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बार भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव त्रिकोणीय होने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा।

राजनीति

30-31 | सबक लेने का वक्त

राजनीति में कोई भी हार या जीत आखिरी नहीं होती। चूँकि भाजपा विचार के स्तर पर अलहदा ढंग की पार्टी है, इसलिए उससे उम्मीदें कुछ ज्यादा ही की जाती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड की हार के बाद वह ठंडे मन से मुद्दों पर सोचेगी, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा बढ़ाएगी...

सियासत

32-33 | कागज नहीं दिखाएंगे

शासन-प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने का नारा देकर सत्ता में आई मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक चंदा लेने की जो प्रक्रिया शुरू की है वह किसी भ्रष्टाचार से कम नहीं है। आलम यह है कि पार्टियां मिलने वाले चंदे से मालामाल तो हो रही हैं लेकिन जब चंदा देने वाले...

6-7 | अंदर की बात

35 | छत्तीसगढ़

36 | महाराष्ट्र

37 | राजस्थान

38 | उत्तरप्रदेश

39 | बिहार

46 | त्पंग



बरसों रहे हैं आप हमारी निगाह में...

नूर नाहवी का एक शेर है...

**बरसों रहे हैं आप हमारी निगाह में
ये क्या कहा कि हम तुम्हें पहचानते नहीं**

नौकरशाही के प्रति कुछ ऐसी ही अंदाज है मध्य प्रदेश में लगातार 15 साल शासन करने वाली भाजपा के नेताओं का। भाजपा के शासनकाल के दौरान जिन नौकरशाहों के दम पर सुशासन के बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे, आज वही नौकरशाह भाजपा नेताओं की आंख का कांटा बन गए हैं। बात-बात पर कभी पूर्व मुख्यमंत्री तो कभी वर्तमान नेता प्रतिपक्ष नौकरशाही को खरी-खोटी सुनाने से चूकते नहीं हैं। आलम यह है कि वर्तमान सरकार के साथ समन्वय बनाकर अफसर जिस तरह काम कर रहे हैं वह शायद भाजपा नेताओं को भा नहीं रहा है। यही कारण है कि कोई भाजपाई नौकरशाहों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो कोई उन्हें देवपुरुष कहता है। वहीं कोई इन्हें वैश्या की संज्ञा दे देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो अफसर 15 साल तक भाजपा सरकार की आंख-कान थे, आज वे उन्हें चुभन क्यों दे रहे हैं? हैरानी की बात तो यह है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को ये अफसर सबसे अधिक खटक रहे हैं। पिछले एक साल में ऐसा क्या हो गया कि भाजपा शासनकाल में यही नौकरशाह सरकार की रीढ़ बने थे, वे अब खलनायक बन गए हैं। भाजपा नेताओं के बोल सुनकर तो यही लगता है कि उनके शासनकाल में नौकरशाहों ने शायद उनकी एक नहीं सुनी इसलिए वे अब कांग्रेस शासनकाल में उन पर टारगेट कर रहे हैं। यह तथ्य सभी जानते हैं कि अफसरशाही हमेशा सरकार की नीति और रीति के अनुसार काम करती है। भाजपा ने अपने शासनकाल में इन अफसरों से अपनी नीति और रीति के अनुसार काम करवाया। अब कांग्रेस करवा रही है। लेकिन ऐसा लगता है भाजपा नेता इस बात को 15 साल शासन करने के बाद भी नहीं समझ पाए हैं। नहीं तो प्रदेश में बड़े अवैधानिक पद पर आसीन नेता प्रतिपक्ष यह नहीं कहते कि - **अधिकारी तो वैश्या की तरह कपड़े बदलते हैं**, सरकार बदलते ही चोला बदल लेते हैं। निजाम बदलते वक्त नहीं लगता, अधिकारियों को यह बात समझना होगी कि सरकार बदलते ही उनकी क्या दुर्गति होगी। यही नहीं उन्होंने यहां तक कह डाला कि सत्ता में लौटे तो अफसरों को नौकरी लायक नहीं छोड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष का यह बयान यह दर्शाता है कि सत्ता जाने के बाद भाजपाई किस तरह बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट में वे कभी सरकार गिराने तो कभी अफसरों को सबक सिखाने का दावा करने लगते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष सबसे आगे हैं। हद तो यह कि ब्यावसाय में प्रशासन की सख्ती पर वे इस कदर बौखलाए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा है कि **'एलीट वर्ग'** की नजर में सभी राजनीतिक व्यक्ति डाकू हैं और वह स्वयं में **'देव पुरुष'** हैं। यही देवपुरुष जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर अप्सराओं के साथ मधुपान करते हैं और फिर ट्रैप में फंसेते हैं। तब जाकर एक वीडियो के बदले एक करोड़ रुपए तक देते हैं। यह पैसा कहां से आता है। ऐसे लगभग **8 देवपुरुषों के वीडियो** मेरे एक परिचित के पास हैं। मैं चाहता तो खुलासा करता लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि यह गंदगी फैले और मेरा मध्यप्रदेश पूरे देश और दुनिया में कुकर्म प्रदेश के रूप में जाना जाए। इस कारण मैं अभी तक चुप रहा। सवाल यह उठता है कि माननीय जिस हनीट्रैप की बात कह रहे हैं वह तो उनके ही शासनकाल में हुआ था। जो महिलाएं और पुरुष हनीट्रैप में शामिल हैं वे उनके ही शासनकाल में पले-बढ़े हैं। उस समय वे कैसी तंद्रा में थे कि इतना बड़ा घटनाक्रम होता रहा और उन्हें जानकारी नहीं मिली। इसलिए माननीय को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपनों के दामन में झांकने की जरूरत है।

-राजेन्द्र आगाल

प्राशिक्षक
अक्षर

वर्ष 18, अंक 9, 1 से 15 फरवरी, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जौन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो

मुंबई :- ऋतुन्द्र माथुर, कोलकाता:- इंद्रकुमार,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, छत्तीसगढ़:- संजय

शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह,

लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथुरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत

098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

देशीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इन्डेलव मायापुरी-

फोन : 011 25495021, 011 25494676

मुंबई : बी-1, 41 शिव पार्वती चेंबर प्लॉट नंबर 106-110 सेक्टर-21

नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411

कोलकाता : 70/2 हजर रोड कोलकाता

फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)

फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,

मोबाइल 094241 08015

इंदौर : 39 बुद्धि सिल्टर निगानिया, इंदौर

मोबाइल - 094251 25096

स्वाधिकाारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जौन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



प्रत्यक्ष प्रणाली से हो चुनाव

जब भी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुए हैं, अप्रतिष्ठा-फरोख्त बढ़ी है। इस तरीके से प्रजातंत्र की हत्या होती है। सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव कराए। जनता को ही तय करने दिया जाए कि उसका महापौर और नगर निगम अध्यक्ष कौन होगा।

● राहुल सेन, इंदौर (म.प्र.)

मोदी का जादू कम हुआ

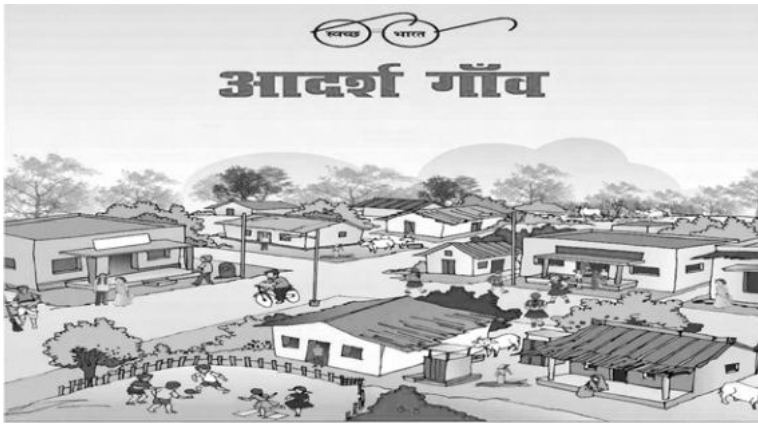
2019 के चुनाव के बाद से जिस तरह के कानून मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं। उनसे जनता को काफी दुख पहुंचा है। सीएए और एनआरसी जैसे कानून को लाकर सरकार हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है। देश को बांट रही है। केंद्र सरकार लोगों को भड़का रही है।

● राजू तिवारी, भोपाल (म.प्र.)

कुछ तो करे सरकार

राजस्थान में जिस तरह नवजात शिशुओं की मौतें हो रही हैं उसके लिए कांग्रेस की सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री को गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यहां की जनता उन्हें चुनकर अत्ता में लाई है। ताकि वे जनता का ध्यान रखें।

● पवन कुमार, जयपुर (राजस्थान)



प्रधानमंत्री की कोशिश नाकाम रही

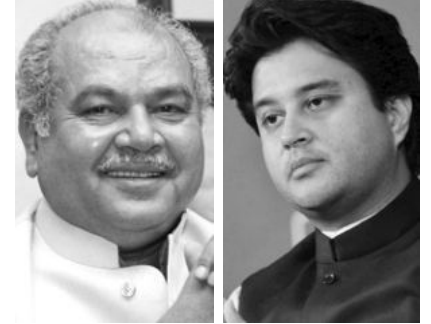
प्रदेश में आदर्श ग्राम योजना में सांसदों को कोई दिलचस्पी नहीं रही। वहीं दूसरी ओर सांसदों द्वारा अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी भी एक गांव को गोद लेने की संख्या तेजी से घटी है। और तो और जिन सांसदों ने गांवों को गोद लिया भी था उनमें भी कोई विकास नहीं दिखा। योजना के तहत विकास कार्य पूरा करने के लिए कई तरह से फंड मिलते हैं। लेकिन सांसद इन 6 सालों में गांवों के प्रति फिक्रमंद नहीं दिखे। प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी संभावनाओं के साथ इस योजना को लागू किया था। ताकि गांवों का विकास हो सके। लेकिन लगता है सांसदों को गोद लिए गांवों की कोई चिंता ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की कोशिश नाकाम रही है।

● छवि शर्मा, बरंडवा (म.प्र.)

दिल्ली में फिर केजरीवाल आएंगे

बीते पांच सालों में केजरीवाल की सरकार ने लोगों के लिए कई अच्छे काम किए हैं। बिजली, पानी मुफ्त देकर दिल्ली सरकार ने यहां के लोगों को राहत दी है। वहीं महिलाओं के लिए उन्होंने मेट्रो में मुफ्त सफर कराकर उनका दिल जीत ही लिया है। हजारों लोगों का मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। मानते हैं कि दिल्ली सरकार में कई विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं कराया, लेकिन उसका दोष अकेले अरविंद केजरीवाल को देना नासमझी है। दिल्ली में फिर केजरीवाल को आना चाहिए।

● राकेश बिह, नई दिल्ली



भाजपा अब कहीं नहीं

प्रदेश में भाजपा का जो बचा हुआ रूतबा था वो भी कम होता जा रहा है। कमलनाथ सरकार द्वारा किए जा रहे कामों से जनता खुश है। झाबुआ उपचुनाव में भी जनता ने दिखा दिया कि कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही है। अब जौरा में होने वाले उपचुनाव में भी जनता कांग्रेस को ही चुनेगी। भाजपा नेताओं की भाषणबाजी और उनकी अधूरी योजनाओं के कारण ही जनता ने कांग्रेस को चुना है। भाजपा के दिन अब खत्म हो गए हैं।

● रानी सोनी, मुबैना (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



मंझधार में नैया

बसपा सुप्रीमो मायावती हताशा से उबर नहीं पा रही हैं। गत दिनों देश के सबसे बड़े सूबे की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकीं दलित नेता का जन्मदिन मनाया गया। इस बार गौर करने वाला पहलू यह था कि समर्थकों ने उन्हें फिर सूबे का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया। जबकि अतीत में उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने के दावे होते थे। लंबे अरसे बाद मायावती को ऐसे दौर से गुजरना पड़ रहा है जब वे किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। लोकसभा में 2014 में तो उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। इस बार गनीमत रही कि समाजवादी पार्टी से तालमेल कर चुनाव लड़ा तो दस सीटें मिल गईं। पर राज्यसभा में तो संख्या लगातार घट रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी अब गिनती के सदस्य हैं। पर हार से सबक लेकर कोई प्रभावी रणनीति अपनाने को तैयार नहीं। कभी बहुजन तो कभी सर्वजन के सहारे सत्ता के शिखर पर पहुंचने में सफल रहीं। पर मोदी और भाजपा के उभार ने उन्हें महज दलित वोट बैंक तक ही सीमित कर दिया। लोकसभा में पिछले सात महीने में पांच बार नेता बदल चुकी हैं। तय नहीं कर पा रहीं कि किन वर्गों को जोड़कर आगे बढ़ें। असमंजस में फंसी बहनजी के कारण उनकी पार्टी की नैया मंझधार में है। अब देखना यह है कि वह पार कैसे लगती है।

आखिर हकीकत क्या है?

वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को उन्होंने अमित शाह के कहने पर जनता दल (यू) में शामिल किया था। तब उनके बयान पर लोगों की ज्यादा तवज्जो नहीं गई थी क्योंकि जब प्रशांत किशोर ने भाजपा विरोध का झंडा नहीं उठाया था। अब वे खुलकर भाजपा के विरोध में बोल रहे हैं और उन्होंने नागरिकता कानून पर केंद्र सरकार के विरोध में मोर्चा खोला है। दूसरे, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तभी नीतीश कुमार का यह कहा बहुत अहम है कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल किया था। अब सवाल है कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को सिर्फ पार्टी में शामिल किया था या उनको उपाध्यक्ष भी शाह के कहने पर ही बनाया था? ध्यान रहे नीतीश ने प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाते हुए कहा था कि वे पार्टी का भविष्य हैं। तो क्या नीतीश ने अपनी पार्टी का भविष्य अमित शाह के या उनके चुने हुए आदमी के हाथ में सौंपने का फैसला किया था? प्रशांत किशोर ने जवाब में दो बातें कहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने ही रंग में रंगने का गिरा हुआ प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात कही कि लोग कैसे यकीन करेंगे कि नीतीश कुमार आगे अमित शाह के भेजे आदमी के हिसाब से काम नहीं करेंगे।



तालमेल की चुनौती

बंसीधर भगत उत्तराखंड में भाजपा के नए सूबेदार बने हैं। अभी तक अजय भट्ट यह जिम्मा संभाले थे। भट्ट की तरह ही भगत भी ब्राह्मण हैं। उत्तराखंड में भाजपा शुरू से ही राजपूत-ब्राह्मण समन्वय की राजनीति करती रही है। मुख्यमंत्री या विधायक दल का नेता राजपूत हो तो पार्टी की कमान ब्राह्मण के हाथ देने की नीति। चूंकि मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजपूत हैं सो पार्टी की कमान तो किसी ब्राह्मण को ही मिलनी थी। कांग्रेस ने अलबत्ता दलित तबके को भी कई बार कमान सौंपी। माना जा रहा है कि भगत को सूबेदारी दिलाने में केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की अहम भूमिका रही है। जिनका मुख्यमंत्री से छत्तीस का आंकड़ा माना जाता है। दरअसल निशंक खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं और इस कुर्सी पर उनकी निगाह आज भी टिकी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोशिश नैनीताल की लालकुआं सीट के विधायक नवीन दुमका को पार्टी अध्यक्ष बनवाने की थी। वहीं भाजपा का एक खेमा सांसद अजय भट्ट को ही दूसरी बार पार्टी की कमान सौंपना चाहता था। पर संघ परिवार के हस्तक्षेप ने भगत को अहमियत दिलाई। उनका चयन आम राय से हुआ है। पर भगत के लिए पार्टी को आगे बढ़ाने से भी पहले अपने मुख्यमंत्री के साथ सही तालमेल बिटाने की चुनौती होगी।

आस निराश

अशोक गहलोट ज्यादा ही निष्ठुरता दिखा रहे हैं। मलाईदार पदों को बांटने को तैयार ही नहीं। जबकि सरकार बने सवा साल पूरा होने को आ गया। अपनी पार्टी का राज हो तो भला पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सत्ता सुख भोगने के अरमान क्यों न संजोएं। ये अरमान तो वे भी संजोए बैठे हैं जो कम से कम विधानसभा के सदस्य तो हैं। मंत्री पद नहीं मिला तो किसी निगम की चेयरमैन ही सही। निर्दलीय और बसपा से पार्टी में समाहित हुए विधायकों की बेचैनी भी तो बढ़ी है। उन्हें सरकार बनवाने और चलवाने का पुरस्कार चाहिए। ऐसे में गहलोट के लिए भी तो फैसला आसान नहीं। मंत्री तो 29 से ज्यादा हो नहीं सकते। मजबूरी में इन तेरह विधायकों को ही लालबत्ती वाले ओहदे देने पड़ गए तो क्या करेंगे? अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को तो सब्र ही रखना पड़ेगा। निगम, बोर्ड और आयोग की कुर्सियां बांटने से पहले तो जिलास्तर की समितियों में भी खपा सकते हैं काफी लोगों को। चर्चा तो यही है कि इन समितियों में मनोनीत किए जाने वालों की सूची तैयार है।

राजनीति मुगालतों की

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हों या आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हों या तेलंगाना में के.चंद्रशेखर राव हों सबको मौजूदा राजनीति की हकीकत को समझना होगा। सब अपने-अपने खोल में दुबके हैं। तीनों नेता मुख्यमंत्री हैं और इस सोच में हैं कि राजनीति उनके नियंत्रण में है। पर ऐसा है नहीं। तीनों ही राज्यों में भाजपा जिस तरह की राजनीति कर रही है वह अंततः इन प्रादेशिक क्षेत्रों की राजनीति को नुकसान पहुंचा सकती है। तेलंगाना में भाजपा की राजनीति ऑल इंडिया एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की वजह से फल-फूल रही है। केंद्र सरकार के लागू किए नागरिकता कानून के विरोध की कमान ओवैसी और उनकी पार्टी ने संभाली है। ध्यान रहे पिछले साढ़े पांच साल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राष्ट्रीय परिदृश्य पर मजबूत होते जाने का एक अनिवार्य नतीजा यह हुआ है कि मुस्लिम अपना खुद का नेता खोज रहा है और ओवैसी में उसको अपना नेता दिख रहा है। इससे भाजपा मजबूत होती जा रही है।

यह कैसी स्मार्टनेस...?

देश के कुछ सौभाग्यशाली शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में ढलने का मौका मिला है। इसके लिए मद्र के आधा दर्जन से अधिक शहरों में काम चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मद्र की राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी बनने की दौड़ में आगे चल रही है। लेकिन उसकी राह में कई तरह के रोड़े आ रहे हैं। सबसे बड़ा रोड़ा तो यह है कि अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी योजना को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। हद यह है कि भोपाल में इस योजना की देखरेख करने वाले बड़े साहब तो चिंदी चोरी में लग गए हैं। उनकी चिंदी चोरी की चर्चा प्रशासनिक वीथिका में ठाहके के साथ हो रही है। दरअसल, भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी संभालने वाले साहब ने अपनी पदस्थापना के बाद यहां अपने आने-जाने के लिए खुद की गाड़ी अटैच करवा दी है। यही नहीं साहब ने गाड़ी का खर्चा निकालने के लिए ट्रेवल्स कंपनी के नाम पर बिल फड़वाना शुरू कर दिया। हांग लगे न फिटकरी और रंग चोखा की तर्ज पर साहब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। साहब ने तो यह सब चोरी-छिपे किया है, लेकिन यह बात अब सार्वजनिक हो गई है। लोग तो यह कहने लगे हैं कि ये भोपाल को क्या खाक स्मार्ट बनाएंगे। जब वे खुद स्मार्ट नहीं बन पाए हैं। सूत्र बताते हैं कि साहब को भी इस बात की खबर लग गई है कि उनकी चिंदी चोरी की चर्चा अब उन पर भारी पड़ सकती है।

जितने अफसर गए उतने उद्योग भी नहीं लाए

कर्ज में डूबी सरकार हर कदम पर मितव्ययता कर रही है। सरकार की कोशिश है कि वह एक पाई भी ऐसी जगह खर्च न करे, जहां से उसे आय होने की संभावना न हो। इसका असर यह हो रहा है कि प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में अफसरशाही सरकार के हर कदम पर मंथन कर हानि-लाभ का गुणा-भाग करती नजर आ रही है। इन दिनों अफसरों की जुबान पर दावोस यात्रा चढ़ी हुई है। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश आमंत्रित करने के लिए अफसरों का एक दल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां होने वाली वर्ल्ड इकनॉमी फोरम की सालाना बैठक में गया था। दल ने देशी-विदेशी निवेशकों को लुभाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन सूत्र बताते हैं कि देश के दो बड़े औद्योगिक घरानों ने मद्र में किसी भी तरह का निवेश करने से मना कर दिया। इसके पीछे उन्होंने वजह बताते हुए यह कहा कि जब तक केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक हम मद्र में निवेश नहीं कर सकते। दरअसल, केंद्र में भाजपा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण औद्योगिक घराने कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं। यहां बता दें कि जिन औद्योगिक घरानों ने मद्र में निवेश के लिए इनकार किया, वे कांग्रेस के करीबी माने जाते हैं। इस घटना पर प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी यह कहते हुए चुटकी लेते हैं कि काश जितने अफसर वर्ल्ड इकनॉमी फोरम की बैठक में गए थे, उतने उद्योग भी नहीं ला सके। फिर ऐसी यात्रा क्यों?



नो प्रॉफिट में प्रॉफिट

जरूरतमंदों को आवास मुहैया कराने वाली सरकारी निर्माण एजेंसी भले ही नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर काम करती है, लेकिन इस एजेंसी में पदस्थ अफसर प्रॉफिट कमाने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। आलम यह है कि अफसरों की कारस्तानी की वजह से यह सरकारी निर्माण एजेंसी भले ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, लेकिन उसे जमकर लॉस हो रहा है। लेकिन अफसरों को इसकी चिंता नहीं है। खासकर इस एजेंसी में अपने आपको नंबर-1, नंबर-2, नंबर-3 मानने वाले तीन अफसरों में तो कमाई की ऐसी होड़ लगी है कि वे लॉस में भी प्रॉफिट पा लेते हैं। हालांकि इस एजेंसी में पदस्थ सबसे बड़े साहब हैं तो बड़े ईमानदार लेकिन वे अपने से कनिष्ठ उन तीन अफसरों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं जो नो प्रॉफिट में भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि तीनों अफसरों का एक ही सूत्र है कि उनका खजाना भरता रहना चाहिए, इसके लिए चाहे सप्लायर और ठेकेदार की जो दुर्गति हो जाए। उनके इस सूत्र का असर यह हो रहा है कि सप्लायर कमीशन बांट-बांट कर परेशान हो उठे हैं। स्थिति यह है कि अफसरों की कारस्तानी के कारण सरकारी निर्माण एजेंसी द्वारा बनाए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। इससे निर्माण एजेंसी की साख दिन पर दिन गिरती जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस निर्माण एजेंसी को घटिया निर्माणों के कारण कई बार मुंह की खानी पड़ी है। फिर भी अफसर कमीशनखोरी में डूबे हुए हैं।

नोट कमाने में व्यस्त

प्रदेश में खेती-किसानी वाले विभाग में इन दिनों दो लोग जमकर चांदी काट रहे हैं। आलम यह है कि विभागीय मंत्री सरकार तथा अपनी साख मजबूत करने के लिए रात-दिन एक किए हुए हैं। वहीं उनके स्टाफ में शामिल ये दोनों जनाब नोट कमाने में व्यस्त हैं। मंत्रीजी को इसकी जानकारी है या नहीं, यह तो वही जानें, लेकिन उनके दोनों अफसरों की कारस्तानी प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा में है। इनमें से एक जनाब रिटायर्ड हैं, जो विशेष सहायक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी मंत्रीजी के पिताश्री के समय टेलीफोन ऑपरेटर थे और निज सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दोनों साहेबान ने अपनी-अपनी कमाई के लिए विभागों का बंटवारा कर लिया है। एक साहब हॉर्टिकल्चर व अन्य जगह से कमाई कर रहे हैं, तो दूसरे मंडी की दलाली कर रहे हैं। इन दोनों की नोट कमाने की ललक से मंत्रीजी की साख दांव पर लगी हुई है।

कमिश्नर प्रणाली क्यों नहीं?

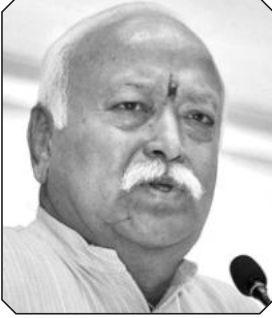
उत्तरप्रदेश के दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद मद्र में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि कम से कम भोपाल और इंदौर में तो इसे लागू किया जा सकता है। वैसे यह चर्चा एक दशक से चल रही है। जब भी यह चर्चा शुरू होती है तो यह कहा जाता है कि इसकी जरूरत क्या है? इसके लिए तर्क दिया जाता है कि अगर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई तो पुलिस महकमा निरंकुश हो जाएगा। लेकिन प्रदेश में कई ऐसे अवसर आए हैं जब पूरी प्रशासनिक मशीनरी पुलिस के हाथ में रही है। साल में कम से कम तीन दिन तो यही देखने को मिलता है। वे तीन दिन वह होते हैं जब राजधानी में आईएस सर्विस मीट आयोजित होती है। इन तीन दिनों तक पूरे प्रदेश के कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य आईएस अधिकारी अपना काम छोड़कर राजधानी में डेरा डाले रहते हैं। इस दौरान जिलों में आईजी, डीआईजी, एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाले रहते हैं। यही नहीं पिछले कई सालों से यह देखा जा रहा है कि इस दौरान प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना नहीं होती है। ऐसे में प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू क्यों नहीं की जा रही है।

अक्स का आईना



शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन मजबूत है। हम लोग राज्य के विकास के लिए एक साथ आए हैं। हम लोगों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं। यही तो लोकतंत्र है। इतिहास में न जाकर हम लोगों को मौजूदा मुद्दों पर बात करने की जरूरत है।

● आदित्य ठाकरे



राष्ट्रीय स्वयं संघ को लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। संघ के पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है और ना ही वह किसी को अपने हिसाब से चलाता है। संघ का कोई एजेंडा नहीं है, वह भारत के संविधान को मानता है। हम शक्ति का कोई दूसरा केंद्र नहीं चाहते, संविधान के अलावा कोई शक्ति केंद्र होगा, तो हम उसका विरोध करेंगे।

● मोहन भागवत



भारत के पास विराट कोहली है जो शायद सर्वकालिक महान वनडे खिलाड़ी है और रोहित शर्मा है जो शायद सर्वकालिक बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पांच में शामिल होगा। वे लाजवाब हैं और अभी भारतीय टीम की विशेषता यह है कि उसके अनुभवी खिलाड़ी बड़े मैचों में अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं।

● एरोन फिंच



मेरा मानना है कि सीएए असंवैधानिक है। हर राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करने और इसे वापस लेने का संवैधानिक अधिकार है। जब कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक घोषित किया जाता है तो इसका विरोध करना समस्याग्रस्त होगा। लड़ाई जारी रहेगी।

● कपिल सिब्बल



हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक सज्जन कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा दिए जाने से पहले भारत की कोई अवधारणा थी। यह सही नहीं है। अगर भारतवर्ष नहीं था तो महाभारत क्या था? जो 5000 साल पहले एक महाकाव्य लिखा गया था, वो क्या था? वेद व्यास ने क्या लिखा था? कुछ लोग हैं, जिन्होंने ऐसे नैरेटिव बनाए हुए हैं, जो उनको सूट करते हैं। श्रीकृष्ण जिस महाभारत में थे। तो भारत तो था, तभी तो वह महान था। तभी तो भारतवर्ष के सभी राजाओं ने मिलकर वह महायुद्ध लड़ा था। नेचुरल सी बात थी कि जैसे आप देखते हैं कि यूरोप के कुछ राष्ट्र हैं, वो राज्य छोटे-छोटे थे, लेकिन उनकी एक पहचान थी। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिसका नाम था भारत।

● कंगना रनावत

वाक्युद्ध



केंद्र सरकार सीएए थोपकर देश में कुछ विशेष लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। आज पूरे विश्व में भारत की छवि खराब हो रही है। धर्मनिरपेक्ष देश को धर्मशासित देश बनाने की कोशिश की जा रही है। जो कभी भी नहीं हो सकता। फिर देश में लोगों के बीच बैर-भाव क्यों फैलाया जा रहा है। यह समझ से परे है।

● राहुल गांधी

हम कहते हैं कि हम धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। तो हम ऐसा क्यों करेंगे? अपने ही लोग विदेश में देश को बदनाम कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश तो यह ऐलान कर चुका है कि उनका एक धर्म है। उन्होंने खुद को धर्मशासित देश घोषित किया है। हमने ऐसी घोषणा नहीं की है। यहां तक कि अमेरिका भी धर्मशासित देश है।

● राजनाथ सिंह



मप्र कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि यहां जितने दिग्गज नेता हैं पार्टी उतने धड़े में बंटी हुई है। बात भी सही है। लेकिन वर्तमान समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ गुट सबसे अधिक चर्चा में है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कमलनाथ ने या तो कुछ गुटों को साध लिया है या दबा रखा है। ऐसे में प्रदेश में जब भी सिंधिया सक्रिय होते हैं प्रदेश कांग्रेस में राजनीतिक हलचल का पारा बढ़ जाता है। लेकिन जनवरी में सिंधिया का तीसरा दौरा कांग्रेस को सियासी सुकून दे गया।

सिंधिया के दौरे से पहले तरह-तरह की अटकलें लगाई गई थी। लेकिन उनके इस दौरे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं तथा खुद सिंधिया ने गुटिय समीकरणों को भ्रामक प्रचार साबित करने का प्रयास किया। सिंधिया ने जनवरी महीने में प्रदेश के तीन दौरे किए। 16 से 19 जनवरी के चार दिन के तीसरे दौरे में सिंधिया ने गुटिय राजनीति की छाप से हटकर दूसरे नेताओं के समर्थकों से मेल-मिलाप कर सर्वमान्य नेता की छवि दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने इसके लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से हटकर दूसरे नेताओं के यहां पहुंचकर कांग्रेसजन को चौंकाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल प्रवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी उनके साथ सक्रिय दिखाई दिए। वहीं, सिंधिया ने न केवल अपने समर्थक दो मंत्रियों सहित अन्य नेताओं को समय दिया, बल्कि उन्होंने कमलनाथ समर्थक मंत्री सुखदेव पांसे व पचौरी समर्थक मानी जाने वाली मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधु के निवास पर पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस के दूसरे खेमों में भी अपनी मौजूदगी दर्शाने की कोशिश की।

यही नहीं सिंधिया ने अपने चार दिन के प्रवास में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम बनाया था। यहां वे अपने समर्थकों के अलावा पार्टी के दूसरे नेताओं के समर्थकों से मिले। उन्होंने अपने समर्थकों को पीछे रखते हुए आम कार्यकर्ताओं के साथ मेल-मुलाकात की। विदिशा में स्थानीय विधायक के घर पहुंचकर उनका मान रखा। चार दिन के दौरे में वे भोपाल, इंदौर, विदिशा, चंदेरी, मुंगावली में शादी समारोह व स्थानीय नेताओं से सौजन्य मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे तो अपनी पार्टी के नेताओं के घरों में हुए शोक पर श्रद्धांजलि देने उनके घर भी पहुंचे। सिंधिया के इस रूप को देखकर कांग्रेसी भी दंग रह गए।

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा भले ही खत्म हो गया हो, मगर उसके निहितार्थ खोजे जाने लगे हैं। डिनर से लेकर पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में गुटबाजी सतह पर

वर्तमान समय में मप्र की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन पार्टी के नेताओं में हमेशा एक अनजाना डर देखा जा सकता है। सबसे अधिक तब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में सक्रिय होते हैं। लेकिन विगत दिनों अपने प्रदेश दौरे के दौरान सिंधिया भोपाल और इंदौर में सियासी संतुलन साधते दिखे। ऐसे में सिंधिया के इस कदम का प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में अलग-अलग नजरिए से देखा गया।



सियासी संतुलन

अब तक ग्वालियर और चंबल में ही थे सीमित

ज्योतिरादित्य आमतौर पर हर हफ्ते प्रदेश के दौरे पर आते हैं, लेकिन फोकस अपनी संसदीय क्षेत्र गुना-शिवपुरी या चंबल अंचल में ही रहता है। लंबे समय बाद उनका इतना विस्तृत दौरा बना। वे भोपाल के बाद विदिशा, इंदौर एवं अपने संसदीय क्षेत्र भी जा रहे हैं। सिंधिया आमतौर पर दौरे से समर्थकों को संदेश देते हैं कि वे पूरी तरह सक्रिय हैं, इसलिए उनकी टीम को चिंता करने की जरूरत नहीं। वह भी सक्रिय रहे। सिंधिया को चाहते वाले इस कदर वफादार हैं कि उनके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। यह पूंजी ही सिंधिया को ताकतवर बनाए हुए है। सात माह बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे सिंधिया के समर्थन में जिस तरह कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ा वह इसका प्रमाण है। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष और राज्यसभा की अप्रैल में रिक्त हो रही सीटों को लेकर पार्टी में घमासान मचा है। पीसीसी अध्यक्ष के लिए प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही चर्चा चल रही है, जबकि राज्यसभा में जाने के लिए भी अभी तक हाईकमान की ओर से किसी तरह के संकेत नहीं आए हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव अभियान समिति का जिम्मा सौंपा गया था, लिहाजा सरकार बन जाने के बाद से उनके समर्थक अपने नेता को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की आस लगाए हुए हैं।

दिखी। कमलनाथ खेमा इस पूरे कार्यक्रम से दूर रहा। इसने कई तरह की अटकलों को जन्म दिया गया। सिंधिया दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर दौरे पर आए थे, इसलिए इसे उन्हें मिलने वाली नई जवाबदारी से जोड़कर देखा रहा है। इस दौरे से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह से दूरी बनाई उसकी भी चर्चा है। कमलनाथ भोपाल में थे और आईएएस एसोसिएशन के डिनर में शामिल होने गए लेकिन सिंधिया की मौजूदगी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के यहां डिनर में वे नहीं पहुंचे।

अगस्त में जब सिंधिया की मौजूदगी में मंत्री तुलसी सिलावट ने डिनर दिया था तब कमलनाथ पहुंचे थे और खासा समय दिया था लेकिन गोविंद राजपूत के यहां वे नहीं पहुंचे। वे चाहते तो थोड़े समय के लिए जाकर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ के सिंधिया से संबंध ठीक नहीं है। वे साथ-साथ दिखते रहे हैं। इसलिए चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री गोविंद सिंह राजपूत से नाराज हैं। एक समय गोविंद की अगुवाई में ही सिंधिया समर्थकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। कैबिनेट की बैठक तक में बड़ा हंगामा हुआ था। चर्चा यह भी है कि कमलनाथ ने सिंधिया के दौरे से दूरी बनाकर संदेश देने की कोशिश की है कि वे प्रदेश में दो पावर सेंटर बनने देने के पक्ष में नहीं है।

● सुनील सिंह

मप्र में कमलनाथ के ऊपर पिछले 13 महीने से दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। कमलनाथ का सारा ध्यान सरकार में लगा हुआ है। इस कारण वे संगठन को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला बार-बार उठता रहता है। पिछले एक साल से हर महीने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला उठता है और शांत हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस को फुलटाइम अध्यक्ष कब मिलेगा ?

मप्र कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और उसे कब नियुक्त किया जाएगा इस पर लगातार बहस चल रही है। अभी हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि नए पीसीसी अध्यक्ष का ऐलान 15 दिन के अंदर हो जाएगा। वहीं

अब खेल मंत्री जीतू पटवारी कह रहे हैं कि प्रदेश में निकाय चुनाव मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस पद के लिए समर्थक लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा जता रहे हैं लेकिन पार्टी खामोश है।

लोकसभा चुनाव के बाद सीएम कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने की बात कही थी। कमलनाथ ने कहा था कि सरकार और संगठन का काम एक साथ नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पार्टी को नए अध्यक्ष के बारे में सोचना चाहिए। युवा नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि इसके साथ ही उमंग सिंघार, जीतू पटवारी और प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन का नाम भी इस रेस में माना जा रहा है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद सिंधिया मध्यप्रदेश दौरे पर आए थे। इस दौरान सिंधिया ने पार्टी के सभी विधायकों और सभी खेमे के नेताओं से मुलाकात की थी। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी के निर्देश के बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्यप्रदेश में सक्रिय हुए हैं।

उधर, प्रदेश कैबिनेट के विस्तार की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ मंत्रियों की परफॉर्मंस के आधार पर उनके कद में कटौती और बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। साथ ही कुछ नए नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन यह सब करने से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तय मानी जा रही है। वहीं पार्टी में निगम मंडलों में राजनीतिक कुर्सी के लिए भी होड़ मची है। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए गाइडलाइन बनाई है। लेकिन उस गाइडलाइन पर अभी तक मुख्यमंत्री की सहमति



फुल टाइम अध्यक्ष कब ?

पचौरी-अजय किनारे क्यों... ?

सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाने के लिए कांग्रेस ने तीन दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव व पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को क्यों चुना, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। सरकार बनने के बाद बड़े नेताओं के बीच तनातनी को काबू में करने का रास्ता पार्टी हाईकमान ने तलाशा, तो वह भी विवाद की श्रेणी में आ गया। सात सदस्यीय समिति को देखकर साफ है कि गुटिय संतुलन पूरी तरह से नहीं बनाया जा सका है। यही वजह है, बड़े नेता होने के नाते इसमें मुख्यमंत्री नाथ के अलावा दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो जगह मिली लेकिन पचौरी, भूरिया व अजय को दूर रखा गया। एक और बड़े नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी भी समिति से बाहर हैं। चतुर्वेदी को अपने बेटे को सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा। समिति में शामिल कमलनाथ, दिग्विजय सिंह तथा सिंधिया के बाद प्रदेश में सबसे ज्यादा पकड़ अजय सिंह की मानी जाती है। अजय सिंह को शामिल न करने पर चर्चा चल पड़ी है कि बड़े नेताओं के अलावा समिति में शामिल मीनाक्षी, जीतू पटवारी एवं अरुण यादव पर पार्टी को भरोसा है और इनमें से किसी नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी सौंपने के कयास लगाए जाने लगे हैं। वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित पार्टी के कुछ नेता सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी या असंतोष व्यक्त करते रहे हैं। कुछ विधायकों ने बीच-बीच में मोर्चा भी खोला है। लेकिन सुरेश पचौरी एवं अजय सिंह सार्वजनिक तौर पर सरकार के खिलाफ कभी सामने नहीं आए। फिर भी नाराज चल रहे सिंधिया और यादव को समन्वय समिति में शामिल कर लिया गया और पचौरी व अजय रह गए।

नहीं बन पाई है। उधर, पिछले एक साल से निगम मंडलों में नियुक्ति की आस लगाए बैठे नेताओं में निराशा का भाव पनप रहा है। इस कारण अक्सर कोई न कोई नेता या विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने से चूकता नहीं है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही सरकार असंतोष दूर करने के लिए निगम मंडलों में नेताओं की नियुक्ति कर सकती है।

इस बीच पार्टी में बार-बार सामने आने वाले असंतोष को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने समन्वय का फॉर्मूला लागू कर दिया है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में जबसे कांग्रेस सत्ता में आई है। उसके बाद से ही संगठन और सरकार में तालमेल बैठाने की कोशिश हो

रही है। मगर नेताओं की गुटबाजी की वजह से आज तक यह सफल नहीं हो पाया है। ऐसे में कांग्रेस शासित प्रदेशों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने एक नया फॉर्मूला अपनाया है। इसके जरिए सरकार और संगठन में समन्वय बनाने की कोशिश की है।

दरअसल, सोनिया गांधी ने मध्यप्रदेश में सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी में सात लोगों को जगह मिली है। कमेटी का अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को बनाया है। इसके साथ ही सीएम कमलनाथ, दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व

अध्यक्ष अरुण यादव और मीनाक्षी नटराजन आदि भी समिति के सदस्य हैं। इनके कंधों पर सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी है।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस कई गुटों में बंटी है। हर गुट पॉवर कॉरिडोर में अपनी स्थिति मजबूत चाहती हैं। ऐसे में सबके तकरार भी सामने आते रहते हैं। दरअसल, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का एक अलग खेमा है। सीएम कमलनाथ का गुट भी अलग है। वहीं दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी अपने अलग-अलग गुट हैं। सरकार और संगठन में चारों पकड़ चाहते हैं। इस वजह बीच-बीच में खटपट सामने आते रहती है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिग्विजय सिंह और सिंधिया के पास संगठन और सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ऑफिसियली पहली बार दोनों समन्वय की

जिम्मेदारी दी गई। हालांकि दोनों ही नेताओं ने सरकार में अपने गुट के लोगों को जरूर शामिल करवाए हैं। उनके जरिए ही सरकार में दखलअंदाजी रखते हैं। सोनिया गांधी के द्वारा बनाई गई इस कमेटी में सभी लोग पार्टी के कद्दावर नेता हैं।

सोनिया गांधी द्वारा गठित कमेटी के मुखिया दीपक बावरिया की पकड़ दिल्ली दरबार में मजबूत है और वह सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक रूप से वह अपने इरादे स्पष्ट करते रहे हैं। प्रदेश प्रभारी रहते हुए वह पार्टी के अलग-अलग गुट को साथ लाने में कामयाब नहीं हुए। सियासी जानकारों के बीच चर्चा यह भी है कि सीएम कमलनाथ के साथ ही हाल के दिनों में उनकी ठन गई। वजह निगम और मंडलों में नियुक्तियों को लेकर भी है। ऐसे में सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित करना उनके लिए आसान नहीं है।

मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के साथ-साथ संगठन के भी मुखिया हैं। गुटबाजी के चलते विरोधियों से ज्यादा अपने ही उनके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। कभी सरकार के खिलाफ कोई विधायक उतर आता है तो कभी मंत्री कहने लगते हैं कि अफसर हमारी सुनते नहीं। यही नहीं इनके गुट के लोग दूसरे खेमे के नेताओं को टारगेट करते हैं। समन्वय समिति के

ही सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरकार से बेरुखी कई बार सुर्खियां बनीं। ऐसे में दूसरे खेमे के साथ तालमेल बैठाना सीएम के लिए आसान नहीं हैं। क्यों सरकार गठन के एक साल बीत जाने के बाद भी कमलनाथ पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं।



पांच महीने बाद सिंधिया को प्रदेश में जिम्मेदारी

ज्योतिरादित्य सिंधिया को पांच महीने बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 22 अगस्त, 2019 को कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी दी थी। उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि 23 जनवरी, 2019 को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में उनके पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था वो अभी भी पार्टी के महासचिव हैं। जानकारों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को समन्वय समिति में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह है उनकी नाराजगी को लेकर आ रही खबरें। मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाराजगी की खबरें आ रही थीं और उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी मांग की जा रही थी। लेकिन अब समन्वय समिति में शामिल होने के बाद सिंधिया सत्ता और संगठन दोनों के बीच समन्वय बनाएंगे।

मध्यप्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का एक अलग गुट है। उनके ऊपर प्रदेश के मंत्री यह आरोप लगाते रहे हैं कि पर्दे के पीछे से सरकार वहीं चला रहे हैं। दिग्विजय सिंह बीच-बीच में चिट्ठी लिखकर सरकार को नसीहत भी देते रहते हैं। ऐसे में कयास लगाए जाते हैं कि सीएम

के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप है। ऐसे में दिग्विजय सिंह के लिए पहली चुनौती तो समन्वय समिति के बाकी दिग्गज नेताओं के बीच ही समन्वय स्थापित करने की होगी। क्योंकि समिति में शामिल चारों नेताओं की राह अलग-अलग है।

कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्यप्रदेश में पावर के लिए लगातार दिल्ली से लेकर भोपाल तक संघर्ष कर रहे हैं। मध्यप्रदेश कांग्रेस का कोई खेमा नहीं चाहता कि सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले।

ऐसे में नए समीकरण के जरिए प्रदेश में वह सभी को साधने में लगे हैं। दूसरे गुट के नेताओं के साथ भी वह हालिया भोपाल दौरे के दौरान सक्रिय रहे और विरोधियों को भी साधने में लगे रहे। ऐसे में सवाल यह है कि सोनिया गांधी के समन्वय का यह फॉर्मूला क्या मध्यप्रदेश में कामयाब होगा। क्योंकि कमेटी में जिन चार नेताओं को उन्होंने समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है, उनके बीच आपसी समन्वय की कमी है। ऐसे में पहले तो इन नेताओं के बीच तालमेल सही हो। तभी मध्यप्रदेश में सोनिया गांधी का यह फॉर्मूला सफल होगा। अब सभी को समन्वय समिति की पहली बैठक का इंतजार है, जिससे बहुत कुछ साफ होगा।

मध्यप्रदेश में जबसे कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके बाद से ही यह शिकायत मिलती रहती है कि ज्यादातर मंत्री कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। सार्वजनिक मंच से भी कई बार पार्टी के विधायक भी यह सवाल उठा चुके हैं। हाल ही में सरकार की कुछ नीतियों को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने ही विरोध किया था। ऐसे ही विवादों को सुलझाने के लिए यह कमेटी बनी है। अब यह देखना है कि पिछले 13 महीने से बात-बात पर कांग्रेस में हो रहे विवाद पर यह समिति किस प्रकार अंकुश लगाती है।

● अरुण दीक्षित

सं गठनात्मक तौर पर मजबूत माने जाने वाले मप्र भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के लिए दिग्गज नेताओं में महीनों से प्रतिस्पर्धा चल रही है। लेकिन दिग्गजों में एक राय नहीं बन पाने के कारण अभी तक नए प्रदेश अध्यक्ष का मामला अधर में लटका हुआ है। हालांकि जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर से नए प्रदेश अध्यक्ष की संभावना बढ़ गई है। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के कई दावेदार हैं और वे अपने समीकरण भी बैठा रहे हैं। सागर संभाग से पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह भी प्रदेशाध्यक्ष के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह फिर से रिपीट किए जा सकते हैं। इनके अलावा कई और नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए सक्रिय हैं।

भूपेंद्र सिंह को चौहान और तोमर दोनों का ही करीबी माना जाता है। संघ की पसंद के चलते खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा का नाम भी दौड़ में शामिल है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इधर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए वे भी दावा ठोक रहे हैं। लेकिन अभी तक दिग्गज नेता मप्र अध्यक्ष के नाम पर मुहर नहीं लगा पाए हैं।

संगठनात्मक तौर पर मजबूत माना जाने वाला भाजपा का संगठन क्या एमपी में कमजोर पड़ गया है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा अब तक संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई है। न ही पार्टी अब तक प्रदेश अध्यक्ष को चुन पाई है। न ही सभी जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त कर पाई है। भाजपा जिलाध्यक्षों की पहली सूची करीब दो महीने पहले जारी कर चुकी है और दूसरे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी निर्वाचन हो चुका है। लेकिन मप्र में फैसला अटक हुआ है।

दरअसल भाजपा में 57 में से 52 संगठनात्मक

जेपी नड्डा के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब मप्र में भी नए अध्यक्ष को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। हालांकि पार्टी की ओर से नए अध्यक्ष को लेकर कोई संकेत नहीं मिला है, फिर भी नेता सक्रिय हो गए हैं। गौरतलब है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की आस में भाजपा का संगठन भगवान भरोसे चल रहा है। आलम यह है कि अभी तक 19 जिला अध्यक्षों का नाम भी तय नहीं हो पाया है।

फीसदी जिलाध्यक्ष चुने जा चुके हैं। इसके बावजूद नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ 19 जिलों में जिलाध्यक्ष चुने जाने हैं। ऐलान ना होने के पीछे एक ही वजह है कि नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही। पार्टी के सामने सरकार जाने के बाद संगठन को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि किसी भी एक नेता की राय पर मुहर नहीं लग पा रही है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाने में भी यही परेशानी सामने आ रही है।

उधर, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए भी प्रदेश के नेताओं ने कवायद शुरू कर दी है। अब तक भाजपा के पूर्व

राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की टीम में मध्य प्रदेश से पांच केंद्रीय पदाधिकारी थे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित राज्यसभा सदस्य प्रभात झा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद और ज्योति धुर्वे सचिव पद पर काम कर रहे थे। वहीं पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव के रूप में बंगाल का प्रभार संभाल रहे थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा की ताजपोशी के बाद अब केंद्रीय पदाधिकारियों को नई टीम बनेगी, जिसमें स्थान बनाने के लिए ज्यादातर नेता दिल्ली में सक्रिय हो गए हैं। चारों केंद्रीय पदाधिकारी पिछले कुछ समय से प्रदेश में अति सक्रियता दिखा रहे थे, जिसकी वजह साफ थी कि आने

वाली टीम में अपना स्थान बना सकें। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव भले ही संगठन नहीं करवा पाया हो, लेकिन अब राष्ट्रीय टीम में स्थान पाने की सियासत शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अब जल्द ही अपनी नई टीम बनाएंगे। इस टीम में मप्र से कौन-कौन से चेहरे होंगे, फिलहाल कहा नहीं जा सकता है पर स्थानीय नेताओं ने दिल्ली में सक्रियता बढ़ा दी है। नड्डा की ससुराल जबलपुर की है, इसलिए वे प्रदेश के ज्यादातर नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं।

● राजेश बोरकर

फिर तेज हुई दावेदारी



जिलों में जिलाध्यक्षों की रायशुमारी की गई थी। उसके बाद 5 दिसंबर 2019 को जिलाध्यक्षों की पहली सूची जारी की गई। पहली सूची में पार्टी ने केवल 33 जिलाध्यक्षों के नामों का ही ऐलान किया। 19 संगठनात्मक जिलों में नामों का ऐलान बाद में करने की बात कही गई। इसके पीछे वजह ये बताई गई कि भोपाल, इंदौर सहित 19 जिलों में बड़े नेता किसी एक नाम पर एकमत नहीं हो पाए। पार्टी विधान के मुताबिक, कुल संगठनात्मक जिलों में से 50 फीसदी में जिलाध्यक्षों का चुनाव होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। मध्य प्रदेश में 50

अपनी ही उलझन में गुम हो गई है भाजपा

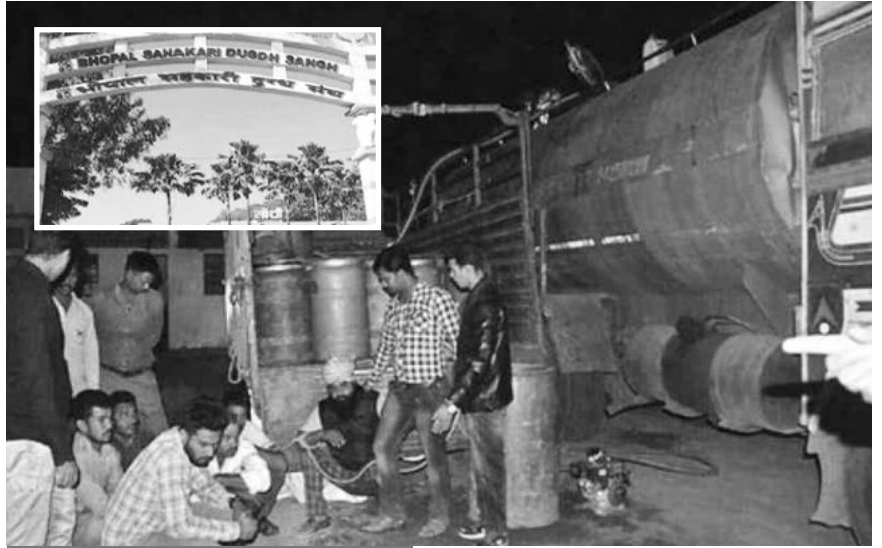
आपसी मतभेद से स्तब्ध, कांग्रेस को जवाब देने के तरीके को तलाशने में परेशान और उचित प्रतिक्रिया के लिए अनुपयुक्त मार्ग का इस्तेमाल करने के साथ मप्र की भाजपा इकाई दबाव का सामना कर रही है। जैसे-जैसे कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही है वैसे-वैसे भाजपा अपने खुद की तैयारी की गई उलझनों को समाप्त करने के लिए परेशान दिख रही है। कांग्रेस मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में आश्वस्त और उत्साही नजर आ रही है। कमलनाथ अपनी सरकार की योजनाओं के व्यापक संपर्क और लोकप्रियता के साथ काफी आगे हैं। यह भाजपा के लिए अपने आप में हतोत्साहित करने वाली बात है। लेकिन भाजपा एक सुसंगत प्रतिक्रिया तैयार करने में असमर्थ है। यह आलोचना करना चाहती है, लेकिन किस आधार पर?

एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी की तर्ज पर मद्र में मिलावट का घलमेल चल रहा है। मिलावट पर नकेल कसने के लिए एक ओर कमलनाथ सरकार हर तरह के माफिया और खासकर मिलावटी माफिया को जड़ से मिटाने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर सरकारी उपक्रम के तहत संचालित होने वाला सांची मिलावटी दूध के जरिये लोगों को धीमा जहर दिया जा रहा है। सांची दूध की यह स्थिति है कि यह पूरी तरह से वर्षों से माफिया के कब्जे में है, सांची दूध का खुलासा होने के बाद भी माफिया से मुक्त नहीं कराया गया बल्कि मिलावट माफिया के पूरे रैकेट को बचाने के लिए 45 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। यही नहीं कुछ दिन बाद सांची में अपने दूध के दाम बढ़ा दिए।

दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने के बावजूद हमारे देश में लोगों को शुद्ध दूध नहीं मिल रहा। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) की जांच में प्रोसेस्ड यानी पैकेट बंद दूध के 37.7 प्रतिशत नमूने गुणवत्ता मानकों पर फेल हो गए। जबकि, नियमानुसार इस दूध का एक भी नमूना फेल नहीं होना चाहिए। वहीं सांची के पास जो मशीन है वह दूध में 0.8 प्रतिशत या इससे अधिक यूरिया होने की पकड़ हो सकती है। जबकि अमूल और मदर डेयरी जैसी संस्थाओं में 0.1 प्रतिशत तक यूरिया पकड़ा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सांची दूध को ग्राहकों तक पहुंचाने से पहले उसकी शुद्धता की जांच करने वाली मशीन ही नहीं खरीदी गई। मिलावट माफिया बड़े आराम से 0.7 प्रतिशत तक यूरिया की मिलावट करता रहा। घटिया मशीन भी कभी पकड़ी नहीं गई।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में भी यह तथ्य सामने आया है कि सांची दूध के नाम पर हम और हमारे बच्चे धीमा जहर पी रहे हैं। दूध में यूरिया की मिलावट की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में यूरिया की मात्रा तय सीमा (700 पीपीएम-पार्ट पर मिलियन) से दोगुने से भी ज्यादा मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सांची दूध के टैंकर, कंटेनर में रखे दूध व बोरी में रखी यूरिया के सैंपल लिए थे। जांच में तीनों असुरक्षित (मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक) पाए गए हैं। हालांकि, फैट की मात्रा मानक के अनुसार मिली है। गड़बड़ी करने के आरोप में कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने टैंकर संचालक योगेन्द्र देव पाण्डे व ड्राइवर फरहान पर रासुका लगाया है।

गौरतलब है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने औबेदुल्लांगज के पास सांची दूध एक टैंकर को रात 7 बजे के करीब पकड़ा था। भोपाल की



मिलावट का घालमेल

प्रदेश में दूध का कारोबार

सरकार किसानों की सहकारी समितियों के जरिए दूध इकट्ठा करती है। यह काम सहकारिता के तहत डेयरी फेडरेशन करता है। फेडरेशन सांची के नाम से दूध या उसके उत्पाद बेचता है। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और बुंदेलखंड दुग्ध संघ हैं जो ग्रामीण प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों से दूध लेते हैं, ये समितियां किसानों और पशुपालकों से दूध इकट्ठा करती हैं। प्रदेश में 4698 सहकारी समितियां हैं जिनसे 2 लाख 57 हजार 418 किसान जुड़े हैं। इन किसानों से प्रतिदिन 10 लाख 10 हजार 888 किलो दूध इकट्ठा होता है, जबकि 7 लाख 40 हजार 271 किलो दूध का विक्रय होता है। बाकी से दुग्ध उत्पाद तैयार होते हैं। प्रदेश में दूध का कुल उत्पादन 150 लाख लीटर से ज्यादा है। जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे अमूल, मदर डेरी और सौरभ जैसी कंपनियां करती हैं। प्रदेश में दूध के कुल उत्पादन में सांची की हिस्सेदारी दस फीसदी भी नहीं है। यानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की प्रदेश के उन गांवों तक पहुंच है जहां तक सरकार नहीं पहुंच पाती है।

तरफ आ रहा यह टैंकर एक खेत के पास खड़ा था। इससे दूध निकालकर जमीन पर रखे कंटेनरों में भरा जा रहा था। पुलिस ने 40 कंटेनर व टैंकर जब्त किया था। मौके से एक बोरी में यूरिया मिला था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने यूरिया के

अलावा कंटेनर व टैंकर में भरे दूध के सैंपल लिए थे। जांच रिपोर्ट में तीनों सैंपलों में यूरिया की पुष्टि हुई है।

यूरिया की मिलावट के बाद अब सांची दूध में नमक और शक्कर मिलाने का मामला पकड़ में आया है। इस मामले में 5 दूध समितियों के सचिव और टेस्टर को हटा दिया गया है। इनमें बृजेश नगर, कनेरिया, बरखेड़ा सालम, खिजड़ा एवं बरखेड़ी घाट समिति शामिल हैं। गत दिनों यह जानकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सीईओ केके सक्सेना ने संभागायुक्त दफ्तर में आयोजित बैठक में दी। बैठक में संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले दूध की हर स्तर पर जांच की जाए। सक्सेना ने बताया कि वर्तमान में 3 लाख 25 हजार लीटर दूध कलेक्शन किया जा रहा है। इसमें से 8 हजार लीटर दूध की वृद्धि होकर क्षमता 3 लाख 33 हजार लीटर हो गई है।

उधर, भोपाल में सांची दूध फिर महंगा हो गया है। 12 जनवरी सुबह से सांची दूध दो रुपए प्रति लीटर महंगा बिक रहा है। पहले सांची गोल्ड आधा लीटर पैकेट 26 रुपए में मिलता था, अब यह 27 रुपए हो गया है। भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन के अधिकारियों के अनुसार किसानों की ओर से खरीदी के दाम में इजाफा किया गया है। इस वजह से दूध बिक्री के दाम बढ़ाए गए। दुग्ध संघ ने तीन महीने पहले ही दूध के दाम में दो रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।

उल्लेखनीय है कि सांची दूध के दाम छह महीने में तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। इससे पहले जून 2018 में और अक्टूबर में दो-दो रुपए प्रतिलीटर की बढ़ोतरी की गई थी। छह महीने के भीतर ये तीसरा मौका है जब 2 रुपए प्रतिलीटर की दर से दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह छह महीने के अंदर दूध के दाम छह रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है।

● अरविंद नारद



दलगत भावना से ऊपर उठकर विकास की बात हो

उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने अपने प्रभार के जिला देवास में जिला योजना समिति की बैठक ली। उन्होंने समिति के सदस्यों से कहा कि यह समिति जिले के विकास से संबंधित कार्यों पर चर्चा करने का मंच है। यहां जन-प्रतिनिधियों को दलगत भावना से ऊपर उठकर जिले के विकास की बात पर जोर देना चाहिए। पटवारी ने निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में विकास और निर्माण के कार्यों का नियमित निरीक्षण करें, जिससे व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखा जा सके। मंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, शिक्षा, महिला-बाल विकास, स्वास्थ्य, पशु-पालन और अजा-अजजा कल्याण की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से संबंधित सभी योजनाओं की अद्यतन जानकारी और ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी क्षेत्रीय विधायक को दी जाए।

शिक्षक-विहीन शालाओं में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। छात्रावासों में सोलर पैनल लगाने की कार्य-योजना बनाई जाए। पटवारी ने कहा कि नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की प्रक्रिया में जन-प्रतिनिधियों के प्रस्ताव भी शामिल किए जाएं। प्रसूति सहायता योजना में लंबित सभी मामलों में तुरंत भुगतान की कार्यवाही की जाए। जिला योजना समिति की बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में 30 गौ-शालाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 20 गौ-शालाओं का निर्माण आगामी फरवरी माह के अंत तक पूर्ण किया जाएगा। द्वितीय चरण में 90 गौ-शालाओं का प्रस्ताव है। बैठक में जानकारी दी गई कि देवास जिले के 500 तक की जनसंख्या वाले सभी गांव प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना में बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ दिए गए हैं। इसी तरह, 250 से 500 तक जनसंख्या के गांवों को मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना में ग्रेवल स्तर तक के मार्ग का निर्माण कर पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।

कड़कनाथ के पालन के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित करें

पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री लाखन सिंह यादव ने बानमोर में सहकारी दुग्ध संघ मुरैना द्वारा संचालित दुग्ध संयंत्र एवं रायरू में शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार कड़कनाथ और आरआईआर प्रजाति की मुर्गियों के चूजे पालकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन प्रजातियों के मुर्गी-पालन के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित करें। मंत्री यादव ने प्रक्षेत्र में कड़कनाथ, आरआईआर और चेपब्रो प्रजाति के मुर्गी पालन के साथ इन प्रजातियों की मुर्गियों के अंडों से विशेष मशीन द्वारा 21 दिन में चूजे निकलने की प्रक्रिया को देखा। इस प्रक्रिया में 18 दिन तक अंडों को मशीन में रखकर निर्धारित तापमान दिया जाता है। इसके बाद तीन दिन हेचर होने पर मुर्गी का चूजा प्राप्त होता है। चूजों को अनुकूल वातावरण देकर उनकी देख-रेख की जाती है। शासकीय कुक्कुट-पालन प्रक्षेत्र रायरू में 6-7 हजार मुर्गे एवं मुर्गियां हैं।



अब 1 हेक्टेयर में 85 क्विंटल गेहू की होगी पैदावार

मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक और छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। जिले का गारी पिपल्या देश का सबसे ज्यादा उपज वाला गांव बनेगा। राज्य की कमलनाथ सरकार ने इस गांव को गोद लिया है। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। जबकि सीएम कमलनाथ के निर्देश पर सरकार के तीन मंत्री सचिन यादव, तुलसी सिलावट और बाला बच्चन ने खेतों में जाकर उगी गेहू की फसल का जायजा भी लिया और किसानों की हौसलाअफजाई भी की। इंदौर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर सांवेर विधानसभा क्षेत्र का गारी पिपल्या गांव अपनी अलग पहचान बना रहा है। सरकार ने विशेष प्रयास कर गेहू उत्पादन के क्षेत्र में इसे देश में अक्वल बनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए किसानों को कृषि बीज, खाद और तकनीकी सलाह देकर विशेष प्रयास किए गए हैं और अब इस गांव में बोई गेहू की फसल लहलहा रही है। सीएम कमलनाथ के निर्देश पर इंदौर जिले के प्रभारी और गृहमंत्री

बाला बच्चन ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री सचिन यादव के साथ गारी पिपल्या गांव पहुंचे। उन्होंने खेतों में लहलहाती गेहू की उन्नत खेती को देखा। जबकि खेतों में पहुंचे तीनों मंत्रियों ने किसानों का स्वागत किया और कहा कि यहां फसल देखकर लग रहा है कि गेहू का बम्पर उत्पादन होगा और प्रदेश का ये गांव देश में गेहू उत्पादन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम करेगा। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कृषि विभाग के सहायक संचालक गोपेश पाठक का कहना



है कि हमारा लक्ष्य कि गारी पिपल्या गांव की औसत उत्पादकता पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में सर्वाधिक हो और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों को गांव में ले जाकर किसानों को विशेष ट्रेनिंग दिलवाई गई। उनको बोने की तकनीकी, खाद डालने का तरीका बताया गया और उन्हें जो भी समस्या आती है कृषि विज्ञानिकों को ले जाकर हल कराई जाती है।

प्रत्येक पंचायत में बनाए जाएंगे मंगल भवन

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सचिन यादव और परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मंत्रीद्वय ने राहतगढ़ में प्रतीक-स्वरूप 12 किसानों को सम्मान-पत्र और ऋण माफी प्रमाण-पत्र प्रदान किए। सागर जिले में योजना के द्वितीय चरण में कुल 22 हजार किसानों के 158 करोड़ 60 लाख रुपए के फसल ऋण माफ किए जाएंगे। प्रथम चरण में जिले के 50 हजार 886 किसानों के 156 करोड़ 21 लाख रुपए के फसल ऋण माफ किए गए।

राजस्व मंत्री ने कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना से लाभान्वित किसानों की सूची पंचायत भवनों पर चस्पा की जाएगी। प्रत्येक



पंचायत में मंगल भवन बनवाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को शादी-विवाह और मांगलिक कार्यों में स्थान के लिए परेशान न होना पड़े। राजपूत ने किसानों से आग्रह किया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्र सबसिडी योजना का भरपूर लाभ उठाएं।

मंत्री सचिन यादव ने राहतगढ़ में कृषि उपज मण्डी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों से कहा कि गौ-आधारित कृषि पद्धति अपनाएं। इससे कृषि की लागत में कमी आएगी और फायदा अधिक होगा। उन्होंने किसानों को कीट-नाशकों के अधिक प्रयोग से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी। यादव ने कहा कि राहतगढ़ कृषि उपज मण्डी को आदर्श मण्डी के रूप में विकसित किया जाएगा।



आपदाग्रस्त परिवारों को रियायती दर पर मिलेगा गेहूं

खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाग्रस्त मदसौर, नीमच, आगर-मालवा और भिण्ड जिले के लगभग 6 हजार परिवारों को 6 माह तक रियायती दर पर गेहूं मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने ढाई करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

मंत्री तोमर ने बताया कि प्राकृतिक आपदाग्रस्त परिवारों को एक रुपए प्रति किलो की दर पर 5 किलो प्रति सदस्य के मान से गेहूं प्रदाय किया जाएगा। उन परिवारों को ही गेहूं प्रदाय किया जाएगा, जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सस्ता राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपदाग्रस्त परिवारों को केवल गेहूं प्राप्त करने की पात्रता होगी। तोमर ने कहा कि आपदाग्रस्त परिवारों की संख्या में वृद्धि होने पर संचालक, खाद्य-नागरिक आपूर्ति को अधिकतम 15 प्रतिशत परिवारों को लाभान्वित किए जाने के अधिकार होंगे।

श्रीलंका में बनेगा भव्य सीता माता मंदिर

श्रीलंका में सीता माता का भव्य मंदिर बनाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्रीलंका के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मंदिर के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश और श्रीलंका के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी। मंदिर के साथ ही सांची में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बौद्ध संग्रहालय, अध्ययन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाने पर भी चर्चा हुई। इसकी कार्ययोजना भी जल्द बनाने निर्देश दिए गए हैं।



मुख्यमंत्री कमलनाथ मंत्रालय में श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। बैठक में महाबोधि सोसायटी के अध्यक्ष बनागला उपतिसा भी शामिल थे। मंत्री कमलनाथ ने कहा कि श्रीलंका में सीता मंदिर के भव्य निर्माण के लिए शीघ्र ही एक समिति बनाई जाए, जिसमें मध्यप्रदेश एवं श्रीलंका सरकार के अधिकारियों के साथ ही महाबोधि सोसायटी के सदस्य भी शामिल हों। समिति मंदिर निर्माण कार्यों की निगरानी करेगी, जिससे मंदिर का निर्माण तय समय में हो सके। कमलनाथ ने कहा कि कहा

कि मंदिर के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाए और इसी वित्तीय वर्ष में आवश्यक धन राशि भी उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने सांची में बौद्ध संग्रहालय, अध्ययन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए आवश्यक भूमि आवंटित करने के

साथ ही यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने को कहा। इसके लिए जल्द ही कार्ययोजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान की कई कंपनियों और अन्य संस्थाओं में सांची में विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने श्रीलंका यात्रा के दौरान सीता मंदिर के निर्माण के संबंध में वहां की सरकार से चर्चा की थी। उन्होंने सीएम के साथ बैठक में इसकी भी जानकारी दी।

● अक्स टीम

सोनाली मिश्रा को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक

भा रतीय पुलिस सेवा की वर्ष 1993 बैच की मध्यप्रदेश कैडर की अधिकारी सोनाली मिश्रा को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।



सोनाली मिश्रा वर्तमान में बीएसएफ में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदस्थ हैं। उन्हें राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिदेशक का प्रशस्ति पत्र (डीजी सीआर) भी

मिल चुका है। ज्ञात हो सोनाली मिश्रा मध्यप्रदेश के नीमच व रायसेन जिले की पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी है। उन्हें यूनाइटेड नेशन मिशन, सीबीआई में पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन नई दिल्ली व डीआईजी एंटी करप्शन मुंबई क्षेत्र सहित अन्य पदों पर कार्य करने का अनुभव है।

बीएसएफ आईजी की पदस्थापना के दौरान सोनाली मिश्रा का वर्ष 2017 व 2018 में हुई सफल अमरनाथ यात्राओं में भी अहम योगदान रहा है। गोगोलैंड कश्मीर में वर्ष अक्टूबर 2017 में हुए फिदायीन हमले को नाकाम करने में उन्होंने कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया था। इसमें तीन विदेशी आतंकवादी मारे गए थे।

डीजीपी ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए



मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे। उन्होंने वहां स्थित शौर्यशिला पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों को नमन किया। साथ ही राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय व शौर्यगाथा खंड भी देखा। पुलिस महानिदेशक ने संग्रहालय में मध्यप्रदेश पुलिस को समर्पित खण्ड का विशेष रूप से अवलोकन किया। साथ ही आगन्तुक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश भवन मुकेश जैन सहित अन्य अधिकारी उनके साथ थे। ज्ञात हो नई दिल्ली

के चाणक्यपुरी क्षेत्र में बने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक परिसर में शौर्यशिला की स्थापना उन बलिदानी पुलिसकर्मियों के सम्मान में की गई है, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां स्थित संग्रहालय भी शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृतियां संजोने के लिए समर्पित है। संग्रहालय में पुलिस प्रणाली के इतिहास और उसमें निरंतर होने वाले विकास को प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह शौर्यगाथा खंड में उन 35 हजार 134 पुलिसकर्मियों के नाम उक्तीर्ण हैं, जिन्होंने आजादी के बाद कर्तव्य पालन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

महिला अपराध पर सेमीनार आयोजित

महिला अपराध तथा जेंडर संवेदनशीलता विषय पर भौरी स्थित मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी में एक अहम सेमीनार का आयोजन हुआ। इस सेमीनार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं प्राशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 56 पुलिस अधिकारियों को पीड़ित महिलाओं के साथ संवेदनशील व्यवहार एवं महिला अपराधों की त्वरित विवेचना के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी जानकारी दी गई। साथ ही महिला अपराध नियंत्रण में महिला पुलिस अधिकारी की सशक्त भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।



पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा आयोजित इस सेमीनार में मुख्य वक्ता के रूप में शैफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी यूके की प्रोफेसर डॉ. सुनीता तूर ने विषयवस्तु को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्यप्रदेश अकादमी के निदेशक केटी वाइफे ने की। संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रश्मि पाण्डेय द्वारा किया गया। ज्ञात हो पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर महिला अपराधों की त्वरित विवेचना के मकसद से प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अकादमी भौरी में इस सेमीनार का आयोजन किया गया।

म प्र में सबसे अधिक महिला अपराध होता है। इसके लिए शराब को सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में शराब की नई दुकानों के खुलने पर प्रतिबंध लगा रखा था। अब जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है तो कर्ज में डूबे प्रदेश को उबारने के लिए सरकार शराब से राजस्व कमाने की कवायद में जुट गई है।

शराब के जरिए राजस्व भरने की कवायद में जुटी सरकार अब वित्तीय वर्ष के बचे 2 माह के लिए भी उपदुकानें खोलने को मंजूरी देने जा रही है। सरकार ने कहा है कि ठेकेदार चाहें तो चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले फरवरी और मार्च दो महीने के लिए शराब की उप दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सालभर के लिए निर्धारित अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा। उपदुकान खोलने की अनुमति संबंधित जिले के कलेक्टर देंगे। दरअसल, सरकार ने हाल में आबकारी नीति में बदलाव किया है। इसके तहत शराब लायसेंस को उपदुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में शराब की दुकान नहीं होने पर जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि में शराब दुकान नहीं होने पर उप दुकान खोलने की मंजूरी दी जाएगी। उप दुकान खोलने के लिए सालाना शराब ठेके के अतिरिक्त राशि देना होगी। शराब दुकान के लाइसेंस शुल्क के आधार पर उप दुकानों के अतिरिक्त शुल्क का स्लैब तैयार किया गया है। सवाल यह उठता है कि सरकार की यह कैसी नीति है कि एक तरफ तो प्रदेश को माफिया मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ शराब की उप दुकानें खोली जा रही हैं।

दरअसल, वर्तमान समय में मद्र करीब पौने दो लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। वहीं केंद्र की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार राजस्व, परिवहन और आबकारी विभाग के माध्यम से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने की कोशिश में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रदेशभर में शराब की उपदुकानें खोलने की तैयारी की जा रही है। आबकारी विभाग के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने जिस तरह से शराब की उप दुकानें खोलने के लिए दूरी की शर्त तय की है, उससे प्रदेश में करीब 500 उप दुकानें खुलने का अनुमान है। इसमें देसी और विदेशी शराब की उप दुकानें शामिल हैं। इससे सरकार को सालभर में करीब 1500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के आसार हैं। 2 करोड़ रुपए तक की शराब दुकान संचालक को उप दुकान खोलने 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देना होगी। दो करोड़ से 5 करोड़ रुपए मूल्य की दुकान के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। 5 करोड़

मद्र में सरकार ने इस समय माफिया के खिलाफ अभियान चला रखा है। माफिया चाहे किसी भी प्रकार का हो, मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि उनके खिलाफ सत्ता से सत्ता कार्रवाई की जाए। इसलिए भू-माफिया, ड्रग माफिया, कॉस्मेटिक माफिया के साथ ही तेजाब रखने वालों के खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विडंबना यह है कि सरकार ने शराब की उपदुकानें खोलने की अनुमति दे डाली है।



यह कैसी नीति?

फिर गुटखे पर प्रतिबंध क्यों?

सरकार एक तरफ प्रदेश में शराब की उपदुकानें खोलने की अनुमति देने जा रही है वहीं दूसरी तरफ उसने गुटखे पर आखें तरेरी हैं। सवाल उठता है कि आखिर सरकार की यह कैसी नीति है? जानकारों का कहना है कि शराब गुटखे से अधिक घातक होती है। प्रदेश में बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं शराब के नशे के कारण होती हैं। जबकि गुटखा खाने से कोई भी ऐसी घटना होने की संभावना नहीं रहती है। फिर भी सरकार शराब की दुकानें खुलवाने जा रही है। सरकार के इस कदम को भाजपा के साथ ही सामाजिक संगठनों ने गलत बताया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सरकार के इस कदम का हम हर कदम पर विरोध करेंगे। वह कहते हैं कि सरकार प्रदेश में दिखावे के लिए माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है। वह सरकार से सवाल पूछते हैं कि क्या शराब की दुकानें खुलने से प्रदेश में अपराध बढ़ेगा नहीं?

रुपए से अधिक की शराब दुकान संचालक को उप दुकान खोलने 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देना होगी। किसी मुख्य शराब दुकान के लिए एक या

एक से अधिक उप दुकानें भी स्वीकृत की जा सकेंगी।

प्रदेश सरकार की जो नई आबकारी नीति बनने जा रही है उसके मुताबिक शराब की दुकानें अलग-अलग नीलाम करने के बजाय ठेकेदारों के समूहों को एक या दो जिलों की सभी दुकानें देने की तैयारी है। इतना ही नहीं, एक साल का लाइसेंस देने और अगले साल टेंडर करने की व्यवस्था को भी बदलकर दो साल का लाइसेंस दिया जा सकता है। आबकारी विभाग के आला अधिकारियों के साथ शराब कारोबारियों की चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कारोबारियों की मंशा के अनुरूप इस तरह के बदलाव की तैयारी है। 16 साल पहले दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते शराब का कारोबार समूहों के ही हाथ में था। इसके बाद भाजपा के सत्ता में आने पर यह नीति बदल दी गई थी। इससे 2003-04 तक 750 करोड़ तक का सालाना रेवेन्यू सीधे 200 करोड़ रुपए बढ़ गया। 2019-20 में 11 हजार 500 करोड़ हो गया।

लंबे समय से शराब कारोबारियों का लाइसेंस नवीनीकरण ही किया जाता रहा। दस साल में आखिरी बार नीलामी 2015-16 में हुई। अब वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए नीलामी प्रस्तावित है। आबकारी विभाग को उम्मीद है कि इससे राजस्व बढ़ जाएगा। वर्ष 2018-19 में करीब 9000 करोड़ रेवेन्यू था, जिसे 2019-20 में बढ़ाकर 11500 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब इस लक्ष्य से भी आगे बढ़ना है।

● नवीन रघुवंशी



सा लभर फाइलों में गुम रहने वाले नौकरशाह जब हर साल आईएएस ऑफिसर्स सर्विस मीट में उतरते हैं तो उनकी मस्ती, खेल-कूद, गीत-संगीत आदि देखकर हर कोई अर्चाभित हो जाता है। इस बार भी राजधानी भोपाल में तीन दिनी आईएएस ऑफिसर्स सर्विस मीट में आईएएस ऑफिसरों की प्रतिभा देखने को मिली। मस्ती की पाठशाला में किसी ने खेलकूद, किसी ने गायन-वादन, किसी ने पाक कला तो किसी ने नाट्य कला में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मुख्य सचिव एसआर मोहंती से लेकर युवा आईएएस अधिकारियों ने तीन दिनों तक जमकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

आईएएस ऑफिसर्स सर्विस मीट में तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये अफसरों और उनके परिवारों का गेट-टुगेटर था। इसमें 1993 से लेकर 2017 बैच तक के एमपी कैडर के आईएएस अफसर शामिल हुए। मीट का उद्घाटन सीएम कमलनाथ ने किया था। 3 दिन की इस मीट में जिंदगी के विविध रंग देखने को मिले। बड़े तालाब में सैर सपाटे के साथ वॉटर स्पोर्ट्स भी हुआ, नावों की रेस हुई, जिसमें एक-दूसरे को हराने की होड़ थी। सैलानियों के आने से झील में रौनक आ गई। झील का नजारा देखने

मस्ती की पाठशाला



लायक था। बोटिंग और स्पोर्ट्स से फुरसत मिली तो अफसर झील के किनारे सेल्फी लेते रहे। दिन

में सैर-सपाटा और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। शेर-ओ-शायरी का दौर भी चला। साथी अफसरों ने भी हर शेर पर दाद दी।

आईएएस सर्विस मीट में खेलों के रोमांच और सैर-सपाटे के साथ गजल की महफिल भी जमी। दिनभर की थकान मिटी लजीज पकवान खाकर। अफसरों का कुकरी शो भी रखा गया था। एमपी आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित सर्विस मीट-2020 की पहली शाम अरेरा क्लब में अलग-अलग थीम पर कल्चरल इवेंट्स हुए। इसमें बाजी मारी ग्रीन ग्रुप ने। दूसरे स्थान पर रेड ग्रुप, तीसरे पर ऑरेंज ग्रुप रहा। ग्रीन ग्रुप के एसीएस विनोद कुमार एंड टीम ने 'शोला जो भड़के' पर डांस किया। ब्लू ग्रुप के एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स अविनाश लवानिया ने पत्नी मेधा के साथ 'नीले-नीले अम्बर पर' परफॉर्म किया। कलेक्टर भोपाल तरुण पिथोड़े ने पत्नी काम्या के साथ मैं शायर तो नहीं... गीत पर डांस किया। रेड ग्रुप के कप्तान प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव और सीएस एसआर मोहंती की पत्नी नंदिनी ने मर्डर मिस्ट्री पर एक्ट किया। यह कहानी एसआर मोहंती ने आईआईएम के दिनों में लिखी थी। किरदारों को भी अंत तभी पता चलता है जब कहानी खत्म होती है।

● विशाल गर्ग

ये रहे विनर्स

- ब्रिज: विनर-मोहनराव, वीपी सिंह
रनरअप: टीएन श्रीवास्तव, मलय श्रीवास्तव
- पतंगबाजी: विनर-संजीव श्रीवास्तव
- बिलियर्ड्स: मोहनराव, विजय कुमार
रनरअप: अजय नाथ और आनंद शर्मा
- पूल: विनर-मोहनराव, विश्वनाथ
रनरअप-वीके बाथम, अकित अस्थाना
- गोल्फ: विनर-एसआर मोहंती, अजय नाथ
रनरअप- मोहनराव,
विवेक अग्रवाल

- बैडमिंटन: मेंस डबल
विनर-संजय दुबे, उमेश सिंह
रनरअप-अभय वर्मा, अनिल सुवारी
- लेडी सिंगल्स
विनर-अरुणा मोहनराव, रनरअप-वंदना सिंह
- टेबल टेनिस मेंस डबल
विनर- मनोज गोविल, अर्चना
रनरअप-अनुराग जैन, अनयश
- टेनिस: विनर-अनुराग जैन, मनोज गोविल
रनरअप-अनय द्विवेदी, सुदाम खाड़े

- फुट क्रिकेट-विनर-टीम ग्रीन
रनरअप-टीम ब्लू
- बोट रेस: विनर-टीम ब्लू
रनरअप-टीम ग्रीन
- मोस्ट ग्रेसफुल कपल: विनर-मिस्टर एंड
मिस प्रमोद और रेणु अग्रवाल
- ड्रेस गर्ल: विनर-धनिका श्रीवास्तव
- बेस्ट ड्रेस बॉय: विनय-इशांत सिंह
- बेस्ट ड्रेस मेल: विनर-सौरभ सोनवाने
- बेस्ट कमेंट्रेटर: श्रीमन शुक्ला

आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार



बर्फ से घिरी वादियों वाले स्विट्जरलैंड के दावोस में चार दिनों तक चली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में दुनियाभर के शीर्ष उद्योगपतियों, राजनेताओं सहित करीब 3000 शख्सियतों के बीच मद्र का विकास चर्चा का विषय रहा। इसकी वजह यह रही की मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देशी-विदेशी उद्योगपतियों के बीच मद्र में निवेश के लिए जो तस्वीर प्रस्तुत की वह सभी को भा गई। यही नहीं कई निवेशकों ने तो उसी समय निवेश का प्रस्ताव दे दिया, तो कई ने निवेश की इच्छा जाहिर की। इससे यह संभावना बढ़ी है कि मद्र में जल्द ही बड़े-बड़े निवेश आएंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

दावोस में कमलनाथ की उद्योगपतियों से मुलाकात के बाद मध्यप्रदेश में 4125 करोड़ के निवेश पर मुहर लग गई है। इसमें मंडीदीप में स्थित दावत फूड कंपनी लिमिटेड को सऊदी अरब एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी से 125 करोड़ का विदेशी निवेश मिला है। विप्रो ने भोपाल में यूनिवर्सिटी खोलने पर सहमति जताई है। जापान की सॉफ्ट बैंक एनर्जी और इंग्लैंड की एक्टिस ने 4000 करोड़ की दो सेंट्रल विंड परियोजना में निवेश करने की प्रारंभिक स्वीकृति दी है। दोनों परियोजना 650 मेगावाट की होंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के तीसरे दिन कमलनाथ ने फोरम के अध्यक्ष बॉर्ज ब्रेंडे और लुलु ग्रुप के मालिक मोहम्मद यूनुस अली से भी मुलाकात की।

दावोस में विप्रो के सीईओ अबीदाली नीमचवाला ने कमलनाथ से मिलकर भोपाल में मेगा यूनिवर्सिटी खोलने पर सहमति जताई। यूनिवर्सिटी में बीएड और एमएड सहित अन्य कोर्स पढ़ाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी सोशल सेक्टर में भी काम करेगी। कंपनी प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव एसआर मोहंती और उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा से प्रोजेक्ट पर चर्चा भी की। अमेजन वेब सर्विस के वाइस प्रेसीडेंट मेक्स पीटरसन ने मध्यप्रदेश में अमेजन की एंटी की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, प्रदेश में डाटा सेंटर व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण है। सरकार सभी सुविधाएं देगी।

गौरतलब है कि मद्र पिछले एक साल में रियल स्टेट पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बना है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, नए हैरीटेज होटलों का पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी रियायत के साथ ही लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों में से निर्यातक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश नीतियों में दस से अधिक संशोधन पिछले एक साल में किए गए हैं। इससे प्रदेश की आर्थिक दर में वृद्धि और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष में प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन इण्डस्ट्रियल इजेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हाई एंड मैनुफेक्चरिंग के लिए शोध एवं अनुसंधान, रियल स्टेट, खनन क्षेत्र, एमएसएमई विकास नीति एवं पर्यटन सहित निवेश की संभावना वाले क्षेत्र में अधिकाधिक रियायत एवं प्रोत्साहित करने वाले निर्णय लिए गए हैं। इसका असर यह हुआ है कि प्रदेश में बेरोजगारी कम हुई है।

मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार गति पकड़ रही है और बीते एक साल में राज्य में जहां औद्योगिक क्षेत्र में 32,500 करोड़ रुपए

से ज्यादा का निवेश हुआ है, वहीं एक लाख नौ हजार से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। यह दावा सरकारी आंकड़ों में किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में पिछले वर्षों की तुलना में बीते 12 माह में स्थापित इकाइयों में 52 प्रतिशत अधिक निवेश हुआ है। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों के चलते वर्ष 2019 में प्रदेश में वृहद, मध्यम और लघु उद्योगों में कुल 32,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस अवधि में एक लाख नौ हजार 210 रोजगार के नए अवसर भी निर्मित हुए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उद्योगों को 773 एकड़ से अधिक विकसित भूमि आवंटित की गई। इससे पहले वर्ष 2018 में 463 एकड़ जमीन ही उद्योगों को आवंटित हो सकी थी। औद्योगिक केंद्र विकास निगम ने विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में 67 प्रतिशत अधिक विकसित औद्योगिक भूमि आवंटित की। इसके साथ ही बिजली की खपत भी 17 प्रतिशत बढ़ी है। अब दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में मिले संकेतों के बाद मद्र में और निवेश बढ़ने की संभावना है।

● श्याम सिंह सिकरवार

टाइम बाउंड क्लीयरेंस 2020 एक्ट का मसौदा तैयार

मध्यप्रदेश में निवेश को आकर्षित करने, युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध करवाने और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के लिए मुख्यमंत्री की चार दिवसीय दावोस यात्रा के दौरान उद्योगपतियों को इस मसौदे के साथ ही राज्य सरकार की निवेश मित्र नीतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछले एक वर्ष में प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए जो प्रयास किए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है निवेशकों के अंदर विश्वास की वापसी के साथ ही ऐसे अनेक निर्णय लेना जिससे उद्योगपति मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित हुए हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि परिणाम देने के लिए यह जरूरी है कि हर काम का समय सुनिश्चित हो और निर्धारित अवधि में वह काम हो। अपनी इस सोच को राज्य शासन की कार्य-संस्कृति में परिवर्तित करने के प्रयासों के साथ ही निवेश के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने विशेष पहल की है। उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को विभिन्न विभागों से समय पर उनके प्रोजेक्ट को क्लीयरेंस मिले, इस संबंध में जल्द ही एक सुनियोजित नीति बनाई जाएगी, जिसे कानून का स्वरूप दिया जाएगा।

प्राधिकरण इन दिनों जहां अपनी नई संपत्तियों खासकर भूखंडों को फ्री होल्ड की शर्त के साथ बेच रहा है, वहीं पुरानी लीज की संपत्तियों को भी फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इसके अलावा नगर तथा ग्राम निवेश की एनओसी के आधार पर पुराने भूखंडों को उपयोग परिवर्तन की मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन अब खुद नगर तथा ग्राम निवेश ने इन प्रावधानों का विरोध किया है, क्योंकि यह मास्टर प्लान के प्रावधानों के भी विपरीत है। नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जो अभिन्यास मंजूर किया जाता है उसमें भूखंड एक विशेष प्रयोजन के लिए आरक्षित हो जाता है और फिर उसका अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग विधि अनुकूल नहीं है। यानी फ्री होल्ड भूखंडों का भी उपयोग वर्तमान और भविष्य में बदला नहीं जा सकेगा। इस पर शासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मास्टर प्लान में अगर भू-उपयोग बदला गया है, तब ही नगर तथा ग्राम निवेश एनओसी जारी कर सकेगा। अपर संचालक डीएन त्रिपाठी ने इस आशय का पत्र भी भोपाल से इंदौर कार्यालय भिजवा दिया है।

प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड की तमाम लीज की संपत्तियों का दुरुपयोग होता रहा है, जिनमें इंदौर विकास प्राधिकरण के कई मामले तो चर्चित रहे हैं, जो अदालतों से लेकर लोकायुक्त जांच के दायरे में भी हैं। चाय-किराना व्यापारी से लेकर होटल सायाजी सहित कई चर्चित मामले भी हैं, जिनमें प्राधिकरण ने लीज शर्तों के उल्लंघन पर नोटिस थमाए और लीज निरस्ती की प्रक्रिया भी शुरू की। प्राधिकरण की तमाम योजनाओं में आवासीय या अन्य प्रयोजन के भूखंडों पर व्यावसायिक या अन्य गतिविधियां चल रही हैं, जिसके चलते अभी पिछले दिनों प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने नया नियम लागू किया, जिसमें मास्टर प्लान में अगर उपयोग व्यावसायिक या अन्य स्वीकार है तो 2 से 4 प्रतिशत वर्तमान गाइडलाइन के

फ्री होल्ड भूखंडों पर पहरा



मुताबिक राशि जमा कर प्राधिकरण लीज बहाली से लेकर फ्री होल्ड की प्रक्रिया कर सकेगा, लेकिन इसके पूर्व आवंटिती को इस आशय की एनओसी नगर तथा ग्राम निवेश से लाना पड़ेगी। इस शासन आदेश के चलते नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में ढेर सारे आवेदन एनओसी के लिए आ गए, जबकि होना यह था कि मास्टर प्लान में जिन जमीनों का भू-उपयोग बदल गया है या व्यावसायिक मार्ग घोषित किए गए हैं, उन पर ही एनओसी जारी की जा सकती है, मगर हर आवंटिती यह एनओसी लेने को तैयार हो गया।

इसके बाद नगर तथा ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक एसके मुद्गल ने संचालक नगर तथा ग्राम निवेश को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा कि उक्त भूखंडों पर प्राधिकरण द्वारा मूल अभिन्यास में उपदर्शित भूखंडों के उपयोग परिवर्तन के संबंध में अनापत्ति चाही जाती है, जबकि अभिन्यास स्वीकृति के समय उपविभाजन किए जाने के बाद भूखंड एक विशेष प्रयोजन के लिए आरक्षित हो जाता है और फिर इन आरक्षित भूखंडों पर पुनः अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकार्यता दी जाना विधि अनुकूल नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण द्वारा प्रेषित प्रकरणों में एक विशेष प्रयोजन के लिए आरक्षित भूखंडों के उपयोग में परिवर्तन होने की दशा में जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकार्यता के

संबंध में अनापत्ति चाही जा रही है और उक्त स्वीकार्यता का विवरण मास्टर प्लान की सारणी क्रमांक 6.22 में दिया गया है, जो कि रिक्त भूमि के ऊपर लागू होता है न कि उपविभाजित किए गए भूखंडों के ऊपर। इतना ही नहीं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01.02.2014 द्वारा मास्टर प्लान 2021 में जो उपांतरण किए गए थे, उसकी कंडिका 26 में सारणी 3.7 के नोट में निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी गई है... 'इन मार्गों पर पूर्व में स्वीकृत अभिन्यास में स्वीकृत उपयोग परिसर को परिवर्तित कर स्वीकृत उपयोग अंतर्गत अनुमत उपयोग परिसर की अनुमति दी जा सकेगी।' किन्तु यह टीप केवल कुछ विशेष मार्गों पर ही लागू होती है। दरअसल **सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई करते वक्त यह आदेश दिया था कि जिस आवासीय कॉलोनी का अभिन्यास मंजूर किया जाता है, भविष्य में उक्त भूखंड का उपयोग भी वही रहता है, जिसे बदला नहीं जा सकता।** नगर तथा ग्राम निवेश के इस पत्र के बाद शासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मास्टर प्लान में अगर प्राधिकरण की किसी योजना में मौजूद संपत्तियों का उन्नयन होता यानी भू-उपयोग परिवर्तन किया जाता है, तब ही नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा एनओसी यानी अनापत्ति पत्र जारी किया जा सकता है।

● विकास दुबे

प्राधिकरण खुद लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में

एक तरफ प्राधिकरण लीज शर्तों के उल्लंघन के आवंटितों को नए नियमों का लाभ देना चाहता है, दूसरी तरफ वह खुद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। योजना क्र. 59 के भूखंड क्र. 5 का आवासीय उपयोग है, जिस पर पेट्रोल पम्प के लिए एनओसी जारी की गई थी। जब विधानसभा में मामला उठा तो प्राधिकरण ने गलत तरीके से जारी एनओसी को न सिर्फ रद्द किया, बल्कि लीज शर्त के उल्लंघन का नोटिस भी थमा दिया। उक्त भूखंड कांग्रेस नेता अशोक धवन का है, जिसे फ्री होल्ड भी कर दिया था, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को निर्देश दिए कि जब फ्री होल्ड कर दिया है तो फिर लीज निरस्ती की प्रक्रिया क्यों की गई? हाईकोर्ट आदेश के बाद प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट गया और वहां से स्टे भी ले आया, जो अभी भी कायम है। यानी एक तरफ प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ अन्य भूखंडों को फ्री होल्ड करना चाहता है।

राजधानी में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आए दिन हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार की संगीन वारदात हो रही हैं। बावजूद अफसर यह कहकर अपनी नाकामी छिपा रहे हैं कि शहर में क्राइम क्रंटोल पर है। अफसरों से शहर के हालात पूछने पर एक ही जवाब मिलता है कि सब खैरियत है...।

अफसरों के इन दावों की सच्चाई उनके ही अपराध के आंकड़े बता रहे हैं। अपहरण के मामलों में 2018 की तुलना में 2019 में 27 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है। ये स्थिति तब है जब सरकार महिला अपराध को रोकने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। 2018 की तुलना में भोपाल में महिलाओं से जुड़े अपराध किडनैप, रेप, छेड़छाड़, दहेज हत्या, प्रताड़ना के मामलों में 8.17 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। जनवरी से नवंबर 2018 के बीच इन अपराधों में 2706 पर था और 2019 में इन अपराधों का ग्राफ 3009 पहुंच गया। महिलाओं के साथ किडनैपिंग के मामलों में 27 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

मध्य प्रदेश में 2018 के तुलना में 2019 में रेप के मामलों में कमी आई है, लेकिन प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही महिला अपराधों की स्थिति ठीक नहीं है। 2018 में मध्यप्रदेश में रेप के 5353 मामले दर्ज हुए, जबकि 2019 में 20 नवंबर तक रेप के 4926 मामले दर्ज हुए। 2019 में 427 रेप की घटनाएं कम हुईं। प्रदेश में महिला अपराध कम हुए, लेकिन ये शर्मनाक है कि राजधानी भोपाल में इस तरह की स्थिति है। यहां अपहरण, छेड़छाड़, रेप, दहेज हत्या, धमकी और प्रताड़ना जैसे अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। यहां महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है। पुलिस अधिकारी जरूर दावे कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े हर बार इन दावों की पोल खोलकर रख देते हैं।

वहीं, नए साल में भी नाबालिग के साथ रेप के कुछ केस दर्ज हुए हैं। साल के शुरुआती तीन दिन में भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में एक तेरह वर्षीय छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई। इसके साथ ही गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन में भी रिश्तेदार ने ही पांच वर्षीय बच्ची के साथ रेप किया। वहीं, चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर अर्चना सहाय ने कहा कि एनसीआरबी के जो रिपोर्ट आए हैं, उसके अनुसार नाबालिग के साथ जो अपराध के मामले दर्ज हुए हैं, उसमें 95-97



क्राइम कैपिटल

फीसदी लोग रिश्तेदार ही हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में समझाएं।

भोपाल में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं कोलार और हबीबगंज में घटित हुई हैं। इसके बाद छोला, निशातपुरा, गोविंदपुरा, अशोका गार्डन, जहांगीराबाद, पिपलानी और ऐशबाग पुलिस स्टेशन है। मीडिया से बात करते हुए डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि पुलिस लगातार एनजीओ के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रही है। ज्यादा फोकस आर्थिक रूप से कमजोर और स्लम एरिया में हैं। क्योंकि यहीं से ज्यादा केस आते हैं। साथ ही पुलिस ने वैसी जगहों को चिह्नित भी किया है जहां से छेड़छानी और ईव टीजिंग के मामले ज्यादा सामने आते हैं। मैत्री और शक्ति की टीम लगातार वहां विजिट करती है।

भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने माना कि शहर में अपहरण के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों के मामलों को पुलिस विभाग गंभीरता से लेता है। हम कार्रवाई करके बच्चों को छुड़ाते भी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की कोशिश रहती है कि लोगों को जागरूक

किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस हर मामले की बारीकी से जांच करती है।

राजधानी पुलिस से जारी आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2017 में अप्रैल तक 5452 अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किए गए। जिनमें हत्या, लूट, चोरी जैसे संगीन अपराधों की संख्या अधिक है। हालांकि यह आंकड़ा 2016 अप्रैल तक (5833) के मुकाबले करीब 400 कम जरूर है, लेकिन इस साल शहर में सनसनीखेज वारदात अधिक हुई हैं। सनसनीखेज अपराधों का आंकड़ा बढ़ने की प्रमुख वजह गुंडे-बदमाशों को पुलिस से मिल रही आजादी को बताया जा रहा है। सरकार की तरफ से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने जोर देने की बात तो हो रही है मगर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही।

आंकड़ों की गवाही

अपराध	2017	2018	2019
किडनैपिंग	276	343	434
रेप	261	282	396
छेड़छाड़	449	544	552
प्रताड़ना	410	295	373
दहेज हत्या	27	12	14
धमकी	945	1190	1240

● बृजेश साहू

ये हैं खौफनाक वारदातें

26 फरवरी 2019 को भोपाल के कटारा हिल्स में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। जब एक 16 वर्षीय छात्रा को 22 साल के लड़के ने अपहरण कर लिया। पार्क में चाकू की नोक पर उसके साथ रेप किया। इस घटना से पीड़िता और उसके परिवार के लोग इतने सहम गए अगले दिन शाम को पुलिस से संपर्क करने का साहस जुटा सके। बाद में आरोपियों ने कटारा हिल्स पुलिस के समझ समर्पण कर दिया। इसी तरह भोपाल के कोहेफिजा इलाके की नाबालिग लड़की के साथ दो लड़कों ने मनुआभान की टेकरी में एक मई को रेप के बाद पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। इसके बाद नौ जून को कमला नगर स्थित एक झुग्गी में दस वर्षीय नाबालिग के साथ उसके पड़ोसी ने रेप किया।

देश में वन भूमि पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण मध्यप्रदेश में हो रहा है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार अब तक मप्र में करीब 5,347 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है। जबकि दूसरे नंबर पर असम और

तीसरे नंबर पर उड़ीसा का नाम है। मध्य प्रदेश में वन विभाग के संरक्षण शाखा की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्रति वर्ष साढ़े 700 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर खेती और आवास

बनाने के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है। रिपोर्ट में ये बात भी स्वीकार की गई है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने में मात्र 20 फीसदी ही सफलता मिल पाती है। इसकी मुख्य वजह **वोट बैंक की राजनीति मानी जा रही है।** रिपोर्ट में पिछले तीन साल के अतिक्रमण आंकड़ों का हवाला देकर कहा गया है कि 13209 हेक्टेयर में अतिक्रमण हुआ। जबकि मात्र 1039 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराने में वन महकमा सफल हो पाया।

प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसे हटाने में प्रति वर्ष करीब 50 वन सुरक्षाकर्मी घायल होते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई हैं जिनमें सुरक्षाकर्मियों को अतिक्रमण मुहिम में जान से हाथ धोना पड़ा है। प्रदेश में करीब पांच माह पहले खंडवा जिले के गुड़ी वन परिक्षेत्र के आमाखुजरी में अतिक्रमण हटाने गए रेंजर सहित अन्य वन कर्मी और पुलिस कर्मियों को अतिक्रमणकारियों ने हमला कर घायल कर दिया था। इस मामले में राजनीतिक दबाव के चलते उल्टे वन कर्मियों पर ही सरकार ने प्रकरण दर्ज करा दिया।

इसके बाद डीएफओ सहित कई अधिकारियों को सजा के तौर पर स्थानांतरण कर दिया गया। इससे वन विभाग के अधिकारियों को झटका लगा है, हालांकि इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है। सूत्रों का कहना है कि अगले माह रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। जंगल माफिया गार्मी के मौसम में पहले पेड़ों की अवैध हटाई करते हैं और बारिश के दौरान उसे खेत के रूप में तब्दील कर देते हैं। वन विभाग के अवैध कटाई की रिपोर्ट को देखा जाए तो पेड़ों की अवैध कटाई सबसे ज्यादा मामले दिसंबर से मई के बीच दर्ज किए जाते हैं। इसी तरह अतिक्रमण के मामले मानसून सीजन (जून से लेकर सितंबर) में होते हैं।

वन मंत्री उमंग सिंघार के इंदौर परिक्षेत्र में एक साल 8 गुना अतिक्रमण हुआ है। इसके



अतिक्रमण में नंबर वन

प्रति वर्ष खर्च होता है 2600 करोड़

वन विभाग वनों की सुरक्षा और विकास के नाम पर प्रति वर्ष विभाग 2600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करता है। इसके अलावा ग्रान इंडिया मिशन, कैपा सहित अन्य मदों से विभाग को करोड़ों रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। इसके बाद भी वनों की सुरक्षा पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। अतिक्रमण, अवैध कटाई और उत्खनन के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं।

राज्यों में वनक्षेत्र की स्थिति

टॉप 5 राज्य	क्षेत्र वर्ग किमी में
मप्र	5347
असम	3172
उड़ीसा	785
महाराष्ट्र	605
अरुणाचल प्रदेश	586
टॉप 5 जिले	क्षेत्र हेक्टेयर में ये आंकड़े (2017 से 2019) तीन साल के अंदर के हैं
छतरपुर	6477
खंडवा	1997
शिवपुरी	1224
ग्वालियर	685
शहडोल	519

पहले इंदौर परिक्षेत्र में 2017 में 23 और 2018 में 25 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ था। वर्ष 2019 में 492 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ। वन मंत्री अपने क्षेत्र से मात्र 9 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवा पाए हैं। इसके अलावा अतिक्रमण के मामले में खंडवा, शिवपुरी, छतरपुर और शहडोल सर्किल सबसे आगे हैं। इन सर्किलों में वन भूमि पर हर साल करीब 300 से लेकर एक हजार हेक्टेयर तक अतिक्रमण होता है। छतरपुर जिले में वर्ष 2017 में 5992 हेक्टेयर में अतिक्रमण किया

गया, जिसमें से मात्र 22 हेक्टेयर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग आलोक कुमार कहते हैं कि प्रदेश में वन भूमि पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण मालवा, चंबल और शहडोल क्षेत्र में होता है। अतिक्रमण पुलिस और प्रशासन के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रति वर्ष की जाती है। कई जगह पर अतिक्रमण हटाने के बाद लोग फिर से कर लेते हैं। प्रदेश में वन भूमि 95 हजार वर्ग किलोमीटर है।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

बुंदेलखंड पैकेज में हुए आर्थिक घोटाले की ईओडब्ल्यू ने विधिवत जांच शुरू कर दी है। भोपाल स्थित ईओडब्ल्यू मुख्यालय ने हाल ही में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) और वन विभाग के अधिकारी, ठेकेदार समेत अन्य एजेंसियों के खिलाफ मिले तथ्यों के सत्यापन की जांच रजिस्टर्ड की है। वहां से ईओडब्ल्यू सागर को तथ्य जुटाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सके। इधर एक चर्चा ये है कि यह जांच कांग्रेस के आला नेताओं के निर्देश पर शुरू हुई है। दरअसल लोकसभा-2019 के दौरान चुनावी सभाओं में तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घोटाले की जांच की घोषणा की थी। इसी दौरान इस घोटाले को लेकर कई नए खुलासे किए गए।

बुंदेलखंड पैकेज में हुए घोटाले और धांधली के खिलाफ लगातार आवाज उठाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता पवन घुवारा का कहना है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने मप्र-उप्र के बुंदेलखंड को सूखे से निपटने के लिए 7600 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसमें से मप्र के बुंदेलखंड (दतिया समेत सागर संभाग) को 3860 करोड़ रुपए मिले। लेकिन इसमें से एक अनुमान के अनुसार 2100 करोड़ रुपए तत्कालीन जनप्रतिनिधियों व अफसर-इंजीनियर हजम कर गए। पैकेज से बुंदेलखंड में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ, जिससे यहां के लोगों के जीवनस्तर में कोई बदलाव आया हो।

सागर ईओडब्ल्यू के एसपी नीरज सोनी का कहना है कि पिछले साल मीडिया रिपोर्ट्स के तत्कालीन खुलासों के बाद ईओडब्ल्यू ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया। प्रारंभिक जांच में ही हमें काफी गंभीर किस्म की अनियमितताएं मिली। उसके आधार पर ही मुख्यालय ने तथ्यों के सत्यापन की प्रक्रिया को रजिस्टर्ड किया है। उम्मीद है हम जल्द ही जांच पूरी कर संबंधित दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेंगे।

जांच रजिस्टर्ड होने को लेकर बुंदेलखंड से विधायक एवं राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस पैकेज को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मंजूर कराने वाले प्रतिनिधिमंडल में, मैं भी बतौर विधायक शामिल था। प्रधानमंत्री सिंह ने राहुल गांधी के विशेष अनुरोध पर एक बड़ी राशि मप्र के बुंदेलखंड के लिए दी थी। लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार की मिली भगत के चलते यह पूरा पैकेज घोटाले का शिकार हो गया। अगर सही ढंग से जांच की



भ्रष्टाचार की जांच

100 से ज्यादा लोगों से की जाएगी पूछताछ

3760 करोड़ रुपए के बुंदेलखंड पैकेज की जांच के लिए ईओडब्ल्यू ने जांच अधिकारी तय कर दिया है। जोनल एसपी नीरज सोनी के अनुसार शाखा में पदस्थ इंस्पेक्टर एमके उपाध्याय इस मामले में एफआईआर करने के लिए जरूरी दस्तावेज, जांच रिपोर्ट्स से लेकर संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आदि का बयान लेंगे। एसपी सोनी के अनुसार एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान जांच अधिकारी 100 से अधिक लोगों के बयान लेंगे। पूछताछ का मुख्य बिंदु यही रहेगा कि उन्होंने सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि का व्यय कैसे और किन नियमों का पालन करते हुए किया। एसपी सोनी के अनुसार आरटीआई एक्टिविस्ट, अखबारों से मिली जानकारी के आधार पर शाखा द्वारा अधिकांश जरूरी दस्तावेज पहले ही जुटा लिए गए हैं। लेकिन एक पुख्ता केस तैयार करने के लिए हमें सपोर्टिंग दस्तावेज से लेकर जांच रिपोर्ट्स की मूल प्रति की जरूरत होगी। जांच अधिकारी पत्राचार कर संबंधित विभाग प्रमुखों से मंगवाएंगे। उन्हें यह काम पूरा करने के लिए मैनुअल के अनुसार 3 महीने का वक्त दिया गया है। बता दें कि इसी सप्ताह ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल ने पैकेज के तहत काम करने वाले आरईएस और वन विभाग के खिलाफ पुख्ता जांच को मंजूरी दी है।

जाए तो यह गड़बड़ी तत्कालीन भाजपा सरकार के सिंहस्थ घोटाले से कहीं अधिक बड़ा साबित होगा।

ईओडब्ल्यू के प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इस तरह के मामलों में साधारणतः 3 महीने का समय तथ्य जुटाने के लिए दिया जाता है। जांच अधिकारियों को अगर संबंधित विभागों से सहयोग मिला तो यह जांच और पहले कंपलीट हो सकती है। जांच के जल्द पूरे होने का एक बड़ा आधार हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता भोपाल के संयुक्त दल द्वारा की विस्तृत जांच रिपोर्ट भी है। इसमें पैकेज की राशि का कैसे बंदरबांट किया गया, इसका तथ्यात्मक व मैदानी लेखा-जोखा है। इस संयुक्त जांच दल में आरईएस, पीएचई, एग्रीकल्चर, मततस्य, पशुपालन, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग के आला-अधिकारी शामिल थे।

बुंदेलखंड पैकेज के तहत जिन छह जिलों में काम होना था उनमें सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना और दतिया शामिल हैं। सागर में 840 करोड़, छतरपुर में 918 करोड़, दमोह में 619 करोड़, टीकमगढ़ में 503 करोड़, पन्ना में 414 करोड़ और दतिया में 331 करोड़ का काम होना था लेकिन कुल फंड की 80 फीसदी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।

● सिद्धार्थ पांडे



भगवा पर हावी भक्ति

अपनी 'भगवा' राजनीति से विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी भाजपा मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ की 'भक्ति' से टेंशन में नजर आ रही है। दरअसल, दिखावे से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 13 माह के कार्यकाल में धर्म और संस्कृति के विकास, विस्तार और संवर्द्धन की दिशा में जो कदम उठाए हैं वे जन मानस पर छा गए हैं। इस कारण जनता में कमलनाथ और उनकी सरकार की बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा के रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है।

● राजेंद्र आगाल

क हावत है कि 'लोहे को लोहा ही काट सकता है।' मप्र में 15 साल सत्ता से दूर रही कांग्रेस ने भाजपा की भगवा सरकार को उखाड़ने के लिए भक्ति का माध्यम चुना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा के माध्यम से घर बैठे कांग्रेसियों को निकलने के

लिए मजबूर किया और देखते ही देखते कांग्रेस नए जोश के साथ मैदान में नजर आने लगी। फिर 2018 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भक्ति अभियान की बागडोर संभाली। चुनावी अभियान की शुरुआत पूजा-अर्चना से शुरू कर कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता की कुर्सी से उतार दिया। उसके

बाद से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को उसी के अंदाज में जवाब देने में लग गए हैं। भाजपा के एजेंडे में जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मुद्दा सबसे ऊपर रहा, वहीं कमलनाथ सरकार श्रीलंका में सीता मंदिर बनाने जा रही है। इसके लिए रामगमन पथ पर काम हो रहा है और गौशालाएं बनाई जा रही हैं। ये वे



मुद्दे हैं, जिनका इस्तेमाल भाजपा ने आस्था के नाम पर खूब किया है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में एक बात अक्सर कही जाती है कि उनकी सोच वहां से शुरू होती है, जहां लोग सोचना बंद कर देते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भोपाल के मिंटो हॉल में हनुमान चालीसा के सवा करोड़ जाप एक साथ कराए जाने के आयोजन में यह बात पूरी तरह से सही साबित होती दिखाई भी दी। भाजपा जहां अपनी पूरी राजनीति भगवान श्रीराम को केंद्र में रखकर करती रही है, वहीं कमलनाथ ने सीता माता और राम भक्त हनुमान का हाथ अपने संकट निवारण के लिए पकड़कर सभी को चौंका दिया है। श्रीलंका में माता सीता के भव्य मंदिर के निर्माण पर तेजी से अमल करने की तैयारी हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इसे अमली जामा नहीं पहना पाए थे।

भाजपा से फिसलता हिंदुत्व एजेंडा

भारतीय राजनीति में भाजपा यह दर्शाने की हमेशा कोशिश करती है कि उसके एजेंडे में हिंदुत्व सबसे ऊपर है। मप्र की सियासत में अभी तक चित्रकूट के रामपथ गमन, श्रीलंका के सीता मंदिर, हनुमान, नर्मदा और गाय भाजपा के मुख्य मुद्दे रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही ये सभी मुद्दे भाजपा के हाथ से छीन लिए हैं। यही वजह है कि भाजपा आजकल प्रदेश में राम-सीता, हनुमान और गाय के नाम पर सियासत नहीं कर रही है। दरअसल, भाजपा की अब तक की राजनीति पर गौर करें तो हम पाते हैं कि वह अभी तक हिंदुत्व के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति करती आ रही है। लेकिन कमलनाथ ने इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाकर भाजपा के हाथ से हिंदुत्व के एजेंडे को फिसला दिया है। अपने 13 माह के कार्यकाल में धर्म और संस्कृति की दिशा में सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिससे भाजपा हासिए पर आ गई है। इसकी एक वजह यह है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल के दौरान जिन धार्मिक और

सांस्कृतिक क्षेत्रों के विकास की कोरी घोषणा की गई थी, उन्हें पूरा करने का काम वर्तमान कांग्रेस सरकार करवा रही है। प्रदेश सरकार के इस कदम को भाजपा राजनीति करार दे रही है। वहीं प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं कि यह राजनीति नहीं, सरकार का कर्तव्य है।

मप्र में भाजपा ने अपने पंद्रह साल के शासन में कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में काफी हद तक संघ लगा ली थी। पिछले चुनाव में कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व के चलते सांप्रदायिक आधार पर वोटों का धुर्वीकरण नहीं हो पाया था। इंदौर और भोपाल जैसे सांप्रदायिक रूप से संवदेनशील शहरों में भी उम्मीद से ज्यादा सफलता कांग्रेस को मिली। यद्यपि कांग्रेस को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। कांग्रेस को 114 सीटें मिलीं। भाजपा 108 सीटें ही जीत पाई। सिंहस्थ जैसे धार्मिक आयोजनों का भव्य स्वरूप भी भाजपा की मदद नहीं कर पाए थे। दलितों को भाजपा के पक्ष में लाने के लिए आयोजित किए गए समरसता स्नान का भी असर भाजपा के पक्ष में दिखाई नहीं दिया था। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता कहते हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ का भरोसा धर्म की राजनीति में नहीं है। पाखंडी तो भाजपा के नेता हैं। भाजपा का पाखंड उजागर हो चुका है।

हनुमान चालीसा और नर्मदा महोत्सव

राम, शंकर और नर्मदा भक्ति के सहारे विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार करने वाली कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में गांधीजी की पुण्यतिथि के मौके पर हनुमान पाठ का आयोजन सवा करोड़ मंत्रों के साथ कराने के बाद अनूपपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव का रंगारंग आगाज करवाकर सबका मन मोह लिया है। राजधानी के मिंटो हॉल में हुए हनुमान चालीसा के सवा करोड़ जाप को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का कहना है कि ऐसे आयोजन लोगों को भ्रमित करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन जनता भ्रमित नहीं होगी। वहीं भाजपा के सवालियों पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते

भाजपा के सारे दांव बेअसर

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भाजपा के सारे दांव बेअसर हैं। अपनी सटीक चाल से वह हर जगह अभी तक भाजपा को मात देते आए हैं। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा से मप्र में वह भी छिनने लगे हैं। इसके लिए उनके पास तीन प्लान हैं। जिसके जरिए भाजपा को मात देने की तैयारी है। इसके लिए वह सहारा ले रहे हैं, भगवान राम, मां सीता और बजरंग बली का।

श्रीलंका में बनवा रहे हैं सीता मंदिर

कमलनाथ भाजपा को धर्म के आधार पर घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते हैं। मध्यप्रदेश की सरकार श्रीलंका में भव्य सीता माता का मंदिर बनवा रही है। इसके लिए कमलनाथ ने हाल ही में अधिकारियों को एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा पिछले दिनों इसे लेकर श्रीलंका दौरे पर भी गए थे। मंदिर निर्माण के लिए वहां से एक प्रतिनिधिमंडल ने आकर सीएम कमलनाथ से मुलाकात भी की।

राजा राम की नगरी को संवार रहे

भाजपा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति कर रही है। लेकिन कमलनाथ राजा राम की नगरी को संवारने में लगे हैं। मध्यप्रदेश के ओरछा में राजा राम का निवास है। यहां के राजा आज भी राम हैं। ऐसे में सरकार ओरछा की ब्रांडिंग के लिए ओरछा महोत्सव का आयोजन कर रही है। जिसमें पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी तैयारी तेजी से चल रही है।

धर्म-संस्कृति की दिशा में सरकार के कदम

- महाकाल मंदिर विकास विस्तार योजना
- ओंकारेश्वर विकास कार्य-योजना
- रामपथ गमन विकास के लिए 22 करोड़ से अधिक मंजूर
- धार्मिक आस्था स्थलों का जीर्णोद्धार
- सिंधु दर्शन, कैलाश मानसरोवर और श्रीलंका तीर्थ-यात्रा
- मंदिरों, मठों, देव-स्थानों और नदियों का संरक्षण
- प्रमुख तीर्थ-स्थानों पर सुविधाओं का विस्तार
- धार्मिक-स्थलों पर सुरक्षा एवं प्रबंधन
- ब्लॉक-स्तर तक आनंदक मेले
- 1100 गौशालाओं का निर्माण
- मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना शुरू
- गौ-वंश संरक्षण में जन-सहयोग के लिए पोर्टल स्थापित

राम वनगमन पथ निर्माण के लिए बनेगा ट्रस्ट

राम वनगमन पथ निर्माण के लिए सरकार ट्रस्ट बनाएगी। निर्माण से जुड़े कामों की जिम्मेदारी सड़क विकास निगम की रहेगी। पहले चरण में 60 किलोमीटर का पथ निर्माण किया जाएगा। यह 30 किलोमीटर अमरकंटक और 30 किलोमीटर चित्रकूट क्षेत्र से लगा हुआ होगा। यह निर्णय 30 जनवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में राम वनगमन पथ निर्माण को लेकर हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। पथ के सर्वे के लिए सड़क विकास निगम को अधिकृत किया गया है। आध्यात्म मंत्री पीसी शर्मा विभागीय अधिकारियों के साथ जल्द ही प्रस्तावित मार्ग का जायजा लेने जाएंगे। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी मौजूद थे। सरकार ने राम वनगमन पथ का निर्माण करने के लिए बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सूत्रों के मुताबिक आध्यात्म विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने योजना का ब्यौरा दिया तो मुख्यमंत्री ने दो-टुक कहा कि कहानी नहीं, यह बताएं काम कब से शुरू कर देंगे। इसमें तेजी लाएं और जल्द ही ट्रस्ट बनाया जाए। इसमें साधु-संतों और जनप्रतिनिधियों को शामिल करें। पूरा निर्माण ट्रस्ट की निगरानी में हो। पथ निर्माण के लिए भगवान राम के प्रति आस्था रखने वालों से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जाए। पथ निर्माण से जुड़े सर्वे सहित अन्य काम सड़क विकास निगम करे।



हुए कहा है कि अगर भाजपा ये कहती है कि हनुमान चालीसा का जाप लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है तो उन पर धिक्कार है। हनुमान चालीसा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं राकेश सिंह के सवालों का सीएम कमलनाथ ने जवाब देते हुए पूछा है कि क्या धर्म की एजेंसी भाजपा के पास है। कांग्रेस के पूजा-पाठ करने पर भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है।

संजीवनी बनेगी हनुमान चालीसा

भोपाल की ऐतिहासिक इमारतों में से एक मिंटो हॉल में 29 जनवरी को एक और इतिहास लिखा गया। इस दिन शाम को हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया था। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे हनुमान सांस्कृतिक मंच भोपाल नामक संस्था थी। प्रधान पीठ पर जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता थे। हनुमान चालीसा का सवा करोड़ जाप कराने का संकल्प कमलनाथ सरकार के मंत्री पीसी शर्मा ने लिया था। पंडित मेहता के हजारों अनुयायी देश-दुनिया में हैं। एक चैनल के सीधे प्रसारण के जरिए उन्होंने भी हनुमान चालीसा जाप के इस आयोजन में हिस्सा लिया। लगभग ढाई घंटे के इस आयोजन में मधुर संगीत के साथ संकट मोचन के जाप किए गए। जिसे भारत सहित विश्व के आधा सैकड़ा से अधिक देशों ने लाइव देखा। कमलनाथ सरकार की इस भक्ति ने भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे पर पानी फेर दिया है।

हनुमान चालीसा के सवा करोड़ जाप के कार्यक्रम को महानिर्वाण नाम दिया गया था। मंच पर लगाए गए बैनर पर पंडित विजय शंकर मेहता के साथ हनुमान भक्त कमलनाथ की फोटो लगी हुई थी। छिंदवाड़ा के विशाल हनुमान का चित्र भी मंच पर लगाया गया था। राम-सीता के साथ हनुमानजी का चित्र भी लगाया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद को हनुमान भक्त बताने पर गर्व प्रकट करते हुए कहा कि हनुमानजी की मुझ पर अपार कृपा रही है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं। महात्मा गांधी और हनुमानजी के मेल पर पंडित विजय शंकर मेहता ने सत्य, अहिंसा और राष्ट्र भक्ति को मुख्य आधार बताया। जाहिर तौर पर कार्यक्रम को गैर राजनीतिक स्वरूप देने की कोशिश जरूर की गई। भाजपा नेताओं को ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न्योता भी दिया। लेकिन, कोई भाजपाई कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच पर रखी कुर्सी पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पंडित मेहता ने कार्यक्रम पर कहा कि मैं साल में आठ-नौ कार्यक्रम करता हूँ, लेकिन इस महानिर्वाण

को लेकर जो उत्सुकता लोगों में दिखाई दी, वैसी पहले कभी नहीं देखी गई। मेहता ने कहा कि 56 देशों में लोगों ने सीधे प्रसारण के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ किया।

हनुमान भक्त हैं सीएम कमलनाथ!

वैसे मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद बड़े हनुमान भक्त माने जाते हैं। 80 के दशक से खुद के संसदीय और अब विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर ग्राम सिमरिया में कमलनाथ ने 101 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की भी स्थापना की है। वहीं इंदौर के पास सनावदिया में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। एक करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर में स्थानीय लोगों के अलावा सरकार का आध्यात्म विभाग सहयोग करेगा। विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति कमलनाथ ने खुद तैयार की थी। उनकी रणनीति में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को जगह नहीं मिल पाई थी, जबकि राम वनगमन पथ और गाय जैसे संवदेनशील मुद्दों को भी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जगह दी। सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन वचनों पर तेजी से अमल भी शुरू किया है। राम वनगमन पथ के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। पंचायत स्तर पर गोशाला निर्माण का निर्णय हुआ। राज्य के विधि मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ हनुमान भक्त हैं। वे कहते हैं कि हर हनुमान भक्त भगवान श्रीराम और माता सीता के बगैर अधूरा है। मंत्री पीसी शर्मा द्वारा कमलनाथ को हनुमान भक्त बताए जाने की बड़ी वजह छिंदवाड़ा का हनुमान मंदिर है।

भाजपा से छीने 'राम-सीता, हनुमान और गाय'

मप्र की सियासत में अभी तक चित्रकूट के रामपथ गमन, श्रीलंका के सीता मंदिर, हनुमान, नर्मदा और गाय भाजपा का मुख्य मुद्दे रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही ये सभी मुद्दे भाजपा के हाथ से छीन लिए हैं। कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री की शपथ लेने के एक घंटे के भीतर प्रदेश में एक हजार गोशालाएं बनाने का आदेश जारी कर दिया। कुछ दिनों के भीतर ही बजट भी जारी कर दिया। अब गोशालाओं का लोकार्पण भी शुरू हो गया है। भाजपा गाय के नाम पर शुरू से ही सियासत करती आ रही है, फिलहाल मप्र में गाय का मुद्दा गायब है। अब कांग्रेस ने गोशालाओं को चुनाव में भुनाना शुरू कर दिया है। इसी तरह श्रीलंका में सीता मंदिर निर्माण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले



राज्यपाल ने थपथपाई कमलनाथ सरकार की पीठ

कभी भाजपा का होने वाले भगवा एजेंडा अब कांग्रेस का बड़ा एजेंडा बन गया है। सीए के विरोध पर मुस्लिमों के साधने में सफल हुई कांग्रेस के हिंदुत्व एजेंडे ने भाजपा की नींद जरूर उड़ा दी है और यही कारण है कि भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में हुए हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर मची सियासत के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने सरकार के सनातन धर्म को लेकर किए जा रहे कामों की तारीफ की है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के मंत्री राज्यपाल की तारीफ पर खुश हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि सरकार के रामपथ के विकास से लेकर श्रीलंका में सीता मंदिर और सुंदरकांड का पाठ कराने के काम तारीफ के काबिल हैं। आज देश को सनातन संस्कृति को बचाने की और मूल संस्कृति की तरफ लौटने की जरूरत है और सरकार के इस दिशा में उठाए गए कदम प्रशंसा वाले हैं। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि राज्यपाल ने 26 जनवरी पर भी सरकार के कामकाज की तारीफ की थी। राज्यपाल संजीदा नेता रहे हैं और गुण-दोष के आधार पर राज्यपाल ने सरकार के कामों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सरकार को उनका आशीर्वाद मिलना जारी रहेगा। वन मंत्री उमंग सिंघार ने कहा है कि राज्यपाल का तारीफ करना बताता है कि सरकार किस तरीके से अलग-अलग क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि राज्यपाल ने उनकी सरकार के कामकाज की तारीफ की जरूर की है लेकिन सरकार इतने प्रोपेगेंडा कर जनता के सवालों से बच नहीं सकती है।

एलान किया था, 2018 के चुनाव में भी चौहान ने सीता मंदिर का मुद्दा उठाया। लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 13 महीने के भीतर श्रीलंका में सीता मंदिर निर्माण की दिशा में काम शुरू कर दिया है। हाल ही में आध्यात्म मंत्री पीसी शर्मा को श्रीलंका भेजकर वस्तु स्थिति जानी। मंदिर निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर ली गई। अगले महीने आने वाले बजट में मंदिर निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा। जल्द ही अफसरों का दल श्रीलंका जाएगा।

महाकाल मंदिर विकास विस्तार योजना

विश्व प्रसिद्ध मध्यप्रदेश के भगवान महाकाल मंदिर के विकास और विस्तार की 300 करोड़

की योजना पर काम शुरू हो गया है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने महाकाल मंदिर के बारे में सोचा है। योजना के कामों की निगरानी के लिए मंत्रिमंडल की तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, आध्यात्म मंत्री पीसी शर्मा और नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्धन सिंह सदस्य हैं। योजना को समय-सीमा में पूरा कराने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को सौंपी गई है। योजना ऐसी बनाई गई है कि यहां ऐसी व्यवस्थाएं रहे कि श्रद्धालु एक-दो दिन आराम से रुक सकें। महाकाल मंदिर के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। उज्जैन शहर और वहां के रहवासियों का विकास भी इस योजना में शामिल है।

योजना के पहले चरण में यात्रियों-श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही, मंदिर के प्रवेश एवं निर्गम द्वार, फ्रंटियर यार्ड और नंदी हाल का विस्तार किया जा रहा है। महाकाल थीम पार्क, महाकाल कॉरिडोर और वर्केज लॉन पार्किंग आदि का निर्माण कराने की योजना है। दूसरे चरण में महाराजा बाड़ा, कॉम्प्लेक्स, कुंभ संग्रहालय, महाकाल से जुड़ी विभिन्न कथाओं का प्रदर्शन, अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, रूद्रसागर की स्केपिंग, रामघाट मार्ग का सौंदर्यीकरण, पर्यटन सूचना केंद्र, रूद्रसागर झील का पुनर्जीवन, हरी फाटक पुल, यात्री सुविधाओं और अन्य सुविधाओं का निर्माण और विस्तार शामिल है।

ओंकारेश्वर विकास कार्य-योजना

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गौरव को चिर-स्थायी बनाने के लिए 156 करोड़ की विकास कार्य-योजना को मंजूरी दी है। साथ ही, ओंकारेश्वर मंदिर के लिए शीघ्र ही कल्याणकारी एक्ट बनाने के निर्देश भी दिए हैं। यहां ओंकारेश्वर के प्रवेश द्वार को भव्य बनाना, मंदिर का संरक्षण, प्रसाद काउंटर, मंदिर के चारों ओर विकास तथा सौंदर्यीकरण, शांति कॉम्प्लेक्स, झुला-पुल और विषरंजन कुंड के पास रिटैनिंग वॉल, बहुमंजिला पार्किंग, पहुंच मार्ग, परिक्रमा-पथ का सौंदर्यीकरण, शेड निर्माण, लैंड-स्केपिंग, धार्मिक-पौराणिक गाथा की पुस्तकों की लायब्रेरी, ओंकार आइसलैंड का विकास, गौ-मुख घाट पुनर्निर्माण, भक्त निवास और भोजन-शाला, ओल्ड पैलेस तथा विष्णु मंदिर, ब्रह्मा मंदिर और चंद्रेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, ई-साइकिल तथा ई-रिक्शा सुविधा, बोटिंग, आवागमन, बस-स्टैंड, पर्यटक सुविधा केंद्र सहित अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं।

धार्मिक आस्था स्थलों का जीर्णोद्धार

राज्य सरकार ने पिछले साल शासन द्वारा संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया। साथ ही, इन मंदिरों के पुजारियों के मानदेय में भी तीन गुना की उल्लेखनीय वृद्धि की। इस दौरान 30 मंदिरों के जीर्णोद्धार और विकास के लिए 4 करोड़ 82 लाख 36 हजार रुपए की राशि जारी की। अब प्रदेश में मंदिरों को पर्यटन केंद्रों के स्वरूप में विकसित किया जा रहा है।

देव-स्थानों और नदियों का संरक्षण

राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों, देव-स्थानों और

सिंधु दर्शन, कैलाश मानसरोवर और श्रीलंका तीर्थ-यात्रा

प्रदेश में पिछले मात्र एक वर्ष में 23 हजार से अधिक तीर्थ-यात्रियों को राज्य सरकार ने 23 विशेष ट्रेनों के माध्यम से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई। इस यात्रा में तीर्थ-यात्रियों को भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई गईं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में सिंधु दर्शन, कैलाश मानसरोवर और श्रीलंका यात्रा को जोड़कर सर्वधर्म-समभाव का परिचय दिया। इसके लिए तीर्थ यात्रियों को 27 लाख 71 हजार की आर्थिक सहायता-अनुदान भी दिया गया। साथ ही, अन्य बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा निःशुल्क मुहैया कराई गईं। इस योजना के साथ ही, शासन द्वारा संधारित दो धर्मशालाओं का 32 लाख से जीर्णोद्धार भी कराया गया।

आध्यात्म के माध्यम से प्रदेशवासियों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की पहल

आध्यात्म वास्तव में मनुष्य में विकास की लालसा को गति प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। यह औसत से ऊपर उठकर जीने का विवेकपूर्ण तरीका भी है। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने इस शाश्वत सत्य को जन-मानस में संचारित करने के लिए वर्ष 2019 में आध्यात्म विभाग का गठन किया। प्रदेश में धर्मस्व, धार्मिक न्यास और आनंद विभाग के बिखरे स्वरूप को आध्यात्म विभाग में समाहित कर प्रदेशवासियों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने की अहम शुरुआत पिछले वर्ष ही प्रदेश में हुई। मध्यप्रदेश, भारतीय संस्कृति की अभिट धरोहरों से परिपूर्ण एवं समृद्ध राज्य है। यहां देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से दो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर प्रतिष्ठापित हैं। राज्य सरकार ने दोनों ज्योतिर्लिंग को विश्व पर्यटन केंद्र के स्वरूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओंकार सर्किट योजना में महाकाल-महेश्वर के साथ ओंकारेश्वर विकास योजना को भी मंजूरी दी है। पिछले एक साल में प्रदेश में जिले/ब्लॉक स्तर पर आनंदक सम्मेलन की शुरुआत की गई। गिविंग सर्किल की अवधारणा पर कार्य किया गया। वरिष्ठ नागरिक स्वैच्छिक डिस्काउंट कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रदेश में सामाजिक कल्याण एवं पारस्परिकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश में पहली बार समय विनियम कोष की परिकल्पना की गई। इस परिकल्पना में एक-दूसरे के कौशल का उपयोग करके दूसरों की मदद करना तथा समय को पूंजी के रूप में निवेश करना शामिल है, जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सके। आनंद फैलोशिप चार आवेदकों को स्वीकृत की गई। आनंद शिविरों में आम लोगों की भागीदारी के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन का प्रावधान किया गया। अल्प-विराम के द्वारा लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से संबंधित उदाहरणों का 'परिवर्तन की कहानी' के रूप में प्रकाशन तथा वेबसाइट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग 2200 स्थानों पर 14 से 18 जनवरी, 2019 के बीच आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश में आध्यात्मिक गतिविधियों का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक प्रदेशवासी जो भी कार्य करे, उसमें केवल उसका स्वार्थ नहीं हो बल्कि सभी की भलाई निहित हो। तभी प्रदेश सही मायने में विकसित राज्य बनने का हकदार होगा।



पवित्र नदियों के संरक्षण के लिए समितियों और न्यासों का गठन किया। मां नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी और ताप्ती के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए न्यास का गठन किया गया। इसी तरह, प्रदेश के मठ-मंदिरों के सुचारू संचालन के लिए सलाहकार समिति गठित की गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन का 8 मार्च, 2019 को गठन किया गया। ओंकारेश्वर मंदिर अधिनियम, गणपति मंदिर अधिनियम, मप्र शारदा देवी मंदिर अधिनियम, देव-स्थान प्रबंधन एवं विकास विधेयक में आवश्यक संशोधन किए गए।

शासन द्वारा संधारित देव-स्थानों की कृषि भूमि, दुकान, व्यावसायिक संपत्ति एवं भवन प्रबंधन का दायित्व संबंधित जिला कलेक्टर को सौंपा गया। शासन नियंत्रित देव-स्थानों की व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए देव-स्थान स्तरीय, अनुविभाग स्तरीय तथा जिला स्तरीय प्रबंध समिति नियम-2019 जारी किए गए। शासन संधारित मंदिरों/देव-स्थानों के पुजारियों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, नियुक्ति की प्रक्रिया, कर्तव्य, दायित्व, पुजारी की पदच्युति तथा पुजारी पद रिक्त होने पर व्यवस्था के संबंध में नियम बनाए गए। साथ ही, शारदा माता, गणपति खजराना, रामराजा ओरछा एवं ओंकारेश्वर ट्रस्ट के प्रस्ताव और प्रारूप तैयार किए गए।

प्रमुख तीर्थ-स्थानों पर सुविधाओं का विस्तार

प्रदेश के प्रमुख तीर्थ ओरछा और बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा में तीर्थ-यात्रियों की सुविधा के लिए पौने दो करोड़ से ज्यादा की लागत से सेवा सदन बनवाए जा रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा पथ पर यात्रियों की सुविधा के लिए 186 लाख की लागत से तीर्थ-यात्री सेवा सदन का निर्माण कराया जा रहा है। माता मंदिर, रतनगढ़ के विकास की करीब 5 करोड़ की समग्र कार्य-योजना में प्रथम किश्त 80 लाख जारी की गई। जिला दमोह में जोगेश्वर नाथ तीर्थ की विकास कार्य-योजना तैयार की गई। जिला ग्वालियर में धूमेश्वर तीर्थ विकास के लिए 36 लाख से ज्यादा की विकास योजना तैयार की गई। माता रतनगढ़ मंदिर और करीला माता मंदिर पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया गया। करीला माता मंदिर में निर्माणाधीन तीर्थ-यात्री सेवा सदन में वॉटर हॉर्वेस्टिंग, नक्षत्र वाटिका, जैविक खाद, पर्यावरण सुरक्षा तथा विद्युत, ऊर्जा, जल-संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन को आध्यात्मिक परम्परा से जोड़ते हुए नक्षत्र वाटिका तैयार की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से यह तो साफ हो गया है कि वह बिना राजनीति के धार्मिक स्थलों का विकास करवा रही है।

रामपथ को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना

राज्य सरकार ने रामपथ गमन विकास योजना को भी अंतिम रूप दिया है। योजना को सरकार की प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इसके लिए 22 करोड़ 9 लाख 32 हजार रुपए की राशि आध्यात्म विभाग को जारी कर दी गई है। इस राशि में से 4 करोड़ लघु निर्माण कार्यों, एक करोड़ 54 लाख 66 हजार स्थाई संपत्तियों के अनुरक्षण, 2 करोड़ मशीनों एवं उपकरणों के अनुरक्षण और अन्य आवश्यक निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ 54 लाख 66 हजार रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा, रामपथ गमन अंचल विकास, वृहद निर्माण कार्यों, पूंजीगत व्यय और समाज-सेवाओं के लिए 10 करोड़ की राशि दी गई है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। रामपथ गमन मार्ग में सतना, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिले आते हैं। इसमें चित्रकूट के 16 तीर्थ आते हैं। राज्य सरकार ने इस मार्ग पर तीर्थ-स्थलों के जीर्णोद्धार, संरक्षण, विकास एवं जन-सुविधाएं, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, मेले, उत्सव एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम की योजना बनाई है। रामपथ गमन फोर-लेन बनाया जा रहा है। रामपथ को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना है। रामपथ के बीच पड़ने वाली समस्त नदी, झरने एवं जल-स्त्रोत को प्रदूषण-मुक्त करना तथा छायादार पौधरोपण की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बार भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव त्रिकोणीय होने के आसार हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। 'लगे रहो केजरीवाल' गाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक झूम रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जिस फिल्म से यह बोल लिया गया है उसके किरदार मुन्नाभाई की तरह आपके प्रमाणपत्र भी जाली न हों। अब इस 'बाजीगरी' पर तो सवाल उठ ही सकते हैं कि बिजली, पानी और महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर काम चुनावों के चंद महीने पहले क्यों पूरे पांच साल क्यों नहीं हुए। पहले जो काम केंद्र और उपराज्यपाल नहीं करने दे रहे थे वही अब आपकी इच्छाशक्ति से हो गए। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाताओं का गरम मिजाज देख दिल्ली में पक्ष और विपक्षी दल नरम पड़ चुके हैं। पूर्ण राज्य और अन्य केंद्रीय मुद्दों को छोड़ बिजली-पानी और शिक्षा पर बात हो रही है। एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक खेल को छोड़ अब दोस्ताना मैच सा दिख रहा है।

केंद्र में सत्ताधारी भाजपा और हाशिए पर धकेली गई कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल और इन दोनों के खिलाफ विकल्प में उठी आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है। 2014 के पहले से ही दिल्ली के मैदान नए सामाजिक और राजनीतिक कथ्य का निर्माण कर रहे हैं। जो दिल्ली कभी अण्णा आंदोलन, राष्ट्रीय गान, तिरंगा झंडा और भ्रष्टाचार विरोधी नारों के साथ पूरे देश में गूंज रही थी, आज वह पूरी दुनिया में शाहीन बाग के लिए जानी जा रही है। तिरंगा और राष्ट्रीय गान के साथ एक नई चीज जुड़ी है भारत का संविधान। पिछले साल पंद्रह दिसंबर से दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है। कुछ महीनों पहले जहां तीनों दल एक-दूसरे पर आक्रामक थे, जनता की चीख गूंजते ही गरम दल से नरम दल में तब्दील हो गए हैं। दिल्ली के चुनाव में जब केंद्रीय मुद्दों के हावी होने की उम्मीद थी तो अब निकाय चुनाव जैसे बिजली-पानी और सड़क के मुद्दे ही हावी हैं। पिछले पांच सालों से चल रही आक्रामक राजनीतिक पारी अचानक दोस्ताना मैच में तब्दील दिख रही है।

पूर्ण राज्य से लेकर मुफ्त बिजली और पानी तक। केंद्र के साथ रिश्ते बदलते ही दिल्ली के मैदान के खिलाड़ियों का मुद्दा भी पूरी तरह बदल जाता है। पूर्ण राज्य एक ऐसा मुद्दा है जिसे तीनों दलों ने बहुत जोर-शोर से उठाया। इनमें से दो दलों को मौका भी मिला। इस वादे पर अमल करने का क्योंकि वे दोनों केंद्र की सत्ता में शक्तिशाली हुए। अब यह विडंबना ही है कि



त्रिकोणीय मुकाबला

दिल्ली चुनाव में बिहार की धमक

विधानसभा चुनाव भले ही दिल्ली में होने जा रहा है, लेकिन वहां भी 'बिहार की धमक' सुनाई दे रही है। दिल्ली चुनाव में तीन दलों ने अपनी रणनीति पूरी तरह बिहार की तिकड़ी या यूं कहें कि 'झा तिकड़ी' के हवाले कर दी है। दिल्ली चुनाव में भाग्य आजमा रही कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति की बागडोर जहां कांग्रेस के नेता और दरभंगा से पूर्व सांसद रहे कीर्ति झा आजाद के जिम्मे है, वहीं बिहार में सत्ताधारी जनता दल (यूनाइटेड) ने दिल्ली का चुनाव प्रभारी बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को बनाया है। यही नहीं, बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भी राज्यसभा सांसद मनोज झा को चुनाव प्रभारी बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही है। राजद और जद (यू) जहां अपने विस्तार पर लगातार जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस एकबार फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। दिल्ली के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पूर्वांचल समाज के लोग अच्छी खासी तादाद में हैं। यही कारण है कि दिल्ली के सभी राजनीतिक दल पूर्वांचली मतदाताओं को लामबंद करने के लिए अपने-अपने तरीके से योजनाएं बना रहे हैं। इस समाज के लोग मुख्य तौर पर उत्तरी-पश्चिमी, उत्तरी-पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली इलाकों में ज्यादा हैं। जद (यू) के एक नेता कहते हैं, 'दिल्ली चुनाव का दायित्व बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को सौंपा गया है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, इसी भरोसे जदयू यहां से कुछ सीटें हासिल करने की उम्मीद में है। पिछले दिनों बदरपुर में पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सभा कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर चुके हैं।' सूत्रों का कहना है कि जदयू भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरना चाहती है, जिसके लिए बातचीत भी चल रही है। हालांकि सूत्र यह भी कहते हैं कि अगर बात नहीं बनती है, तब जद (यू) अकेले भी चुनाव मैदान में उतर सकती है।

कांग्रेस ने पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया और केंद्र की सत्ता में आते ही इस पर बात करने से परहेज किया। भाजपा ने भी पूर्ण राज्य पर आंदोलनकारी रवैया अपनाया तो केंद्र में कमान मिलते ही इस पर आधे-अधूरे मन से बात करने लगी। अब रही बात आम आदमी पार्टी की जिसका केंद्र की सत्ता में अस्तित्व नहीं है। पिछली दो बार आम आदमी पार्टी ने पूर्ण राज्य के मुद्दे पर बहुत शोर मचाया। दिल्ली मेट्रो से लेकर आंटो और कोने-कोने तक इसके विज्ञापनों पर खर्च किया। यूं लगा कि दिल्ली की सारी समस्याओं की जड़ उसका पूर्ण राज्य नहीं होना है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल भी पूर्ण राज्य पर बात करने से परहेज कर रहे हैं। केंद्र ने जो नहीं करने दिया वह नहीं, बल्कि जो किया, कर सकते हैं और आगे करेंगे उसी का प्रचार कर रहे।

कांग्रेस और भाजपा के बाद केजरीवाल ने भी पूर्ण राज्य पर चुप्पी क्यों साधी? सबसे पहले तो एक चीज उन्हें समझ आ गई कि पूर्ण राज्य के दर्जे का मतलब है केंद्र सरकार से सीधी टकराहट। अपनी सत्ता के शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से पूरी तरह टकराव मोल कर जनता से सहानुभूति हासिल करने की रणनीति रखी। 'काम नहीं करने देते हैं जी, हमारे पास कोई शक्ति ही नहीं है' उनका प्रिय संवाद था। लेकिन विधानसभा चुनाव के छह महीने पहले वो सारे काम अचानक से होने लगे जो अब तक केंद्र सरकार उन्हें नहीं करने देती थी। खासकर प्रधानमंत्री को लेकर उनकी भाषा एकदम से बदल गई। अब अगर भाजपा ने दिल्ली के पानी की गुणवत्ता पर हमला बोला तो केजरीवाल ने बहुत नरम शब्दों में कह दिया कि हम मिलकर पानी की गुणवत्ता ठीक करेंगे और इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दे देंगे।

● ऋतेन्द्र माथुर

सबक लेने का वक्त

6

राजनीति में कोई भी हार या जीत आरिखरी नहीं होती। चूँकि भाजपा विचार के स्तर पर अलहदा दंग की पार्टी है, इसलिए उससे उम्मीदें कुछ ज्यादा ही की जाती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड की हार के बाद वह ठंडे मन से मुहों पर सोचेगी, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा बढ़ाएगी, लोकतंत्र को सही मायने में लागू करेगी और नौकरशाही पर लगाम लगाएगी। फिर वह कुशल शासन व्यवस्था की समझ वाले लोगों को ही जिम्मेदार पद देगी, जरूरत पड़ने पर अहंकारी नेता को बदलने में देर नहीं लगाएगी, तभी जाकर वह आगे बढ़ पाएगी।

9



बीजेपी को कितना बदल पाएंगे नड्डा ?

अक्सर मुस्कराते दिखाई देने वाले जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नड्डा की मोदी से पुरानी राजनीतिक जान-पहचान है और वह उनके नजदीकी भी रहे हैं। राजनीतिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखने वाले जेपी नड्डा के पास संगठन और सरकार में काम करने का लंबा अनुभव है। नड्डा को आरएसएस की परसंद माना जाता है, लेकिन क्या वह बीजेपी को अमित शाह की छाया से बाहर निकाल पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नड्डा का नजदीकी और लंबा रिश्ता रहा है। बीस साल पुरानी एक घटना है। तब नरेन्द्र मोदी बीजेपी के पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी थे। हिमाचल में फरवरी, 1998 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस को बराबर-बराबर 31-31 सीटें मिली थीं। कांग्रेस से अलग हुए नेता और भ्रष्टाचार से चौतरफा घिरे सुखराम की पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस को 5 सीटें मिली थीं। उस वक्त बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने सुखराम की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने से इनकार कर दिया था।

वर्ष 1962 के आम चुनावों में पूरी ताकत लगाने के बावजूद अपेक्षित सफलता न मिलने के बाद समाजवादी पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। इस नारे के आलोक में 1967 में हुए आम और विधानसभा चुनावों में सात राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनीं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस इन राज्यों में विपक्ष में बैठी। तब डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसी सरकारों से कहा था, 'बिजली की तरह कौंध जाओ और सूरज की तरह स्थायी हो जाओ।' इन शब्दों में लोहिया का गैर कांग्रेसी सरकारों के लिए संदेश था, जनहित में जल्दी-जल्दी चौंकाने वाले काम करो और लोगों के दिलों के बीच स्थायी रूप से छत्र जाओ। लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारें लोहिया का यह संदेश ग्रहण नहीं कर पाईं। कुछ ही दिनों बाद पहले उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों का पतन हो गया।

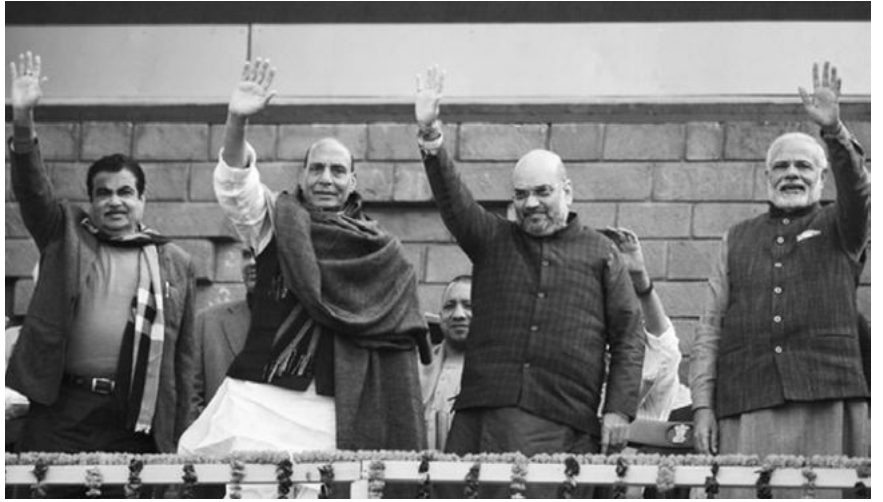
आजादी के बाद नरेन्द्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी नेता रहे, जिन्होंने खुद के दम बहुमत पाया। लोहिया के उन्हीं शब्दों को उधार लें तो वे बिजली की तरह कौंधे और सूरज की तरह छा गए। 2014 और 2019 के आम चुनावों में जिस तरह उन्होंने बड़ी जीत हासिल की, उससे माना जा सकता है कि उन्होंने जल्दी-जल्दी चौंकाने वाले काम किए और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। उनकी इस कामयाबी का स्वाद कई राज्यों में भाजपा ने भी

चखा। लेकिन पिछले एक साल से जिस तरह राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार-दर-हार होती जा रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि भाजपा के मुख्यमंत्री सूरज की तरह स्थायी कहां तक होते, बिजली की तरह कौंध भी नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के भाजपा के मुख्यमंत्रियों को लेकर तो इतना कहा ही जा सकता है। अक्टूबर के चुनावों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश की, मनमाने तरीके से टिकटों का बंटवारा किया, एकनाथ खड्गे जैसे नेता को किनारे लगाया और अब तो आरोप है कि पार्टी की दूसरी बड़ी कद्दावर नेता पंकजा मुंडे को परली विधानसभा सीट पर हराने में पार्टी का अंदरूनी हिस्सा भी सक्रिय रहा, उसका असर यह हुआ कि महाराष्ट्र में 2014 के विधानसभा चुनावों में

हासिल 122 सीटों की तुलना में 105 सीटें ही हासिल हुईं। कुछ वैसा ही झारखंड में हुआ। दिसंबर में हुए चुनावों में रघुबरदास की अगुवाई वाली भाजपा की इज्जत बचाने लायक हार हुई। पार्टी 33.7 प्रतिशत मत पाकर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला दल जरूर रही, लेकिन वह सत्ता से दूर हो गई। रघुबरदास की मनमानी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के राज्य के कद्दावर नेता सरयू राय ने न सिर्फ बागी रूख अख्तियार किया, बल्कि जमशेदपुर में अजेय समझे जाते रहे रघुबरदास को हार का स्वाद चखने के लिए भी मजबूर कर दिया।

भाजपा की हार की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यों में कठपुतली नेतृत्व को आगे बढ़ाया है। यह अमित शाह की कमी मानी जा सकती है। भाजपा से जुड़े सूत्र कहते हैं कि अमित शाह के इर्द-गिर्द वाह-वाही करने वाले लोगों की टीम जुट गई है और वे पार्टी के लिए उचित सलाह देने की जगह सिर्फ और सिर्फ उनकी वाहवाही करती रहती है। 1996 की तरह सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सुषमा स्वराज ने कांग्रेस की ओर सवाल उछाला था कि कहां है आपका दूसरी पंक्ति का नेतृत्व। उन्होंने अपनी यानी भाजपा की ओर का उदाहरण देते हुए कहा था कि हमारे पास वैकेंया नायडू, प्रमोद महाजन, अनंत कुमार, अरुण जेटली जैसे दूसरी पंक्ति के नेता हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अमित शाह के उभार के दौर में भाजपा में दूसरी पंक्ति के नेता ही नजर नहीं आ रहे। खुदा न खास्ता कोई उभरने की कोशिश करता है तो उसे उभरने ही नहीं दिया जाता है। अंग्रेजी में जिसे 'यस मैन' कहा जाता है, राज्यों में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐसे ही नेताओं को सत्ता दी जा रही है। एक दौर था कि मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार और राजस्थान में भैरो सिंह शेखावत जैसे मुख्यमंत्री थे, जिनका कद भारतीय जनता पार्टी की पहली पंक्ति के नेताओं जैसा था। भाजपा बेशक बड़ी हो गई है। लेकिन अब उसके पास ऐसे नेताओं की भारी कमी है और ऐसे नेता बनाने की उसकी अंदरूनी प्रक्रिया पर जैसे ब्रेक लग गया है। इसलिए जरूरी है कि पार्टी एक बार फिर इस तरफ सोचे। भाजपा अगर राज्यों में कद्दावर नेतृत्व नहीं उभार पाई तो निश्चित तौर पर यह उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा।

भाजपा एक दौर में ब्राह्मण-बनिया की पार्टी कही जाती रही है और उसके विरोधी उसकी इस हेतु आलोचना करते रहे हैं। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में उसने मान लिया है कि ब्राह्मण और ठाकुर वोट जाएंगे कहां, उसके ही पास आएंगे। इसलिए उसने ब्राह्मण नेतृत्व को किनारे लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि गंगा-यमुना के मैदान में उसी ने राज किया है,



जिसने ब्राह्मणों पर भरोसा किया है। ब्राह्मण समुदाय चूंकि ज्यादा बोलता है, इसलिए वह पार्टी के लिए माहौल बनाता है। पिछड़ी और आदिवासी जातियां अपने जातीय हक के लिए सिर उठा सकती हैं, लेकिन मौजूदा माहौल में ब्राह्मण नहीं उठा सकता। लेकिन उसके मन में कसक तो रहती ही है और उपेक्षित होने के बाद वह मायूस हो जाता है। इसका भी असर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं और वे वोटों को घरों से बाहर लाने के लिए उत्साह से काम नहीं कर रहे हैं।

भारतीय शासन व्यवस्था में कार्यकर्ताओं को कमाने देने की जो परिपाटी विकसित हुई है, उस परिपाटी से चूंकि स्वच्छता का दावा करने वाली भाजपा अलग रहती है। भाजपा में कार्यकर्ताओं को समायोजित करने का ढंग नहीं है। वह कांग्रेस और दूसरे दलों की तरह अपने कार्यकर्ताओं को खुश नहीं रखती, इसका भी असर है कि अब कार्यकर्ता नाराज हो रहा है और वह पार्टी के साथ खड़ा होने से हिचक रहा है। यह सच है कि केंद्रीय स्तर पर तीन तलाक, उज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं भाजपा ने लागू की। अक्ल तो इनसे जिन्हें फायदा मिले, उन्हें तो भाजपा का वोट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय लोकतांत्रिक

व्यवस्था में प्रशासनिक मशीनरी राज्यों के पास है और केंद्र की चाहे कितनी भी महत्वाकांक्षी योजना क्यों ना हो, उसे राज्यों के जरिए ही लागू किया जाता है। लेकिन इन योजनाओं को लागू करने वाला प्रशासनिक तंत्र बेहद भ्रष्ट है और दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा शासित राज्यों में भी इस तंत्र को काबू करने की कोशिश नहीं हुई। केंद्रीय स्तर पर सत्ता का विकेंद्रण कम ही हुआ और अधिकारियों को प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुली छूट दी। अधिकारी सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय की सुनते हैं और मंत्रियों तक की नाफरमानी करते हैं। नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है। इसीलिए अच्छी और भली योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं। इससे भी जनता नाराज है।

राज्यों में हो रही भाजपा की हार की एक वजह यह भी है कि अब जनता समझदार हो गई है। अनुच्छेद 370 का हटाना, नागरिकता कानून में संशोधन और राम मंदिर के निर्माण की राह को खोलने से व्यापक हिंदू समाज को आप खुश तो कर सकते हैं, लेकिन आज का वह समाज भी मानता है कि ये सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए वे भाजपा को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन राज्य स्तर पर तो वे उन्हें ही समर्थन देंगे, जो उनके रोजगार, रोटी और बेहतर जिंदगी का इंतजाम कर सकते हैं। लगता है कि भाजपा इन तथ्यों को नहीं समझ रही।

● दिल्ली से रेणु आगाल

मोदी की रणनीति, नड्डा का साथ

मोदी के लिए यह पहला मौका था, अपनी राजनीतिक कुशलता दिखाने का। मोदी हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे। मोदी ने रणनीति बनाई और जगत प्रकाश नड्डा ने उसे अमलीजामा पहनाने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी ने हिमाचल विकास कांग्रेस के चार विधायकों, कांग्रेस के एक नाराज विधायक और एक निर्दलीय विधायक को अपने पक्ष में कर लिया और बीजेपी के व अन्य सभी विधायकों को हिमाचल से हरियाणा के पंचकूला ले जाया गया। फिर पंचकूला से चंडीगढ़ के शिवालिक ब्यू होटल में रखा गया। उस दौरान मैं भी वहां मौजूद था। लेकिन हिमाचल प्रदेश के इंटेलेजेंस के अफसरों को भनक लग गई, इसलिए उन्हें वहां से हटाना जरूरी था। तब मोदी ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल से बात की और विधायकों को कुरुक्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। लंबी सियासी कसरत के बाद प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने और उस सरकार में नड्डा स्वास्थ्य और संसदीय कार्यमंत्री बनाए गए। तब से मोदी और नड्डा का रिश्ता बरकरार रहा। अक्सर हिमाचली टोपी लगाए रखने वाले नड्डा का जन्म दिसम्बर, 1960 में पटना में हुआ था, जहां उनके पिता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे।

शासन-प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने का नारा देकर सत्ता में आई मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक चंदा लेने की जो प्रक्रिया शुरू की है वह किसी भ्रष्टाचार से कम नहीं है। आलम यह है कि पार्टियां मिलने वाले चंदे से मालामाल तो हो रही हैं लेकिन जब चंदा देने वाले स्रोतों की जानकारी मांगी जाती है तो वह कहती हैं कि हम कागज नहीं देंगे। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों की नीयत शक के दायरे में आ रही है।



कागज नहीं दिखाएंगे

पारदर्शिता बढ़ाई जाए

मोदी सरकार को अपने फैसलों पर जनता को भरोसे में लेने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। आरटीआई कानून के भाग 4 में कहा गया है 'प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी। महत्वपूर्ण नीतियां बनाते हुए या जनता को प्रभावित करने वाली घोषणाएं करते हुए सभी प्रासंगिक तथ्यों को सार्वजनिक करेगा। प्रभावित लोगों को अपने प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक फैसलों के कारण बताएगा। 'इसके बावजूद, जैसा कि सार्वजनिक डेटा पोर्टल फैक्टली के संस्थापक एवं सूचना कार्यकर्ता राकेश रेड्डी डुब्बु कहते हैं, अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने जैसे अहम नीतिगत फैसले की निर्णय-प्रक्रिया के बारे में भी स्वेच्छा से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। इसके उलट फैसले की अचानक घोषणा की जाती है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के लिए सांसदों को महज कुछ घंटे ही दिए जाते हैं और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में संचार माध्यमों को ठप कर दिया जाता है, जिससे संबंधित औपचारिक आदेश को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

भारत में आर्थिक तरक्की की रफ्तार भले ही सुस्त हो, लेकिन राजनीतिक दलों की आमदनी पर इसका कोई असर नजर नहीं आता। बीते एक साल में छह राष्ट्रीय पार्टियों की कुल आमदनी में 2300 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने यह जानकारी दी है। एडीआर ने यह जानकारी पार्टियों के आयकर रिटर्न से हासिल की है जिसकी जानकारी सभी पार्टियों को चुनाव आयोग को देनी होती है। राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं। इनमें से एनसीपी ने अभी तक अपने आय और व्यय की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने जनहित याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीएम) और अन्य की

इलेक्टोरल बॉन्ड पर स्टे के लिए निर्देश देने पर सुनवाई को लेकर कही। आपको बता दें, सरकार ने 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया था। बॉन्ड के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बॉन्ड कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक है या जिसका भारत में कारोबार है।

जैसे वरुण ग्रोवर की कविता 'हम कागज नहीं दिखाएंगे' को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध प्रदर्शन करने वालों ने हाथों-हाथ लिया है। इस कानून का समर्थन करने वालों ने उसी तर्ज पर प्रदर्शनकारियों को 'कागज दिखाने के लिए तैयार रहने' की चेतावनी दी है। लेकिन जहां तक 'कागज दिखाने' की बात है तो भारत की राजनीतिक पार्टियां और नरेंद्र मोदी सरकार खुद सूचना साझा करने की अपनी विधिक और नैतिक प्रतिबद्धताओं में पिछड़ गई हैं। भारत में राजनीतिक दलों की फंडिंग हमेशा से अपारदर्शी रही है। पार्टियां कानून के तहत इस बारे में जानकारी सार्वजनिक करने का प्रतिकार करती हैं और इससे बचने के तरीके ढूंढते रहती हैं। वर्ष 2017 तक राजनीतिक दलों की फंडिंग के संदर्भ में आम लोगों को सबसे कम जानकारी नकद चंदे की होती थी।

जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक राजनीतिक दलों

को 20 हजार रुपए से अधिक के सारे चंदों की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है, बहुत से दल ये दावा करते हुए व्यवस्थित तरीके से इस अनिवार्य प्रावधान की अवहेलना करते हैं कि उन्हें मिले चंदे का बड़ा हिस्सा उन लोगों से मिला है जिन्होंने 20 हजार रुपए से कम का योगदान किया है। उदाहरण के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के उपलब्ध वित्तीय आंकड़ों के अनुसार पार्टी ने पिछले 13 वर्षों में 20 हजार रुपए से अधिक के एक भी चंदे की घोषणा नहीं की है। हालांकि, अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े दानदाताओं की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाती है और इसीलिए हम जान पाए कि 2017-18 में दो प्रमुख दलों को सर्वाधिक चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दिया था, जिसमें कि भारती एंटरप्राइजेज और अन्य कंपनियां शामिल हैं।

चुनावी बॉन्ड से बदली स्थिति पर, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के 2017 के बजट में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत किए जाने के बाद से मोदी सरकार ने राजनीतिक दलों पर वित्तीय जवाबदेही के भार को काफी कम कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 29 अधिकृत शाखाओं में से किसी से खरीदे जा सकने वाले चुनावी बॉन्ड पूर्णतया गोपनीय होते हैं। जनता इनके बारे में सिर्फ इतना भर जान सकती है कि किस पार्टी को कितनी राशि प्राप्त हुई है। हमें अब ये जानने का कानूनी अधिकार नहीं है कि राजनीतिक दलों को बड़े चंदे कौन दे रहा है। साथ ही, चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिल रहे चंदे की मात्रा बढ़ती जा रही है और बढ़ रहा है पार्टियों को इस गुप्त स्रोत से प्राप्त चंदे का अनुपात। 2017-18 और 2018-19 के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनावी बॉन्डों से मिलने वाले चंदे की मात्रा बढ़कर तीन गुना हो गई, जबकि कांग्रेस के कुल चंदे में इस स्रोत का अनुपात 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया। यानी, संक्षेप में कहें तो राजनीतिक दल अपनी आमदनी के उत्तरोत्तर बड़े हिस्से को सार्वजनिक छानबीन के दायरे से बाहर करते जा रहे हैं।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जुड़ी कार्यकर्ताओं अंजली भारद्वाज और अमृता जौहरी ने जब एक करोड़ रुपए से अधिक राशि के चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम मांगे तो एसबीआई की 23 शाखाओं से पिछले सप्ताह

उन्हें मिले जवाब की शुरुआत इस तरह थी, 'यह सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती है क्योंकि ये परस्पर विश्वास से जुड़ी जानकारी है और आरटीआई कानून, 2005 की धारा 8(1)(ई) एवं 8(1)(जे) में जिसे प्रकट नहीं करने की छूट है।' इस पर दोनों सूचना कार्यकर्ताओं ने बयान जारी कर कहा है कि 'यह जानकारी हासिल करने के जनता के अधिकार का उल्लंघन है। अधिकारियों ने इस विषय में



बढ़ रही है राजनीतिक पार्टियों की कमाई

राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं। इनमें से एनसीपी ने अभी तक अपने आय और व्यय की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। बाकी छह पार्टियों ने वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 3,698.66 रुपए की आय घोषित की। इनमें सबसे ज्यादा आय बीजेपी ने घोषित की। पार्टी को 2410.08 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, जो सभी पार्टियों की कुल आय का 65.16 प्रतिशत है। ये पिछले वित्त वर्ष में पार्टी द्वारा कमाई गई धनराशि में 1382.74 करोड़ यानी 134.59 प्रतिशत का इजाफा है। आमदनी के मामले में 918.03 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। ये सभी पार्टियों की कुल आय का 24.82 प्रतिशत है। ये पिछले वित्त वर्ष की कमाई के मुकाबले 718.88 करोड़ यानी 360.97 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो आय में सबसे ज्यादा वृद्धि तृणमूल कांग्रेस ने दर्ज की। पार्टी ने पिछले वित्त वर्ष में महज 5.167 करोड़ रुपये कमाए थे लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 में पार्टी ने 192.65 करोड़ रुपए कमाए, जो 3628.47 प्रतिशत की वृद्धि है।

व्यापक सार्वजनिक हितों पर गौर नहीं किया, जो कि हर उस मामले में अनिवार्य है जिनमें कि आरटीआई की धारा 8 के तहत सूचना देने से इनकार किया जाता हो।'

अब न सिर्फ राजनीतिक दलों को अनुग्रहित करने वाले व्यावसायिक हितों की जानकारी पाना मुश्किल हो गया है, बल्कि ये जानना भी आसान नहीं रह गया है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हित किन बातों में हैं, और परिणामस्वरूप हितों के टकराव का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है।

राज्यसभा के सांसदों को इन पांच मदों में प्राप्त पैसे की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। कंपनी निदेशक का लाभकारी पद, सामान्य लाभकारी गतिविधियां, नियंत्रणात्मक प्रकृति की शेयर हिस्सेदारी, शुल्कयुक्त सलाहकारी सेवा और/या कोई पेशेवर काम। सांसदों के निजी हितों का रजिस्टर सार्वजनिक होना चाहिए था, पर ऐसा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स (एडीआर) द्वारा आरटीआई

आवेदन दाखिल करने के बाद ही हो पाया। सीमित जानकारी देने की बाध्यता होने के बावजूद सचमुच में कुछ नहीं हो रहा है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक रहते नागरिक विमानन से जुड़ी संसदीय समितियों का सदस्य होना एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं।

लोकसभा में तो स्थिति और भी खराब है। सांसदों को सिर्फ अपने चुनावी हलफनामे में परिसंपत्तियों और देनदारियों की जानकारी देनी होती है, वे इसे अपडेट करने के लिए बाध्य नहीं हैं और उन्हें हितों के टकराव संबंधी कोई जानकारी देने की भी बाध्यता नहीं है। बीड़ी के व्यवसाय से जुड़े प्रमुख उद्योगपति और भाजपा सांसद श्यामाचरण गुप्ता तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी का आकार बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने वालों में शामिल थे और आश्चर्य नहीं कि उनका मत इसके खिलाफ था, साथ ही वह कैसर और तंबाकू के बीच के संबंध पर भी सवाल उठाने से नहीं चूके। ऐसे मामलों को उजागर करने की जिम्मेदारी पत्रकारों पर टिकी हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 'मिंट' अखबार ने ऐसे 100 नेताओं और उनके व्यावसायिक हितों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया था।

● इन्द्र कुमार

अब तक तो तारीख पर तारीख को लेकर परेशान थे, लेकिन कानूनी हथकंडों की वजह से निर्भया को इंसाफ मिलने की आस में लोग फांसी पर तारीख और तारीख बढ़ने से हैरान हैं। बचाव के कागजी हथकंडे, दरिंदों की असली उग्र छुपाने की गफलत, कानून के प्रावधान, संवैधानिक विकल्प और प्रशासनिक पेचीदगियां। इन सबको मिलाकर जो सीरप बन रहा है वो शायद निर्भया के चारों सजायाफ्ता दोषियों को जिंदगी की चंद सांसें बढ़ा दे, लेकिन फांसी के तख्ते पर जाने से नहीं रोक सकता। पटियाला हाउस कोर्ट ने आखिरकार इन्हीं कानूनी मजबूरियों की वजह से फांसी की तारीख टाल दी। यानी 22 जनवरी के बजाय अगर कुछ कानूनी बाधा, रोक या अड़चन नहीं हुई तो 1 फरवरी सुबह 6 बजे इन चारों दोषियों को फांसी होगी।

पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान भी यही सब सामने आ रहा है। खुद अदालत ने कहा कि हम इन कानूनी प्रावधानों और दोषियों को अपने बचाव के लिए मिले कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की वजह से इनकी सजा पर अमल को टाल रहे हैं। लेकिन याद रहे सजा रद्द नहीं कर रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका या फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होगी तो डेथ वारंट पर अमल नहीं किया जा सकेगा।

फिलहाल चारों दोषियों की कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की फाइलें अलग-अलग जगह हैं। मुकेश और विनय की सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी। वो भी दो दिन में सारी मेजों से होती हुई राष्ट्रपति के हाथों खारिज हो गई। इस बीच मुकेश ने अपने खिलाफ डेथ वारंट को भी टालने की अर्जी ट्रायल कोर्ट में लगाई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली सरकार भी इनको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की छूट देने को तैयार है तो फिर नई तारीख देनी ही पड़ेगी। फिर नई तारीख दी गई। कोर्ट ने कहा कि अब बचे दोषी क्यूरेटिव और दया याचिका लगाएंगे ही।

दूसरी ओर बचे दो और दोषी अक्षय और पवन गुप्ता, इन दोनों की सुप्रीम कोर्ट से सजा-ए-मौत की पुष्टि वाले आदेश पर पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है। अब ये दोनों कई तरह के हथकंडों के जरिए पहले तो सुधारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने में ही हर संभव देरी करेंगे। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकेश की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सख्त लहजे में पूछा भी कि जब 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आपकी रिट एसएलपी खारिज कर दी थी तो ढाई साल तक आप हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे। इस दौरान आपने रिव्यू और

तारीख पर तारीख



जेल के नियम तोड़े

जेल में बंद कैदियों को जेल के नियमों का पालन करना होता है, और पालन नहीं करने वालों को सजा भी दी जाती है। इन चारों आरोपियों ने तो जेल में भी सजा पाई, पिछले 7 सालों में इन सभी ने नियम तोड़े लेकिन सबसे कम नियम अक्षय ने तोड़े। उसे सिर्फ एक बार नियम तोड़ने पर सजा हुई थी। जबकि मुकेश को 3 बार, पवन को 8 बार और विनय ने जेल के नियमों का उल्लंघन करने पर 11 बार सजा मिली है। भारत में ये पहली बार होगा कि 4 कैदियों को एकसाथ फांसी दी जा रही हो। इन सभी को जेल में अलग-अलग सेल में रखा गया है और सीसीटीवी के जरिए इनकी मॉनीटरिंग की जा रही है। इनके व्यवहार पर भी करीब से ध्यान दिया जा रहा है। पता चला है कि डेथ वारंट जारी होने के बाद चारों दोषी काफी टेंशन में हैं। और इनमें से विनय सबसे ज्यादा परेशान है। उसके चेहरे पर डर देखा जा सकता है। वहीं उसका व्यवहार भी बदल रहा है। अब उसे जरा सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। हालांकि जेल अधिकारी व कर्मचारी बातचीत करके उसे सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 1 फरवरी तक सामान्य रहे इसके लिए विशेषज्ञों से उसकी काउंसिलिंग भी कराई जा सकती है। 3 साल पहले विनय ने भी राम सिंह की तरह ही जेल में आत्महत्या की कोशिश की थी।

क्यूरेटिव क्यों दाखिल नहीं की।

जिनकी दया याचिका लग चुकी है वो तो आखिरी संवैधानिक विकल्प के मोड़ पर खड़े हैं। लेकिन मुकेश और विनय की क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद अब अक्षय और पवन के पास क्यूरेटिव लगाने का विकल्प है। क्यूरेटिव खारिज होने के बाद दया याचिका लगाने और उसके खारिज होने की स्थिति में भी एक बार फिर अदालत में चुनौती देने का अंतिम विकल्प है। यानी दया याचिका खारिज होने की हालत में भी डेथ वारंट को चुनौती देने का विकल्प भी है।

अब देखिए! पवन ने सजा पर अमल में देरी के लिए एक और हथकंडा अपनाया। यानी क्यूरेटिव से पहले अपराध के समय अपने नाबालिग होने की दलील पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी को सुनवाई के बाद

इसे खारिज कर दिया।

ये तो विकल्प हैं। कानूनी और संवैधानिक लेकिन चूंकि हमारा संविधान और कानून दोनों वकीलों के लिए स्वर्ग हैं लिहाजा हथकंडे भी बहुत हैं फांसी टालने के। दोषियों के वकीलों का कहना है कि हमारे कानूनी तरकश में फिलहाल इतने तीर तो हैं कि दो साल तक हम फांसी टालने का माददा रखते हैं। जब तक ये हथकंडे चलेंगे कोई अदालत इनको फांसी तो नहीं दे सकती। अब एक ओर दोषियों के वकील एपी सिंह के दावे हैं दूसरी ओर संविधानिक और कानूनी छूट के बीच सहमे खड़े कानून और संविधान तीसरी ओर इंसाफ की आस में सूनी आंखों से न्याय की अंधी देवी को टकटकी लगाए निहारती देश की जनता और निर्भया के माता-पिता। सूनी पथराई आंखें उन आंखों को देख रही हैं जिन पर काली पट्टी भी बंधी है।

● अवस ब्यूरो

छत्तीसगढ़ में एक ओर जहां माओवादी अपने आखिरी बड़े किले को संजोए रखने के लिए हिडमा जैसे खतरनाक नक्सली लड़ाकों को सुरक्षबलों के खिलाफ मिलिट्री हमलों और अन्य गतिविधियों की कमान सौंप रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के लिए नए लड़ाके नहीं मिलने के कारण प्रदेश में नक्सली कैडर की संख्या अब आधी से भी कम रह गई है। राज्य सरकार और पुलिस के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 13 जिलों में माओवादियों की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। आदिवासियों में घटती लोकप्रियता और स्थानीय युवाओं में माओवाद के खिलाफ बढ़ रही उदासीनता के कारण नक्सली लड़ाकों और उनके मिलिशिया कैडर की संख्याबल पिछले 5-7 सालों में आधी रह गई है।

मिली जानकारी के अनुसार माओवादी लड़ाकों की संख्या 6000 से घटकर अब करीब 3000 रह गई है। हालांकि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दूसरे घटक या विभाग जैसे किसान मोर्चा, मेडिकल सेवा दल जो सुरक्षबलों से सीधे मोर्चा नहीं लेते लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के साथ पारस्परिक और वैचारिक संबंध निरंतर बनाए रखते हैं, उनकी संख्या करीब 15 से 20 हजार आंकी जा रही है। आला सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार माओवादियों के गिरते कैडर संख्या का मुख्य कारण करीब 80 हजार सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के साथ-साथ उनके द्वारा की जा रही बहुआयामी माओवाद चरमपंथी विरोधी सक्रिय कार्यवाही और युवा आदिवासियों में नक्सली विचारधारा से मोहभंग होना।

प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि विगत 5-7 वर्षों में नक्सली लड़कों का संख्याबल आधा हो जाना ही स्थानीय जनता विशेषकर आदिवासियों में नक्सलियों के प्रति घटती लोकप्रियता का परिचायक है। उनका मानना है कि नक्सलियों की संख्या में गिरावट यदि इसी रफ्तार से जारी रही, तो उनकी संगठनात्मक और मिलिशिया क्षमता भी काफी कमजोर हो जाएगी और माओवादी गतिविधियां अपने अंतिम दौर की ओर अग्रसर होती दिखाई देंगी। बस्तर रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा कहते हैं 'नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे का पूर्वानुमान लगा पाना तो बहुत ही कठिन होगा। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 5-7 वर्षों में सशस्त्र नक्सली लड़ाकों और मिलिशिया संख्याबल अब करीब 50 प्रतिशत ही रह गया है।' सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में माओवाद का चरम काल जो 2010-2015 के बीच था अब समाप्त हो गया है और आने वाले समय में उनके गिरावट में और



माओवादी पड़े कमजोर

वरिष्ठ नक्सली नेताओं की मृत्यु, वैचारिक अभाव

देश में माओवादियों का आखिरी गढ़ माने-जाने वाले छत्तीसगढ़ में कम होती लोकप्रियता और ताकत का एक मुख्य कारण सीपीआई(एम) के कुछ बड़े नक्सली नेताओं की मौत के कारण आया वैचारिक खालीपन भी है। सुरक्षबलों का कहना है दिसंबर 2019 में हुई एक करोड़ से भी ज्यादा का वांछित इनामी नक्सली रमन्ना की मौत से पहले सुरक्षबलों द्वारा मुठभेड़ में विगत पांच वर्षों में कई बड़े माओवादी नेता या तो मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसकी वजह से कैडर में वैचारिक प्रचार-प्रसार को नेतृत्व देने के लिए रिसोर्स पर्सन का लगातार अभाव हो रहा है। इस बात की पुष्टि सिन्हा भी करते हैं। सिन्हा ने बताया कि स्थानीय नागरिकों का माओवादी विचारधारा से धीरे-धीरे पूरी तरह मोहभंग हो रहा है और वे अब उनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वे सुरक्षबलों और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ लेकर अपने विकास के नए कार्यक्रम तैयार करने में लगे हैं।

भी तेजी आएगी।

पुलिस विभाग द्वारा दिप्रिंट को दी गई

जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब माओवादी लड़ाकों की संख्या मात्र 3000 के करीब है। इन लड़ाकों में 1000-1200 सशस्त्र कैडर संख्या उन नक्सलियों की हैं जो सुरक्षबलों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ते हैं और 1800 से 2000 मिलिशिया सदस्य हैं। ये मिलिशिया सदस्य आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र लड़ाकों की जगह लेने को तैयार रहते हुए सुरक्षबलों के खिलाफ हमलों में उनकी पूरी मदद करते हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में सबसे अधिक 700 सशस्त्र एवं मिलिशिया नक्सली लड़ाके सुकमा जिले में सक्रिय हैं। करीब 600 बीजापुर जिले में, 600 नारायणपुर में और 200-250 लड़ाके दंतेवाड़ा जिले में सक्रिय हैं, अन्य जिले जहां नक्सली मिलिशिया और सशस्त्र लड़ाके सक्रिय हैं। उनमें बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, राजनांदगांव, कबीरधाम, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद एवं बलरामपुर प्रमुख हैं।

माओवादियों की अपने गढ़ में कम होती पकड़ का एक बड़ा सबूत जो अधिकारियों की बात की पुष्टि भी करता है, वह पिछले तीन वर्षों के दौरान नक्सली हमलों में आई भारी गिरावट है। सुरक्षबलों की भारी मात्रा में तैनाती और नक्सल विरोधी आक्रामक रुख से माओवादियों के गढ़ में शिकंजा निरंतर कसता जा रहा है। यही कारण है कि विगत तीन वर्षों में नक्सली हमलों में 44 प्रतिशत में भारी कमी आई है। वर्ष 2017 में 250 नक्सली हमलों के मुकाबले 2019 में 140 हमले हुए। वहीं दूसरी ओर इन तीन सालों में करीब 250 नक्सली सुरक्षबलों के हाथों मारे गए, 2500 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए और 1100 से अधिक माओवादियों ने सुरक्षबलों के सामने आत्मसमर्पण किया।

● रायपुर से टीपी सिंह

महाराष्ट्र में शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी नेताओं के बेतुके बयान राज्य की ठाकरे सरकार के लिए मुसीबत बन रहे हैं। पहले शिवसेना नेता, सांसद संजय राउत का देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला, हाजी मस्तान

से मुलाकात पर दिया विवादित बयान, फिर मुसलमानों के कहने पर ठाकरे सरकार में शामिल होने के कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद अब अशोक चव्हाण के ही नए बयान ने सरकार को

मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। अशोक चव्हाण के ताजा बयान से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार काफी नाराज हैं और इस बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा करने वाले हैं। चव्हाण ने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने सरकार में शामिल होने से पहले राज्य के नेताओं को निर्देश दिए थे कि वो शिवसेना से लिखित आश्वासन ले कि वो संविधान के दायरे में रहकर ही सरकार चलाएंगे।

28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे के शपथ लेते ही राज्य में ठाकरे सरकार का उदय हुआ। एक महीने बाद उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। सभी 43 मंत्रियों का मंत्रिमंडल राज्य की सेवा में जुटेगा ऐसी उम्मीद थी। लेकिन काम से ज्यादा बयानबाजी में इन नेताओं का ध्यान था। बयान की शुरुआत हुई शिवसेना सांसद संजय राउत से। संजय राउत ने पुणे के एक कार्यक्रम में अंडरवर्ल्ड के विषय में बात करते हुए गुंडों का सीधे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कनेक्शन जोड़ दिया। उन्होंने कहा 'अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला, हाजी मस्तान देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात किया करते थे। 60-70 के दशक में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद पर कौन बैठेगा ये भी अंडरवर्ल्ड तय करता था। और तो और जब ये डॉन मंत्रालय आते थे तो पूरा मंत्रालय खाली कराया जाता था।'

राउत के इस बयान ने कांग्रेस को काफी नाराज किया। कांग्रेस हाईकमान ने संजय राउत को रोकने के लिए खुद मुख्यमंत्री से कहा तो राज्य के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने सरकार से बाहर निकलने की धमकी तक दे दी। नितिन राउत ने कहा कि 'अगर हमारे नेताओं पर इसी तरह के बयान शिवसेना की तरफ से दिए गए तो हम सरकार से पीछे हटने में कतराएंगे नहीं।' दबाव के बाद संजय राउत ने अपने बयान पर माफ़ी मांगते हुए सफाई भी दी। राउत ने कहा 'करीम लाला पठान नेता थे और पठान नेता के तौर पर ही इंदिराजी से मिलते थे। मेरे इस बयान से किसी को

बिगड़े बोल से सरकार मुसीबत में



महाराष्ट्र की राजनीति ने देश को नई राह दिखाई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का श्रेय राज्य के अल्पसंख्यकों को जाता है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बीजेपी सत्ता में दोबारा वापस लौटे। यही वजह रही कि अल्पसंख्यकों ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की। इसके बाद बदलते सियासी माहौल में एनसीपी-शिवसेना-कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र की राजनीति में इस घटनाक्रम ने देश को एक राह दिखाई है। मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार ने पार्टी की अल्पसंख्यक इकाई की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि चुनाव परिणाम आने के कई दिन बाद भी जब बीजेपी और शिवसेना के बीच सरकार गठन के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई, तब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ आई और काफी विचार-विमर्श के बाद राज्य में सरकार बनाई। पवार ने खुलासा किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने उनसे कहा था कि यदि उनकी पार्टी शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी लेकिन बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता से दूर रखा जाना चाहिए। शिवसेना के साथ संभावित तालमेल के बारे में महाराष्ट्र के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों से भी सलाह ली गई थी। हमें अल्पसंख्यकों की ओर से कहा गया कि यदि आप शिवसेना का साथ लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी को दूर रखिए। इसीलिए अल्पसंख्यकों ने भी शिवसेना के साथ सरकार बनाने का स्वागत किया।

ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ।'

ये मामला शांत हुआ ही था कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने नदिड की एक जनसभा में कह दिया कि मुसलमानों की वजह से वो इस सरकार में शामिल हुए। राज्य का मुसलमान ये चाहता था कि बीजेपी को सरकार से बाहर रखे तभी हम इस सरकार में शामिल हुए। अशोक चव्हाण के इस बयान की कड़ी आलोचना हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा लेकिन अशोक चव्हाण ने बयान वापस नहीं लिया। उल्टा चव्हाण ने मीडिया पर ही गलत तरीके से बयान दिखाने का आरोप लगा दिया।

इस बयान से शिवसेना नाराज थी। शिवसेना ने अपनी नाराजगी कांग्रेस के प्रभारी नेताओं तक पहुंचाई। इसके बाद कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड्गे दिल्ली से मुंबई आए। मुंबई आकर सभी मंत्री, नेता और प्रवक्ताओं से जिम्मेदारी से बयान देने के निर्देश दिए। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद अशोक चव्हाण ने ही

एक और विवादित बयान दे दिया जिससे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। अशोक चव्हाण ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सरकार में शामिल होने से पहले राज्य के नेताओं को निर्देश दिए थे कि वो शिवसेना से लिखित आश्वासन लें कि वो संविधान के दायरे में रहकर ही सरकार चलाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सरकार से बाहर आने में देर नहीं करेंगे। अशोक चव्हाण के इस बयान से उद्धव ठाकरे, शरद पवार नाराज हैं। बताया जा रहा है कि इस विषय में ठाकरे और पवार सोनिया गांधी से बात करके अपनी आपत्ति जताने वाले हैं। एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अशोक चव्हाण के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार में रहकर इस तरह के बयान देना गलत है। सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम कर रही है। इस प्रकार के बयान देकर सरकार को नुकसान पहुंचाना गलत है।

● बिन्दु माथुर

राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का विकल्प तैयार करने में जुटे हैं। इसका कारण है राजे से इन दोनों के असहज रिश्ते। यदि संघ की बात करें तो माना जाता है कि वह राजे के पहले कार्यकाल (2003-08) से ही उनके तौर-तरीकों से नाखुश रहा है। वहीं, राजे का पिछला पूरा कार्यकाल (2013-18) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से तनातनी के बीच ही बीता। तब शायद ही ऐसी कोई छमाही गुजरी जब सियासी गलियारों में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की चर्चा ने जोर न पकड़ा हो। लेकिन विधायकों पर उनकी जबरदस्त पकड़ के चलते ऐसा नहीं किया जा सका। लेकिन 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद वसुंधरा राजे को कमजोर करने में पार्टी हाईकमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस कवायद में उसे संघ का भी सहयोग मिलना बताया जाता है। इसकी शुरुआत वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर की गई। जानकारों ने इसे उन्हें राजस्थान की राजनीति से दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा।

अब राजस्थान में जिन नेताओं को राजे के समानांतर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उनमें जयपुर के पूर्व राजघराने से आने वाली सांसद दिया कुमारी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इस बारे में राजस्थान भाजपा के एक पदाधिकारी कहते हैं, 'पूर्व मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत के बाद से राजस्थान में राजपूत मुख्यमंत्री की सहज स्वीकार्यता आज भी महसूस की जा सकती है। खुद राजे भी मराठा राजघराने से आने के बावजूद खुद को राजपूत की बेटि बताकर ही यहां स्थापित हो पाई थीं।'

प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले कुछ जानकार केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे कद्दावर राजपूत नेताओं को भी राजे के विकल्प के तौर पर देखते हैं। लेकिन पूर्व राजघराने से ताल्लुक रखने और महिला होने की वजह से कइयों को दिया कुमारी उस जगह के लिए ज्यादा सटीक नजर आती हैं जो वसुंधरा राजे के बाद खाली हो सकती है। इसके अलावा दिया कुमारी अपने दिवंगत पिता ब्रिगेडियर भवानी सिंह की वजह से राष्ट्रवाद के उस खांचे में भी फिट बैठती हैं जो भाजपा और आरएसएस का पसंदीदा मुद्दा होने के साथ आम लोगों को भी खासा प्रभावित करता है। गौरतलब है कि 1971 के युद्ध में सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने (पश्चिमी) पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। ब्रिगेडियर भवानी सिंह के इस योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे



वसुंधरा का विकल्प

दिया कुमारी का प्रभाव बढ़ा है

दिया कुमारी के राजसमंद से सांसद बनने का एक फायदा तो यही है कि जयपुर और सवाई माधोपुर जैसे मध्य और पूर्वी जिलों के बाद उनका प्रभाव दक्षिण राजस्थान में भी फैल गया है। लेकिन इसका एक और पहलू है जिसके तार इतिहास से जुड़ते हैं। दरअसल राजसमंद मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा है जहां जयपुर राजघराने के प्रति नाराजगी का भाव महसूस किया जाता रहा है। इसकी वजह यह है कि हल्दीघाटी के युद्ध (1576) में जयपुर के राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। ऐसे में दिया कुमारी को मेवाड़ में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का बड़ा मौका मिला है। यह बात उनके राजनीतिक कैरियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ (उदयपुर संभाग) निर्णायक भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि प्रदेश में उसी पार्टी को सत्ता मिलती है जो मेवाड़ में दमदार प्रदर्शन कर पाने में सफल रहती है। इस सबके अलावा जो एक और बात दिया कुमारी को आरएसएस और भाजपा की पहली पसंद बना सकती है वह है उनका कछवाहा राजवंश से ताल्लुक रखना। मान्यता है कि कछवाहा भगवान राम के बेटे कुश के वंशज हैं। जयपुर राजघराने ने बीते साल अगस्त में सार्वजनिक रूप से यह दावा तब किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान राम के वंशजों की जानकारी मांगी थी। अपनी बात के पक्ष में जयपुर राजघराने ने बकायदा अपनी वंशावली समेत कुछ अन्य सबूत और दस्तावेज उसे उपलब्ध करवाए थे।

बड़े वीरता सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया था।

बीते कुछ समय से आरएसएस के कई कार्यक्रमों में भी दिया कुमारी की सक्रिय मौजूदगी दर्ज की गई है। हाल ही में उन्होंने जयपुर राजमहल में एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया था जिसमें राजस्थान भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर और अध्यक्ष सतीश पूनिया जैसे बड़े नेताओं समेत संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम भी मौजूद थे। आमतौर पर क्षेत्रीय प्रचारकों को भाजपा और संघ के बीच समन्वयक के तौर पर देखा जाता है। राजे के प्रभुत्व के समय इस तरह के पदों को या तो समाप्त कर दिया गया था या फिर ये प्रभावहीन हो गए थे।

प्रदेश भाजपा से जुड़े सूत्रों की मानें तो पिछले लोकसभा चुनाव में दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दिलवाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका रही थी। जबकि 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी का टिकट कट गया था। तब वे सवाई माधोपुर से विधायक थीं और उनका कार्यकाल भी संतोषजनक माना गया था। कहा जाता है कि ऐसा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इशारे पर हुआ था। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के बीच असहज रिश्तों की शुरुआत 2016 से मानी जाती है। तब राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें 'बेटी बचाओ' मिशन की ब्रांड एंबेसेडर बनाया था। जानकारों के अनुसार यहीं से तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ और राजे के भी रिश्तों में तलखी आ गई थी।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

ब सपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने फॉर्मूले ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित के गठजोड़ पर संगठन को दोबारा से मजबूत करने के प्रयास में जुट गई हैं। हाल ही में उन्होंने यूपी के अंबेडकर नगर से युवा सांसद रितेश पांडे को लोकसभा का नेता बनाया।

38 वर्षीय रितेश पार्टी का नया ब्राह्मण चेहरा हैं। पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा के साथ-साथ रितेश को अहम पद देकर मायावती ने इस बात का इशारा कर दिया है कि यूपी में ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने का बसपा पूरा प्रयास करेगी। पार्टी सूत्रों की मानें तो आने वाले समय में ब्राह्मणों को संगठन में भी अहम स्थान मिलने वाला है।

मायावती ने बीते दिनों लोकसभा में पार्टी के नेता दानिश अली को हटाकर अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे को जिम्मेदारी सौंपी। वहीं बिजनौर के सांसद मलूक नागर को उपनेता बनाया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली, विधानसभा में बीएसपी के नेता लालजी वर्मा व विधान परिषद में बीएसपी नेता दिनेश चंद्रा अपने पद पर बने रहेंगे। इस बदलाव के पीछे का कारण बताते हुए मायावती ने ट्वीट किया, 'सामाजिक सामंजस्य बनाने के मद्देनजर लोकसभा में पार्टी के नेता व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी एक ही समुदाय के होने के नाते ये परिवर्तन किया गया।'

2019 लोकसभा चुनाव व 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा के खराब प्रदर्शन के बाद मायावती ने पार्टी में जोन व मंडल के बजाए सेक्टर व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था। इसके अनुसार यूपी को चार सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में संगठन को दोबारा से मजबूत बनाने के लिए बीएसपी कई नए चेहरों को भी जिम्मेदारी दे सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 35 से 45 साल के युवाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनमें ब्राह्मणों को तवज्जो मिल सकती है। 38 वर्षीय युवा रितेश को दूसरे वरिष्ठ नेताओं के बदले लोकसभा में नेता बनाना शायद उसी ओर बढ़ती एक पहल है।

बीएसपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि रितेश पांडे पर आलाकमान को काफी भरोसा है और आने वाले वक्त में बसपा की सियासत में उनकी भूमिका और भी अहम होने वाली है। रितेश ने लंदन से इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। अंबेडकर नगर में सियासी तौर पर उनके परिवार का बड़ा कद है। उनके पिता राकेश पांडे खुद बीएसपी से सांसद रह चुके हैं। रितेश 2017 में बीएसपी के ही टिकट पर विधायक बने फिर 2019 में सांसद बन गए। सांसद बनने के 8 महीने के भीतर ही वह पार्टी के लोकसभा नेता भी हो गए हैं। उन्हें पार्टी के नए 'ब्राह्मण फेस' के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी है। 2022 चुनाव में भी उनका रोल अहम रह सकता है।



'ब्राह्मण-मुस्लिम-दलित' समीकरण

प्रियंका व चंद्रशेखर की एक्टिवनेस से बसपा सतर्क

यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव हैं वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने भी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में मायावती के लिए चुनौती अपने संगठन के अहम नेताओं को अपने साथ जोड़े रखने की है। इसी के मद्देनजर पार्टी काइड में इस बात का संदेश दे दिया गया है कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीते लोकसभा चुनाव व हाल ही में हुए 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बसपा 2022 को करो या मरो की तरह देख रही है। इसी कारण मायावती दोबारा से संगठन को मजबूत करने में जुट गई हैं।

पार्टी से जुड़े एक नेता का कहना है कि जिस तरह से योगी सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप लग रहे हैं ऐसे में बसपा को ब्राह्मणों को अपनी ओर आकर्षित कर उनको संगठन में तवज्जो देनी चाहिए। पूर्वी यूपी की राजनीति में ब्राह्मण व ठाकुर में सियासी जंग अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे में बसपा को मौजूदा हालातों में इस पर फोकस करने पर सोच रही है। दूसरे दलों के भी जो ब्राह्मण नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं उनको भी बसपा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अपने संगठन के दूसरे ब्राह्मण नेताओं को भी अहम रोल दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती के भतीजे आकाश कुमार काफी चर्चा में रहे। उन्हें पार्टी का स्टार कैंपेनर भी बनाया गया लेकिन चुनाव के बाद से वे पदों के आगे इतना सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। यहां तक की मायावती के जन्मदिन के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वे नहीं दिखे। पार्टी सूत्रों की मानें तो वे बीएसपी की स्ट्रेटेजी टीम का अभी भी हिस्सा हैं और 2022 चुनाव के आसपास उन्हें पार्टी अहम जिम्मेदारी दे सकती है।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही नहीं हुई है, लेकिन सियासी गणित बैठाना शुरू हो गया है। राज्य में नई संभावनाएं और नए गणित तलाशे जा रहे हैं। बिहार में आरजेडी के अंदर सब-कुछ सामान्य नहीं चल रहा। तेजस्वी के पार्टी की कमान संभालने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी और अब्दुल बारी जैसे नेता खुद को सहज नहीं पा रहे हैं। यह सब अभी तक इस उम्मीद में थे कि उन लोगों के 'पुराने दिन' लौट सकते हैं, क्योंकि एक वक्त यह 'तिकड़ी' लालू प्रसाद यादव की सबसे भरोसेमंद हुआ करती थी।

अब यह 'तिकड़ी' किसी निर्णायक रास्ते की तरफ बढ़ती दिख रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तेजस्वी यादव से पार्टी पर जितनी मजबूत पकड़ की उम्मीद की जा रही थी, वह दिख नहीं पाई। इसी वजह से पार्टी के अंदर बिखराव की स्थिति पैदा हुई है। इन सबके मद्देनजर राज्य में जो सियासी समीकरण बन रहा है, वह खासा दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में अगर बीजेपी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा तो बिहार में बहुत कुछ 'नया' देखने को मिल सकता है। एक समीकरण यह है कि आरजेडी में तेजस्वी से असंतुष्ट सभी 'बिग बॉसेज' एकजुट होकर अपने को 'असली आरजेडी' करार दे सकते हैं।

उधर, नीतीश कुमार भी बीजेपी की जगह इसी 'असली आरजेडी' से गठबंधन कर सकते हैं। बिहार के सियासी गलियारों में इतना तय माना जा रहा है कि अगर दिल्ली में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया तो फिर बिहार में नीतीश कुमार को उसकी कोई खास जरूरत नहीं रह जाएगी। लालू की 'पुरानी टीम' उनके लिए राज्य में बीजेपी से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर नीतीश के साथ आरजेडी के असंतुष्ट नेताओं का समीकरण नहीं बैठ पाया तो यह भी हो सकता है कि असंतुष्टों का यह धड़ा तेजस्वी को अलग रखते हुए गैर एनडीए गठबंधन तैयार करे, जिसमें कांग्रेस को शामिल करने की भी कोशिश होगी। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की छाया से बाहर आने की कोशिश कर ही रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी से विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अब पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का नाम मुख्यमंत्री के लिए उछाला है। ऐसे में दूसरे सहयोगी दल

नया गणित



हर पार्टी के पास अपना चेहरा

आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव आलोक मेहता भावी मुख्यमंत्री के मसले पर कुछ भी स्पष्ट कहने से बचते दिखे। उन्होंने कहा, 'हम लोग साथ बैठेंगे और इस मसले पर बातचीत करेंगे। हालांकि, आरजेडी का स्टैंड क्लियर है कि तेजस्वी ही हमारे आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम फेस होंगे। हालांकि 'हम' ने मीरा कुमार को लेकर अपनी स्थिति पूरी तरह नहीं साफ की। 'हम' के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, 'हर दल में अपना सीएम फेस है। यहां तक कि हमारी पार्टी में भी एक चेहरा है। हालांकि आखिरी फैसला कॉर्डिनेशन कमिटी मीटिंग में लिया जाएगा।' इधर, राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी के प्रवक्ता फैजल इमाम मलिक ने भी हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में सबसे योग्य चेहरा (उपेंद्र कुशवाहा) है।

जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी दबी जुबान में सीएम फेस के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ऐसे में आरजेडी के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। आरजेडी की तरफ से पहले तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए बढ़ाया जा चुका है। आरजेडी अब आपस में बैठकर इस मसले पर बातचीत की बात कह रही है। वैसे पार्टी ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। ऐसे में कांग्रेस के ताजा बयान

और अन्य दलों की पेशकश ने आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में चेहरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को बिहार में बड़ा चेहरा बताया। आरजेडी ने कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताया है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, 'कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास सीएम फेस नहीं है। मैं उन लोगों से साफ बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी नहीं है और मीरा कुमार से बेहतर सीएम फेस कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उनकी काबिलियत का मुकाबला कर सकता है।'

कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने भी प्रेमचंद्र मिश्रा के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'उन्होंने (प्रेमचंद्र) कुछ भी गलत नहीं कहा। हालांकि आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान लेगा।' कांग्रेस का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब जीतनराम मांझी पहले ही सत्ता बंटवारे को लेकर फॉर्मूला दे चुके हैं। मांझी का कहना है कि महागठबंधन की संभावित सरकार बनने पर एक सीएम और दो डिप्टी सीएम होना चाहिए। इनमें से एक दलित, एक बैकवर्ड और एक अल्पसंख्यक समुदाय का हो। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा कहते हैं कि कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास सीएम फेस नहीं है। मैं उन लोगों से साफ बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी नहीं है और मीरा कुमार से बेहतर सीएम फेस कोई नहीं है। कोई भी उनकी काबिलियत का मुकाबला नहीं कर सकता है।

बीते लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल अपने शीर्ष नेता लालू यादव के बगैर उतरी और उसका नतीजा पूरे बिहार ने देखा। तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी ने राज्य में अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। चुनाव परिणाम आने के बाद आरजेडी के अंदर ही तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर विरोध के सुर तेज होने लगे। इसकी बानगी विधानसभा चुनाव से पहले ही फिर से दिखने लगी है। आरजेडी के सबसे प्रमुख नेता जहां इन दिनों पारिवारिक कलह को लेकर परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में आंतरिक कलह भी चरम पर है। पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं में वर्चस्व और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की लड़ाई शुरू हो गई है।

● विनोद बक्सरी

संयुक्त अरब अमीरात यूएई की कुछ कंपनियों कई भारतीयों को टूरिस्ट वीजा पर ले जाती हैं और फिर नौकरी के नाम पर इन लोगों का खूब शोषण किया जाता है। पुलिस और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोगों को फंसाने के लिए टूरिस्ट वीजा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वर्क परमिट के मुकाबले उसे हासिल करना बहुत आसान होता है। इसमें समय भी कम लगता है और पैसे भी ज्यादा नहीं खर्च करने पड़ते। यूएई पहुंच कर भारतीय कामगारों को समझ आता है कि वह किस जाल में फंस गए हैं। वे पुलिस अधिकारियों के पास जाकर अपने शोषण की शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर पुलिस को पता चल जाएगा कि वे गैरकानूनी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।

यह सब कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि टूरिस्ट वीजा का ब्यौरा भारत और यूएई के माइग्रेशन या रोजगार रिकॉर्ड्स में नहीं होता। लेकिन कामगारों, पुलिस और वकीलों का कहना है कि यूएई में यह समस्या लगातार बढ़ रही है। इस खाड़ी देश में लगभग तीस लाख भारतीय कामगार काम करते हैं, जिन्हें झटपट बड़ी निर्माण परियोजना पर काम करने के लिए रखा जाता है। तेलंगाना में इमिग्रेंट्स वेलफेयर फोरम के अध्यक्ष भीम रेड्डी ने बताया, 'एंग्लोयर्स और रिक्रूटर्स ने मिलकर ये नया टूरिस्ट वीजा रूट निकाला है।' रेड्डी की संस्था का अनुमान है कि पिछले साल जुलाई से उनके राज्य के लगभग दस हजार लोगों को यूएई में काम मिला और वे टूरिस्ट वीजा पर वहां गए। करीब 3.06 लाख लोग 2015 में सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में कुल लगभग 27 लाख 30 हजार भारतीय काम करते हैं, जिनसे देश को करोड़ों डॉलर प्राप्त होता है।

अक्टूबर में होने वाली दुबई एक्सपो 2020 वर्ल्ड फेयर जैसे आयोजनों से पहले यूईए में थोड़े समय के लिए बुलाए जाने वाले कामगारों की संख्या बढ़ जाती है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के आयोजन घपला करने वालों के लिए बड़े मौके साबित होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय कामगार रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों में दशकों से जाते रहे हैं। लेकिन उन्हें टूरिस्ट वीजा पर बुलाया जाना एक नया चलन है।

दुबई की अदालतों में प्रवासी मजदूरों के केसों पर काम करने वाली अनुराधा



जाल में फंसते भारतीय

70 लाख भारतीय मध्यपूर्व में हैं

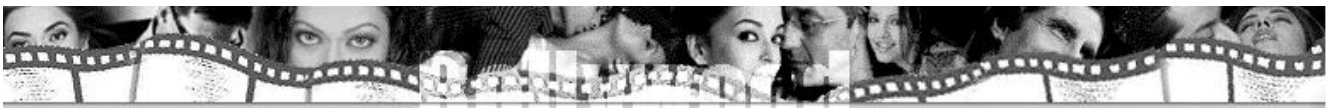
सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन में 70 लाख से भी अधिक भारतीय रहते हैं। यह संख्या पूरी दुनिया में रह रहे एनआरआई की 60 फीसदी है। करीब 3.06 लाख लोग 2015 में सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में लगभग 27 लाख 30 हजार भारतीय काम करते हैं, जिनसे देश को करोड़ों डॉलर प्राप्त होता है। भारत से यूएई जाने वालों की संख्या 2015 में 2.25 लाख रही। यूएई में इस वक्त करीब 17 लाख भारतीय रह रहे हैं। देश में स्थानीय निवासियों के बाद भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या दूसरे स्थान पर है। भारत से इस साल करीब 60 हजार लोग कतर पहुंचे। कतर में करीब 6,50,000 भारतीय रहते हैं, जो कि वहां की कुल आबादी का करीब एक-तिहाई है। ओमान पहुंचने वालों की संख्या 85 हजार रही। आकड़ों के मुताबिक, करीब छह लाख भारतीय ओमान में काम कर रहे हैं और इनमें से 80 फीसदी दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं।

वोबिलीसेट्टी कहती हैं कि उन्होंने 2018 से अब तक कम से कम 270 ऐसे कामगारों की मदद की है जिन्हें टूरिस्ट वीजा पर लाया गया और पूरा वेतन नहीं दिया गया। वर्क परमिट जहां दूतावास जारी करते हैं और इससे पहले पूरी कागजी कार्यवाही होती है, वहीं टूरिस्ट वीजा होटल और एयरलाइन बेचती हैं जिसके चलते कामगारों के पास कोई अधिकार नहीं होते और उन्हें नौकरी पर रखने वाली कंपनी या लोग सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं। वोबिलीसेट्टी कहती हैं, 'एयरपोर्ट पर ही उनके (कामगारों के) पासपोर्ट एजेंट ले लेता है और महीनों तक उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन वे कई महीनों तक बिना वेतन काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर सताता है कि कहीं उनके गैरकानूनी तरीके से काम करने की बात पुलिस तक ना पहुंच जाए।'

सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2019 के बीच विदेशों में नौकरी संबंधी भारतीय कामगारों की शिकायतें तीन गुना बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई हैं। खाड़ी देशों में सफाई कर्मचारी

से लेकर भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से भारतीयों का कहना है कि उन्होंने अपने शोषण और बकाया वेतन को लेकर सरकार और सामाजिक संस्थाओं से बात की है। संयुक्त राष्ट्र के 2017 तक के आंकड़े बताते हैं कि यूएई में रजिस्टर्ड 80 लाख प्रवासी कामगारों में एक तिहाई से ज्यादा भारतीय हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यूएई जाने वाले भारतीय कामगारों की संख्या में अब कमी आ रही है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसकी वजह एक तरफ आर्थिक तंगी है तो दूसरी तरफ टूरिस्ट वीजा का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। दुबई में भारतीय कंसुल जनरल का कहना है कि जो लोग वैध तरीके से आते हैं, उनकी पूरी तरह सुरक्षा की जाती है क्योंकि उन्हें नौकरी देने वाली कंपनी का पूरा ब्यौरा मौजूद होता है। लेकिन कुछ छोटी कंपनियां पैसा बचाने के चक्कर में टूरिस्ट वीजा पर लोगों को बुला लेती हैं। और फिर इनमें से बहुत से लोग शोषण का शिकार बनते हैं।

● अक्स ब्यूरो



दशक की सबसे कमाऊ जनवरी 2020, लेकिन सिर्फ एक फिल्म सफल

2020 का पहला महीना यानी जनवरी बीत चुका है। कमाई के लिए लिहाज से यह हिंदी बॉक्स ऑफिस के लिए एक दशक की सबसे अच्छी जनवरी रही। लेकिन सफल फिल्मों की संख्या ने निराश किया। पिछले साल की तरह ही इस बार भी जनवरी में सिर्फ एक फिल्म तान्हाजी : द अनसंग वॉरियर ही सफलता हासिल कर पाई। जबकि 30 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुईं। 31 जनवरी तक सभी फिल्मों का कुल कलेक्शन तकरीबन 386 करोड़ रुपए रहा। खास बात यह है कि इसमें 240.64 करोड़ रुपए सिर्फ अजय देवगन स्टारर तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर ने की। जबकि बाकी फिल्मों ने साझा रूप से करीब 145.36 करोड़ रुपए ही कमाए।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, बैतूल

January Republic Day

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति हरदा

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति टिबरकिया, जिला-हरदा

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति कुरावर, जिला-राजगढ़

सचिव ● भार साधक अधिकारी

26 JANUARY REPUBLIC DAY

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, टिबरनी, जिला-हरदा

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, इटारसी, जिला-होशंगाबाद

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया, जिला-होशंगाबाद

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति बानापुरा, जिला-होशंगाबाद

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति बनखेडी, जिला-होशंगाबाद

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति बाबई, जिला-होशंगाबाद

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, होशंगाबाद

January Republic Day

सचिव ● भार साधक अधिकारी

मो दी सरकार ने आने के बाद देश से वीआईपी कल्चर को खत्म किया। उससे पहले हर सड़क पर कुछ लालबत्ती वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आ जाती थीं। वैसे इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि लालबत्ती का रौब कितना होता था, लेकिन अब वो रौब नहीं रहा। खैर, अभी भी आप सड़कों पर देखेंगे तो पता चलेगा कि कई छुटभैय्ये नेता भी अपने गाड़ी के आगे-पीछे एक-दो गाड़ियां लेकर चलते हैं। भले ही वह उनकी जरूरत ना हो, लेकिन कम से कम उनका रौब तो बनाए रखने में मदद करते ही हैं। अब सोचिए जरा, अगर किसी से कहा जाए कि ये सब छोड़कर सामान्य व्यक्ति की तरह रहो... बेशक ऐसा मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि जिस वीआईपी कल्चर की आदत हो चुकी हो, उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। आज भी भारत में ऐसे बहुत से रजवाड़े हैं, जो अपने नाम में कुंवर लगाना पसंद करते हैं, राजाओं वाला फील जो आता है। आजादी के बाद जब रजवाड़ों का विलय हो रहा था, तो इसका विरोध भी खूब हुआ था, लेकिन ऐसे लोगों के लिए प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन ने एक नया उदाहरण स्थापित किया है। हैरी और मेघन ने फैसला किया है कि वह रॉयल फैमिली की सदस्यता छोड़ रहे हैं।

इस फैसले पर वह यूं ही नहीं पहुंचे, बल्कि इसके लिए महारानी के साथ उन्होंने करीब हफ्ते भर तक चर्चा की है। यानी अब उन्हें हिज रॉयल हाइनेस और हर रॉयल हाइनेस कहकर नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि अब वह भी सामान्य लोग होंगे। यह सभी बदलाव इस साल फरवरी-मार्च से लागू होंगे। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इससे कितना फर्क पड़ता है?

प्रिंस हैरी और मेघन ने मार्केल के रॉयल फैमिली की सदस्यता छोड़ने के बाद उन्हें बहुत सारे अधिकार नहीं मिल पाएंगे। वह हिज रॉयल हाइनेस और हर रॉयल हाइनेस की उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वह सार्वजनिक कोष का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। यानी उन्हें शाही कर्तव्यों के लिए सार्वजनिक निधि नहीं मिलेगी। हैरी और मेघन अभी तक ड्यूक ऑफ ससेक्स हैरी और डचेस ऑफ ससेक्स मेघन के तौर पर जाने जाते थे, अब यह उपाधि नहीं रहेगी। दंपती के विंडसर कैसल स्थित घर की मरम्मत में करदाताओं के 24 लाख पाउंड खर्च हुए हैं, जिसे उन्हें वापस लौटाना होगा। अब वह किसी भी देश में महारानी एलिजाबेथ के प्रतिनिधि नहीं होंगे। अब एक सवाल ये उठता है कि जब रॉयल फैमिली का सदस्य होने के नाते इतने सारे फायदे और रुतबा मिल रहा था तो फिर उन्होंने टाइटल छोड़ा क्यों?

हैरी ने भले ही रॉयल फैमिली की सदस्यता छोड़ दी है, लेकिन वह राजकुमार और ब्रिटिश



रजवाड़ों के लिए सबक

तो फिर क्यों छोड़ा रॉयल टाइटल?

प्रिंस हैरी शाही परिवार का हिस्सा रहते हुए खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं करते थे। इस बात का इशारा खुद महारानी ने ही किया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि प्रिंस हैरी और मेघन मार्केल के हर कदम पर पिछले दो साल से जिस तरह नजर रखी जा रही है, उसके परिणामस्वरूप उनके सामने आने वाली चुनौतियों को वह समझती हैं और एक अधिक स्वतंत्र जीवन जीने की उनकी इच्छा का समर्थन करती हैं। बता दें कि रॉयल फैमिली का होने की वजह से उनके हर कदम पर मीडिया नजर रखती थी, जिसे वह काफी डिस्टर्ब महसूस करते थे। यहां आपको बता दें कि प्रिंस हैरी ने कुछ दिन पहले भी इंस्टाग्राम के जरिए स्वतंत्र रूप से रहने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि 'हम लोग शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य की हैसियत से हटना चाहते हैं और अपने आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही महारानी को हमारा समर्थन जारी रहेगा।'

शाही गद्दी के छठे वारिस बने रहेंगे। एक सवाल यह भी उठता है कि आगे वह अपना घर चलाने के लिए क्या करेंगे? कहां रहेंगे? बता दें कि वह ब्रिटेन में विंडसर महल में ही अपने पुराने घर में रहेंगे, जिसके रिनोवेशन में करीब 24 लाख पाउंड खर्च हुए थे, जिसे दंपति वापस भी करेगी। इसके अलावा प्रिंस हैरी आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी कर सकते हैं। वे दोनों पहले से ही एक चैरिटी भी चलाते हैं। वहीं मेघन मार्केल एक्ट्रेस थीं, तो वह दोबारा से एक्टिंग शुरू कर सकती हैं।

एक ओर प्रिंस हैरी और मेघन मार्केल हैं, जिन्होंने पलक झपकते ही अपनी रॉयल फैमिली की सदस्यता छोड़ दी और आम लोगों जैसे बन गए। वहीं दूसरी ओर भारत में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो सिर्फ इसलिए सत्ता का दावा करते हैं, क्योंकि उस पर उनके परिवार या खानदान का हक रहा है। बात भले ही कांग्रेस की हो, समाजवादी पार्टी की हो, आरजेडी की हो या अन्य कई पार्टियों की हो, सभी यही सोचती हैं कि पार्टी पर हमेशा से उनके परिवार का कब्जा रहा है तो आगे भी उन्हीं का कब्जा रहे। ऐसे लोगों के लिए हैरी और मेघन एक उदाहरण हैं, जो ये दिखाते हैं कि अगर रॉयल्टी से अलग होना चाहें, तो हुआ जा सकता है। हां अगर किसी को अपना वीआईपी दिखना या राजा-रजवाड़ों की तरह रहना पसंद हो, तो वह हैरी-मेघन जैसा अहम कदम कभी नहीं उठा सकता।

● अक्स ब्यूरो



कमल नाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

गुरुनानक देव जी प्रान्तीय ओलम्पिक खेल 2020



• विशिष्ट अतिथि •
पद्मश्री दीपिका कुमारी
ओलम्पियन तीरंदाज

“ जो वादा किया, निभाया।

मध्यप्रदेश सरकार की इस अभिनव पहल से प्रदेश में प्रान्तीय ओलंपिक खेलों के आयोजन द्वारा खिलाड़ियों को प्रतिभा प्रदर्शन का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। ”

जीतू पटवारी
मंत्री, खेल और युवा कल्याण
म.प्र. शासन



राज्य स्तरीय प्रान्तीय ओलम्पिक - 1 से 7 फरवरी 2020

स्थान- तात्या टोपे स्टेडियम, टी.टी. नगर, भोपाल

प्रदेश की युवा प्रतिभाओं के जोशीले प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं।

आयोजन में शामिल खेल

फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, बास्केटबॉल,
खो-खो, एथलेटिक्स, टेबल-टेनिस

खेल और युवा कल्याण विभाग, म.प्र. शासन

कुलचा के नाम से मशहूर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल अपनी लहराती हुई गेंदों से विरोधी बल्लेबाजों को अधिक देर टिकने नहीं देते हैं। लेकिन पिछले कुछ मैचों से ये दोनों एक साथ मैच में नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये सवाल फिर गर्मा रहा है कि विराट कोहली कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में एक साथ मौका क्यों नहीं दे रहे हैं।

2017 से लेकर 2019 तक टीम इंडिया को जिन दो गेंदबाजों ने जबरदस्त कामयाबी दिलाई। इन दो गेंदबाजों ने एक जैसी काबिलियत होने के बाद भी विश्व क्रिकेट के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को चौंकाया। इन दोनों गेंदबाजों में ऐसा शानदार तालमेल था कि इन्हें 'कुलचा' कहा जाने लगा। 'कुल' यानी कुलदीप यादव और 'चा' यानी युजवेंद्र चहल। ये जोड़ी एक के बाद एक कमाल



करती चली गई। यहां तक की 2019 विश्व कप से पहले ऐसी चर्चा भी जोरों पर थी कि इन दोनों गेंदबाजों की बदौलत ही भारतीय टीम विश्व कप पर कब्जा करने जा रही है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ लीग मैच में इन दोनों गेंदबाजों की पिटाई क्या हुई विराट कोहली का विश्वास डगमगा गया, जो विराट कोहली बार-बार एक बात कहते थे कि वो इन दोनों गेंदबाजों से

विकेट चाहते हैं। वो जानते हैं कि बीच-बीच में ये दोनों गेंदबाज किसी मैच में महंगे भी साबित होंगे लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं।

विराट कोहली के ये सारे बयान इस मैच के बाद सच्चाई से दूर होते चले गए। उन्होंने इस करिश्माई जोड़ी को तोड़ दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ उस मैच में युजवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 88 रन दिए थे। उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। कुलदीप यादव भी इस मैच में 10 ओवर में 72 रन देकर 1 विकेट ही ले पाए थे। इसका नतीजा ये हुआ था कि इंग्लैंड ने वो मैच 31 रनों से जीत लिया था। इसके बाद पूरे विश्व कप में विराट कोहली ने इन दोनों गेंदबाजों को एक साथ प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया। विराट भूल गए कि 1 जनवरी 2017 से लेकर इस मैच के पहले तक कुलदीप यादव ने 50 मैचों में 92 विकेट लिए थे।

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी
समिति रतलाम

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी
समिति, नीमच

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज
मंडी समिति,
जावरा, जिला- रतलाम

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी
समिति मंदसौर

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, सोनकच्छ, जिला-देवास

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
मनासा, जिला-नीमच

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज
मंडी समिति
दलौदा,
जिला-मंदसौर

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज
मंडी समिति
भोपाल



सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की
शुभकामनाओं सहित...



कृषि उपज
मंडी समिति
बैरसिया,
जिला-भोपाल

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज
मंडी समिति,
सीहोर



सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं
सहित...

कृषि उपज
मंडी समिति,
आष्टा जिला-सीहोर

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र
दिवस की
शुभकामनाओं सहित...



कृषि उपज मंडी समिति, नसरुल्लागंज, जिला- सीहोर

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की
शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज
मंडी समिति,
ओबेदुल्लागंज
जिला- रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की
शुभकामनाओं सहित...



कृषि उपज
मंडी समिति
रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की
शुभकामनाओं सहित...



कृषि उपज
मंडी समिति
बेगमगंज,
जिला- रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की
शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज
मंडी समिति,
बरेली
जिला- रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की
शुभकामनाओं सहित...



कृषि उपज
मंडी समिति,
गैरतगंज
जिला- रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज
मंडी समिति
उदयपुरा
जिला-रायसेन

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी
समिति...
विदिशा

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र
दिवस की
शुभकामनाओं
सहित...



कृषि उपज मंडी समिति
गंजबासौदा, जिला-विदिशा

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र
दिवस की
शुभकामनाओं
सहित...



कृषि उपज मंडी समिति, कुरवाई, जिला -विदिशा

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र
दिवस की
शुभकामनाओं
सहित...



कृषि उपज मंडी समिति
ब्यावरा, जिला-राजगढ़

सचिव ● भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी
समिति...
पचौर,
जिला - राजगढ़

सचिव ● भार साधक अधिकारी

मेरा एक मित्र है, वह आकंट कर्ज में डूबा हुआ है। पर उसका रहन-सहन! आप एक बार उसके यहां हो जाएं, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हर नई से नई चीज है उसके घर में। इसका कारण यह है कि वह आधुनिक अर्थशास्त्र का महान ज्ञाता है। दुनिया का बड़ा से बड़ा अर्थशास्त्री भी उसके सामने पानी भरता है। उसके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं। वह जो भी खरीदता है, क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर खरीदता है।

कर्ज चुकता करने के लिए भी और क्रेडिट कार्ड ले रखा है और सूद चुकाने के लिए भी एक और क्रेडिट कार्ड। मूल अदा करने में भले ही देर हो जाए, पर सूद चुकता करने में उससे कभी चूक नहीं होती। उसकी इसी साख से साहूकार बैंक भी उसके कायल हैं और उसे कर्ज देने में ज्यादा आनाकानी नहीं करते। कुछ जरूरतमंद बैंक तो उसे कर्ज देने उसके घर तक आ जाते हैं। और वह भी कभी नहीं चाहता है कि इस चक्र से निकला जाए। पर हां, अपने घर में अपने बीवी बच्चों को वह अपनी आर्थिक स्थिति की भनक तक नहीं लगने देता है। इस मामले में बहुत ही अच्छा गृहस्वामी है मेरा वह मित्र।

कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश का भी है। देश भी मंदी में आकंट डूबा है। पर आश्चर्य यह है कि यह सब अचानक कैसे हो गया! अभी, पिछले साल मई में जब चुनाव हुए थे तब तक तो देश की खराब आर्थिक स्थिति की कोई चर्चा ही नहीं थी। चुनाव हुए, लेकिन चुनावों में आर्थिक स्थिति को किसी ने भी मुद्दा ही नहीं बनाया, न सरकार ने और न ही विरोधियों ने। ये इतने सारे नेता हैं न, बताते रहे कि तुम हिंदू हो तो असली समस्या मुसलमान हैं और एकमात्र हल है राम मंदिर बनाना। और भाजपा की स्थिर पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही राम मंदिर बनवाने में सहायता कर सकती है।

अब जब मस्जिद-मंदिर समस्या उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझा ली गई है तो कुछ और तो होना चाहिए हिंदू-मुसलमान करने के लिए। वैसे तो गौरक्षा और गौमांस हैं, लव जिहाद है हिंदू-मुसलमान करने के लिए पर वे इतने असरदार

मंदी में 'फरारी' कार!



नहीं हो पा रहे हैं। ये साल भर एक छोटे स्तर पर यहां वहां चलते रहते हैं पर बड़े पैमाने पर हिंदू-मुसलमान करने के लिए एक बड़ा मुद्दा चाहिए। इसीलिए अब सीएए और एनआरसी का खेल शुरू कर दिया है हिंदुओं और मुसलमानों को हिंदू-मुसलमान खेल में उलझाने के लिए।

जब से सीएए और एनआरसी की बात शुरू हुई है सब जगह इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार चाहती भी यही है। लोग बाग बिजी रहें इस तरह की चीजों में। जब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, हिंदू-मुसलमान होता रहेगा। और जब तक हिंदू-मुसलमान होता रहेगा इस भाजपाई सरकार को लगता है कि वह बनी रहेगी। पर इस बार ये धरना-प्रदर्शन सरकार

की उम्मीद से अधिक ही हो गया है। लेकिन इसमें इस सरकार की शायद कोई गलती नहीं है। ये तो यह सब हमारे भले के लिए ही करती है। यह सरकार जानती है कि इस देश की अनपढ़, जाहिल और नासमझ जनता के सामने मंदी जैसी गूढ़ आर्थिक समस्याओं का जिक्र करना भैंस के सामने बीन बजाने जैसा है। सरकार जानती है कि सेटों की बीवियों के गहने बनवाओ, गहने तुड़वाओ के तरह ही जनता को हिंदू-मुसलमान

में व्यस्त रखना चाहिए। हमें तो इन नेताओं का शुकुगुजार होना चाहिए कि ये हमें देश की गंभीर समस्याओं में उलझाकर हमारा सुख-चैन नहीं छीनना चाहते हैं। देश की सारी समस्याओं का बोझ ये अपने कंधों पर ही उठाए रख रहे हैं।

पर अब तो देश में मंदी का होना जगजाहिर हो चुका है। सरकार इस मंदी से उबरने के लिए मुस्तैदी से उपाय कर रही है। एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रही है तो दूसरी ओर पैसा कमाने के लिए अपने नवरत्नों को बेचने के प्रबंध किए जा रहे हैं। कुछ की बोली लग रही है बाकी भी बिकने के लिए तैयार हैं।

ऐसा नहीं है कि सरकार हमें मंदी जैसी गंभीर समस्या से ही अलग रखना चाहती है। वह तो एक अच्छे गृहस्वामी की तरह से हमें अन्य सारी कठिनाइयों से भी दूर रखना चाहती है। वह नहीं चाहती है कि हमें बढ़ती बेरोजगारी का पता चले, और हमें दुख पहुंचे। या फिर हमें शिक्षा में हो रही गिरावट की

भनक लगे और हम अवसाद में चले जाएं। सरकार बस एक अच्छे अधिभावक की तरह यह चाहती है कि हम उसके द्वारा पकड़ाए गए खिलौने हिंदू-मुसलमान में उलझे रहें।

अरे! अपने मित्र की कथा सुनाते-सुनाते, पता नहीं मैं कहां से कहां पहुंच गया। अब आपको अधिक बोर न कर अपने मित्र की कहानी का अंत बता ही देता हूँ। उसके धंधे पर तो पहले ही बैंकों का कब्जा हो गया था, कल रात एक बैंक ने उसके मकान पर भी कब्जा कर लिया। मेरे मित्र को अपने बीवी-बच्चों के साथ किशतों में खरीदी गई फरारी कार में रात बितानी पड़ी। बेचारा!

● डॉ. द्रोण कुमार शर्मा

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित... **26**
JANUARY

कृषि उपज मंडी समिति, देवास

सचिव • भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, तराना, जिला-उज्जैन

सचिव • भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, पिपल्वा, जिला-मंडसौर

सचिव • भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन

सचिव • भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
बड़नगर, जिला-उज्जैन

सचिव • भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर, जिला-उज्जैन

सचिव • भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति,
खातेगांव, जिला-देवास

सचिव • भार साधक अधिकारी

26 JANUARY
INDIA
HAPPY REPUBLIC DAY

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...
26 JANUARY
INDIA

कृषि उपज मंडी समिति, शुजालपुर, जिला-शाजापुर

सचिव • भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति
आगर, जिला-शाजापुर

सचिव • भार साधक अधिकारी

गणतंत्र दिवस
की शुभकामनाओं सहित...

कृषि उपज मंडी समिति, सैलाना, जिला-रतलाम

सचिव • भार साधक अधिकारी



मध्यप्रदेश शासन



कमल नाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

कमल नाथ सरकार का एक वर्ष

तेज कदमों से तरक्की की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

“एक साल पहले आज ही के दिन हमने सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलते हुये उनके जीवन को बेहतर और समर्थ बनाने तथा प्रदेश के हर क्षेत्र के समेकित विकास का संकल्प लिया था। यह मात्र रस्मी संकल्प नहीं था, बल्कि असीमित संभावनाओं के धनी प्रदेश के विकास को वास्तविक अर्थों में संभव बनाने का और इस प्रदेश के प्रति मेरी भावनाओं से प्रेरित एक दृढ़ निश्चय था। मध्यप्रदेश विपुल संसाधनों का प्रदेश है और उसी अनुपात में मध्यप्रदेश का विकास हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में रणनीतिक योजनाएं बनाकर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनका परिणाम अब हर क्षेत्र में दिखने लगा है। आने वाला समय उम्मीदें पूरी करने वाला है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मध्यप्रदेश अपनी विकास यात्रा में पीछे मुड़कर नहीं देखेगा।”



एक वर्ष में 365 वचन पूर्ण

कृषि

- ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के अंतर्गत 20 लाख से अधिक किसानों के ऋण माफ।
- मण्डियों में एक साथ ई-अनुज्ञा ऑनलाइन प्रणाली।
- इंदिरा किसान ज्योति योजना में 10 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिये आधी दर पर बिजली उपलब्ध।
- किसान परिवार की कन्याओं के विवाह के लिए कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ। इसमें 51,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के लिए 2.5 एकड़ तक पात्रता।

बिजली

- इंदिरा किसान ज्योति योजना में अब आधी दर पर बिजली उपलब्ध। इससे लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित।
- इंदिरा गृह ज्योति योजना - घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर 100 रुपये प्रति माह में बिजली उपलब्ध।
- घरेलू उपभोक्ताओं तथा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति।
- बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिये 1912 कॉल सेंटर की सेवाएँ।

उच्च शिक्षा

- सभी शासकीय महाविद्यालयों को भूमि का स्वामित्व देकर अगले 30 वर्ष की विकास योजना तैयार करने का ‘भूमि सुरक्षा अभियान’।
- कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के सहयोग से अंग्रेजी भाषा का विशेष प्रशिक्षण प्रारंभ।
- IIT व IIM के उच्च श्रेणी के प्राध्यापक पहली बार नवाचार हेतु उच्च शिक्षा परिषद में शामिल।
- विदेश में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के अर्हकारी अंक और परिवार की आय सीमा को कम किया गया।
- पीएससी से घयनित 3148 प्राध्यापकों व अन्य की नियुक्ति में पहली बार पारदर्शिता से ऑनलाइन पदस्थापना का विकल्प।

आदिवासी समाज

- वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 8,683 दावों का निराकरण।
- आकांक्षा योजना में विद्यार्थियों को JEE, NEET, CLAT की प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर 14 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय।
- बालिकाओं की शिक्षा एवं साक्षरता वृद्धि के लिए 82 कन्या शिक्षा परिसर संचालित।
- मुख्यमंत्री मदद योजना में जन्म एवं मृत्यु के अवसर पर प्रति जन्म 50 किलोग्राम गेहूँ/चावल एवं प्रति मृत्यु पर 100 किलोग्राम अनाज गेहूँ/चावल का वितरण।
- आदिवासी समुदाय के देवस्थानों के संरक्षण के लिए आठान योजना।
- तेंदूपत्ता श्रमिकों की मजदूरी की दरों में वृद्धि। मजदूरी और बोनस का हो रहा है नकद मुगतान।

पिछड़ा वर्ग

- पिछड़ा वर्ग हेतु शासकीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू।
- पिछड़ा वर्ग के परंपरागत कुटीर, हस्तशिल्प, हाथकरघा के उत्पाद जीएसटी से मुक्त।

उद्योग

- निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक नीति में महत्वपूर्ण संशोधन। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिये नई एमएसएमई विकास नीति एवं स्टार्ट अप नीति 2019 लागू।
- पाँवरलूम, फार्मास्युटिकल एवं रेडिमेड गारमेंट के लिए विशेष पैकेज।
- तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मैनुफैक्चरिंग इन्ोवेशन फण्ड की स्थापना।
- निजी भूमि अर्जन के लिये लेण्ड पूलिंग पॉलिसी लागू की गई।
- मैनीफिस्ट मध्यप्रदेश-2019 का इन्दीर में सफल आयोजन।

युवा

- मध्यप्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को देना अनिवार्य।
- प्रदेश के आईटीआई, पॉलीटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ग्लोबल स्किल्स पार्क भोपाल कैंपस में प्रिंसीपल इंजीनियरिंग कोर्स में प्रशिक्षण।
- शहरी बेरोजगार युवाओं को 100 दिन के रोजगार के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वामिमान योजना।
- प्रतिभावान खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि एवं खेल संघों की अनुदान राशि में वृद्धि।
- खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम।
- खेल अकादमी एवं प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को चिकित्सा और दुर्घटना जीवन बीमा की सुविधा।
- स्वरोजगार मूलक योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए पृथक से लक्ष्य।

महिला सशक्तिकरण

- लाइली लक्ष्मी योजना में 3 लाख 20 हजार 289 नई बालिकाओं का पंजीयन।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की अनुदान राशि 28 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये।
- बुढ़ावस्था और विधवा पेंशन राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह।
- प्रदेश की 202 आशा कार्यकर्ताओं को उसी ब्लॉक में एनएएम के पद पर नियुक्ति।
- प्रदेश की 9411 महिलाओं को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण।
- एकीकृत महिला हेल्पलाइन 181 की सेवाएँ प्रारंभ।
- कन्या शैक्षणिक संस्थानों तथा महिला कामकाजी क्षेत्रों को चिन्हित कर वहाँ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था।

उम्मीदें रंग लाईं, तरक्की मुस्कुराईं